सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

03 फरवरी, 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना ।

अष्टादश विधान सभा — मंगलवार, तिथि 03 फरवरी, 2026 ई॰
द्वितीय सत्र — 14 माघ, 1947 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय – 11:00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये)

(व्यवधान)

बैठ जाइए अभी । जीरो ऑवर आएगा न, जीरो ऑवर आएगा ।

(व्यवधान)

अभी बैठ जाइए । जीरो ऑवर आएगा न तो विषय को रखिएगा । आपको समय दिया जाएगा । शून्यकाल में समय दिया जाएगा । मेरा आग्रह है क्वेश्चन ऑवर चलने दीजिए । कार्यस्थगन जब आएगा तो आपको बोलने का मौका दिया जाएगा । प्लीज बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

बिल्कुल, मौका दिया जाएगा । अभी क्वेश्चन ऑवर चलने दीजिए । कार्यस्थगन आपने दिया है, हमने देखा है, उस समय आप लोगों से बुलवाएंगे । बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर बैठ गये)

अब शपथ की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी ।

डॉ॰ रामानंद यादव : अध्यक्ष महोदय,..

अध्यक्ष : बात हो गई है ।

डॉ॰ रामानंद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न की ही बात करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : आप शून्यकाल में बातों को रखेंगे ।

डॉ॰ रामानंद यादव : अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में कैसे रखा जाएगा । यह आवश्यक है...

(व्यवधान)

बुकलेट में प्रश्न नहीं है । यह भारी मिस्टेक है । यह पहली बार ऐसा हुआ है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ठीक है, मैं दिखवा लेता हूं ।

(व्यवधान)

रामानंद बाबू, मैं बिल्कुल दिखवा लेता हूं । निश्चित तौर पर जाकर मैं दिखवा लेता हूं ।

अब शपथ की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी । माननीय सदस्य, शपथ पत्र की प्रति आपके सामने है । जब आप पुकारे जाएं तब आपको उसे पढ़ना है । सामने मेज पर एक रजिस्टर है, उसमें आपको हस्ताक्षर करना है । अब सभा सचिव नाम पुकारेंगी ।

शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण

सभा सचिव :	निर्वाचन क्षेत्र सं॰ एवं नाम	माननीय सदस्य का नाम	शपथ/प्रतिज्ञान
	178–मोकामा	श्री अनंत कुमार सिंह	(शपथ)

अध्यक्ष : अब शपथ ग्रहण की कार्यवाही समाप्त की जाती है ।

अब प्रश्नोत्तर काल होगा । तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । माननीय सदस्य, श्री संतोष कुमारा निराला जी ।

प्रश्नोत्तर काल

तारांकित प्रश्न सं॰–1, श्री संतोष कुमार निराला (क्षेत्र सं॰–202, राजपुर)

(लिखित उत्तर)

डॉ॰ प्रमोद कुमार, मंत्री : आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । बक्सर वन प्रक्षेत्र अंतर्गत सघन वृक्षारोपण एवं वन्यप्राणी संरक्षण से संबंधित विभिन्न विभागीय योजनाओं में दैनिक मजदूरों के माध्यम से कार्य लिया जाता है जिन्हें उपलब्ध आवंटन के आधार पर समय–समय पर भुगतान किया जाता है । बक्सर वन प्रक्षेत्र अंतर्गत मजदूरी भुगतान के संबंध में अद्यतन स्थिति निम्नवत् हैः

1. योजना मद से संचालित वृक्षारोपण योजनाओं में उपलब्ध आवंटन के आधार पर सितम्बर, 2025 तक कार्यरत सभी मजदूरों को वर्तमान न्यूनतम मजदूरी दर पर भुगतान किया जा चुका है ।

2. वन्यप्राणी संरक्षण योजनाओं में उपलब्ध आवंटन के आधार पर नवम्बर, 2025 तक कार्यस्त सभी मजदूरों को वर्तमान न्यूनतम मजदूरी दर पर भुगतान किया जा चुका है ।

3. कैम्पा मद से संचालित वृक्षारोपण योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2025–26 में केन्द्र सरकार से दिनांक–21.01.2026 को स्वीकृति प्राप्त हुई है । इस क्रम में राशि के आवंटन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । आवंटन प्राप्त होते ही मजदूरों को लम्बित भुगतान कर दिया जायेगा ।

सभी मजदूरों का मजदूरी भुगतान न्यूनतम मजदूरी दर पर ही किया जाता है ।

श्री संतोष कुमार निराला : महोदय, मैं पूछता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माईक ऑन कर लीजिए ।

डॉ॰ प्रमोद कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो मजदूर के मजदूरी की बात की है तो किस मद से मजदूर काम कर रहे हैं, योजना मद से, वन्यप्राणी संरक्षण मद से, कैंपा मद योजना से इन्होंने नहीं वर्णित किया है लेकिन मैं इन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि आने वाले समय में मजदूरों को वेतन दिया जाएगा, वह सारी प्रक्रिया चल रही है ।

अध्यक्ष : आपने स्पष्ट किया है कि आवंटन प्राप्त होते ही कर दिया जाएगा, है न ?

डॉ॰ प्रमोद कुमार, मंत्री : जी महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य ।

श्री संतोष कुमार निराला : ठीक है ।

अध्यक्ष : प्रमोद बाबू, दैनिक मजदूरी का क्या रेट है ?

डॉ॰ प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, सरकारी रेट है 429 रुपया प्रतिदिन, जो लेबर कॉस्ट है, जो सरकार ने तय किया है उसी आधार पर उनको दिया जाता है ।

अध्यक्ष : धन्यवाद । माननीय सदस्य, श्री संदीप सौरभ जी ।

<u>तारांकित प्रश्न सं॰–2, श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र सं॰–190, पालीगंज)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुंमार, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या–1729, दिनांक–07.10.2024 द्वारा राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन से संबंधित नीति निर्धारित है ।

उक्त के क्रम में विद्यालय अध्यापक को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं प्रशासी विभाग द्वारा स्थानान्तरण के निमित समय–समय पर निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में स्थानान्तरण की कार्रवाई संबंधित संवर्गीय पद संबंधित नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा किया जा सकेगा । साथ ही, अंकित करना है कि TRE–3 के बाद बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक का पदस्थापन किया गया है । विभागीय स्तर पर स्थानान्तरण/पदस्थापन संबंधी नियमावली का क्रियान्वयन अप्रैल, 2026 तक कर लिया जायेगा । तत्पश्चात शिक्षकों/शिक्षिकाओं का स्थानान्तरण की कार्रवाई की जायेगी ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, मैं पूछता हूँ ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या–1729, दिनांक–07.10.2024 द्वारा राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन से संबंधित नीति है । महोदय, इस संदर्भ में हम कहना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग द्वारा जो स्थानान्तरण किए गए हैं कुल 1 लाख 27 हजार 240 शिक्षकों का किया गया है, उसमें से सबसे पहले हमलोगों ने 690 वैसे शिक्षकों का स्थानांतरण किया जो असाध्य रोग से ग्रसित थे । दूसरा, TRE–1 के तहत 45,637 एवं TRE–2 के तहत 28237 शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया । जहां तक TRE–3 का प्रश्न है इसके संदर्भ में हमें कहना है कि जो TRE–1 का TRE–2 का हमलोगों ने स्थानांतरण किया वह कम से कम एक–एक साल अपने प्रोवेशन पर वहां थे, इनका प्रोवेशन जून–जुलाई में खत्म होगा, उसके बाद हमलोग इनका निश्चित रूप से पोर्टल पर लाकर के स्थानांतरण कर देंगे । उसमें एक ही बात है कि हमलोग दूरी को निश्चित रूप से देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ यह भी देखना पड़ेगा कि वैसे क्षेत्र जैसे–बांका का इलाका है बेलहर या फिर कैमूर का इलाका है या फिर जमुई के कुछ इलाके हैं तो इन जगहों पर वहां के छात्र–छात्राओं, वहां के लोगों ने कम क्वालिफाई किया है तो उन सब जगहों पर भी उनको भेजना आवश्यक है तो रिक्तियों को, इन सब बातों को देखते हुए TRE–3 वाला भी हमलोग जून–जुलाई में पोर्टल के आधार पर निश्चित रूप से कर देंगे ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, TRE–3 के बाद दो और बहालियां हुई हैं, उक्त प्रश्न में यह स्पष्ट है । प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक, ये दोनों बहालियां भी हुई हैं, दोनों के ट्रांसफर का विकल्प सरकार ने खोल रखा है, TRE–1, TRE–2 का भी है, केवल TRE–3 के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ट्रांसफर का विकल्प नहीं खुला है और एक साल से ज्यादा बहाली हो चुकी है । ये लोग अपने गृह जिला से तीन सौ किलोमीटर, चार सौ किलोमीटर, पांच–पांच सौ किलोमीटर का पोस्टिंग इनको दिया गया है, बक्सर के लोगों को पूर्णियां, पूर्णियां के लोगों को रोहतास इस तरह से पोस्टिंग मिली है, तो उसमें कई सारी महिलाएं हैं उनको कोई विकल्प नहीं मिल रहा है तो सरकार जल्द से जल्द उसको शुरू करे, एक तो यह बात कहना चाहते हैं । म्यूचुअल ट्रांसफर सरकार ने शिक्षकों का शुरू किया था लेकिन अचानक से म्यूचुअल ट्रांसफर का भी विकल्प सरकार ने बंद कर दिया, उसका पोर्टल बंद है तो TRE–3 का जल्द से जल्द स्थानांतरण का विकल्प खोला जाय और हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी एक बार कह दें कि म्यूचुअल ट्रांसफर का विकल्प क्यों बंद कर दिया गया है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, बता दीजिए ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह विचाराधीन है और TRE–3 वाला हमने कहा कि जैसे ही एक साल पूरा होगा उसके बाद ही TRE–1 और TRE–2 के जैसे उसी प्रक्रिया में निश्चित रूप से कर लेंगे और म्यूचुअल का जहां तक एक सर्टेन पीरिएड तक खुला था जिसके आधार पर हुआ था, हम पुनः उस पर विचार करेंगे । धन्यवाद ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर शिक्षक हैं ही नहीं, तो म्यूचुअल में तो कोई नुकसान नहीं है, वहां के शिक्षक, वहां के वहां जा रहे थे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा विचार करेंगे । आप बैठ जाइए ।

श्री संदीप सौरभ : कहां विचार करने के लिए कह रहे हैं ? म्यूचुअल ट्रांसफर का...

अध्यक्ष : उन्होंने बोला है । दुबारा बोल दीजिए । माननीय मंत्री जी दुबारा बोल दीजिए, माननीय सदस्य नहीं सुन पाए हैं ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : हमने कहा न, आपने जो सुझाव दिया है, हम उस पर पुनः विचार करेंगे । एक सर्टेन पीरिएड के लिए तो खुला ही था म्यूचुअल का, जिसमें सारे हो गए थे आपका जो सुझाव है उस पर हम विचार करेंगे । धन्यवाद ।

टर्न–2 / पुलकित / 03.02.2026

तारांकित प्रश्न सं0–3, श्री मोहम्मद मुर्शीद आलम (क्षेत्र सं0–50, जोकीहाट)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : उत्तर स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अभिभाषण एवं सात निश्चय–3 के अंतर्गत राज्य के वैसे प्रखण्ड, जहाँ पूर्व से महाविद्यालय संचालित नहीं है, उन प्रखंडों में महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । इस क्रम में विभागीय पत्रांक–40, दिनांक–14.01.2026 द्वारा राज्य के सभी जिला पदाधिकारी से भूमि की उपलब्धता के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई है ।

अध्यक्ष : जवाब दिया हुआ है, आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री मोहम्मद मुर्शीद आलम : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आया है । मैंने जोकीहाट डिग्री कॉलेज के संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री जी को 16.01.2026 को एक आवेदन भूमि विवरण के साथ दिया था । माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी मैंने 19.01.2026 को भूमि विवरण के साथ आवेदन दिया था । लेकिन जवाब जो आया है वह प्रत्याशा में है । मेरा कहना है कि सर उच्च विद्यालय, जोकीहाट में 11 एकड़ 85 डिसमील जमीन है और उच्च विद्यालय, उदाहाट में 13 एकड़ जमीन है। यहां के प्रस्ताव के लिए भी डी.एम. साहब को कहा जाए।

साथ ही, सर मेरा आग्रह है मंत्री महोदय जी से कि जोकीहाट जो प्लस टू उच्च विद्यालय है वहां पर काफी बिल्डिंग है, जिसमें डिग्री कॉलेज की क्लासेस को चालू किया जा सकता है और समय–सीमा भी सर बता दिया जाए कि कब तक डिग्री कॉलेज खोला जाएगा । चूंकि 26 पंचायत और एक नगर पंचायत का प्रखंड है । एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है सर, पिछड़ा इलाका है ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं सब बातों को देखकर राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अभिभाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सात निश्चय–3 में यह तय किया था कि प्रति प्रखंड में हम लोग डिग्री कॉलेज की स्थापना करेंगे । उसमें जो करीब–करीब 213 ऐसी जगह हैं जहां पर डिग्री कॉलेजों को स्थापित करना है । हम लोगों ने जो व्यवस्था की है कि इसको चरणबद्ध तरीके से अगले चार साल में पूरा करेंगे और जहां तक प्रश्न है उन्होंने जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर व्यवस्था है तो हम लोग उसका आकलन कर रहे हैं कि कुछ डायट (DIET) भी हैं, जो ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट हैं विभिन्न जिलों में, उसके अलावे जहां पर संभव हो पाएगा, उसको चिन्हित करके हम लोग शुरू करेंगे और जहां पर नहीं है वहां जमीन को एक्वायर करके जो डी.एम. से हम लोगों ने मांगा है 5 एकड़ ग्रामीण क्षेत्र में, ढाई एकड़ शहरी क्षेत्र में, तो वहां डिग्री कॉलेज का चरणबद्ध तरीके से हम लोग स्थापना करेंगे और इसका निर्माण करेंगे । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मनोहर प्रसाद सिंह जी ।

श्री मोहम्मद मुर्शीद आलम : सर, इस संबंध में जो कहा गया है, चूंकि 26 पंचायत और एक नगर पंचायत का प्रखंड है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा तो है ।

श्री मोहम्मद मुर्शीद आलम : ठीक है, सर उसको जरूर आदेश करने की कृपया की जाए ।

अध्यक्ष : बिल्कुल जरूर । माननीय मंत्री ने स्पष्ट कहा है आपके प्रस्ताव पर सरकार विचार करेगी ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : अब आगे बढ़ गये । प्लीज बात आगे निकल गयी ।

श्री अखतरूल ईमान : सर, मैं माननीय मंत्री जी से यह गुजारिश करूंगा आपके हवाले से कि चरणबद्ध तौर पर जो वे कॉलेजेज स्थापित करना चाह रहे हैं, सीमांचल का वह क्षेत्र क्योंकि शैक्षणिक तौर पर काफी पिछड़ा है इसलिए उसको पहले चरण में लिया जाए, यही विनती हमारी होगी ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य श्री मनोहर प्रसाद सिंह जी ।

(व्यवधान)

शांति–शांति ।

तारांकित प्रश्न सं0–4, श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र सं0–67, मनिहारी)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक ।

समाहर्त्ता, कटिहार के पत्रांक–89, दिनांक–30.01.2026 द्वारा प्रतिवेदित है कि कटिहार जिला के मनिहारी थाना अंतर्गत कांटाकोश पंचायत और नगर पंचायत, मनिहारी के कतिपय स्थानों पर अवैध खनन एवं परिवहन की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल खनन टीम के द्वारा छापेमारी की गई । इस संबंध में मनिहारी थानान्तर्गत अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के मामले में प्राथमिकी संख्या–05/26, दिनांक–06.01.2026 दर्ज करायी गयी है । अवैध खनन एवं परिवहन के पूर्णतः रोकथाम हेतु जिला खनन टीम एवं स्थानीय अनुमंडल प्रशासन, मनिहारी के द्वारा संयुक्त रूप से जाँच एवं छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : महोदय, उत्तर प्राप्त है । उत्तर में दिया गया है कि एक प्राथमिकी संख्या–05/26, दिनांक–06.01.2026 में मामला दर्ज किया गया है । लेकिन सामान्य जनता का एक प्रश्न आया था और एक पेटिशन भी आई थी जिला पदाधिकारी और अन्य लोगों को भी दी गयी थी । दिनांक–26.01.2026 को मैंने भी जिला पदाधिकारी को ई–मेल द्वारा इसकी सूचना दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई । दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों का नाम दिया गया है, उस पेटीशन में राम निवास यादव और अन्य लोगों का नाम दिया गया है । यह आदमी जो जदयू के उम्मीदवार थे उनके समर्थक हैं और दुर्दांत क्रिमिनल है, उनके समर्थक हैं इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। 200 से 500 ट्रक रोज मिट्टी काटी जा रही है । कई–कई लोगों ने बहुत उसके लिए विरोध भी किया है । सड़क टूट गई वहां लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई । प्रशासन और जो पॉलिटिकल संरक्षण है उसके चलते यह हो रहा है । मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा, क्या इसकी जांच कराने का विचार करते हैं ? जो क्रिमिनल हैं उन पर कार्रवाई हो, जो सड़क टूट गई है उसकी मरम्मत की जाए और जो लोग सहायक हैं, जो प्रशासनिक पदाधिकारी सहायक हैं क्या उनके विरुद्ध जांच कर कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न आंशिक स्वीकारात्मक है । महोदय, समाहर्ता कटिहार के पत्रांक 89, दिनांक 30.01.2026 द्वारा प्रतिवेदित है कि कटिहार जिला के मनिहारी थाना अंतर्गत कांटाकोश पंचायत और नगर पंचायत मनिहारी के कतिपय स्थानों पर अवैध खनन एवं परिवहन की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल खनन टीम के द्वारा छापेमारी की गई । इस संदर्भ में मनिहारी थाना अंतर्गत अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के मामले में प्राथमिकी संख्या 5/26, दिनांक 06.01.2026 दर्ज

कराई गई है । अवैध खनन एवं परिवहन के पूर्णतः रोकथाम हेतु जिला खनन टीम एवं स्थानीय अनुमंडल प्रशासन, मनिहारी के द्वारा संयुक्त रूप से जांच एवं छापेमारी की जा रही है । माननीय सदस्य जो जानकारी दिए हैं, तो वह हम पूरी तरह से फिर से एक उड़नदस्ता भेज कर जांच भी करवा लेते हैं ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : हम माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से बिल्कुल असंतुष्ट नहीं हैं लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जो 200 से 500 ट्रक रोज चलते हैं, रातभर चलते हैं, उसके लिए क्या कार्रवाई की गई ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि फ्लाइंग स्क्वायड भेज करके उसकी जांच कराई जाएगी, कार्रवाई की जाएगी ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, ऐसे माननीय सदस्य और इनके माध्यम से सभी सदस्यों को कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो माइंस पॉलिसी बनी, खनन नीति, आज उसका असर पूरे बिहार में दिखाई पड़ रहा है और देश में बिहार पहला राज्य है जहां ओवरलोडिंग पूरी तरह से लगभग बंद है और अवैध खनन पर भी, महोदय अब ट्रक पर खनन नहीं होता है, इनका अभी जो मामला है वो ट्रैक्टर का है और चार ट्रैक्टर पकड़ाया । माननीय मुख्यमंत्री जी के....

(व्यवधान)

नहीं, हम बता रहे हैं कि ये थाना अंतर्गत इस तरह की कई छापेमारी हुई, हमने तो अब जारी कर दिया है कि किसी भी बड़ी गाड़ी का वीडियो बनाकर के भेजेंगे, हमारा कमांड कंट्रोल में बैठा हुआ है प्रधान सचिव के पास सिर्फ वो डिटेल है । उसको हम 10 हजार का ईनाम देते हैं और ट्रैक्टर पर 5 हजार का ईनाम देते हैं । मुख्यमंत्री जी के द्वारा कई लोगों को ईनाम गया है । अगर जो उसकी जानकारी, सूचना देंगे पूरी शक्ति के साथ कार्रवाई करेंगे । आप जो बता रहे हैं, एक–दो जगह इधर का मामला आया है चुनाव के पीरियड में थाने के अंतर्गत ट्रैक्टर वाले की कुछ जानकारी मिली है, तो फिर उसका हम लोग पेट्रोलिंग करके, जांच करके पूरी शक्ति के साथ कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मो0 सरवर आलम जी ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, पूरा सोन बर्बाद हो रहा है, इधर । महोदय, 30–30 मीटर की खुदाई हो रही है ।

अध्यक्ष : इस प्रश्न में सोन नहीं है । आप बैठ जाइये ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, पटना से लेकर सोन में बीच में....

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : माननीय सदस्य लिखकर के दे दे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी कह रहे हैं । सौरभ जी, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि लिखकर के दीजिए कार्रवाई होगी ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि ट्रैक्टर पकड़ा गया है, निश्चित रूप से वही ट्रैक्टर पकड़ा जाता है जो पैसा नहीं देता और हाईवा से ड्राइव जांच....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य जांच होने दीजिए । जांच का इंतजार कीजिए । माननीय सदस्य मो0 सरवर आलम जी ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य सौरभ जी लिखकर के मंत्री जी को दे दीजिए ।

तारांकित प्रश्न सं0–5, श्री मो0 सरवर आलम (क्षेत्र सं0–55, कोचाधामन)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखण्ड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सुकरना में 375 फीट नया चहारदीवारी निर्माण की आवश्यकता है ।

जिला शिक्षा कार्यालय, किशनगंज के पत्रांक–161, दिनांक–31.01.2026 द्वारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सुकरना में चहारदीवारी के निर्माण हेतु बिहार राज्य आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (BSEIDC), पटना से चहारदीवारी निर्माण हेतु अनुरोध किया गया है ।

उक्त चहारदीवारी का निर्माण BSEIDC, पटना द्वारा स्वीकृत्योपरांत अगले छः माह में पूर्ण कराने का लक्ष्य है ।

श्री मो0 सरवर आलम : जी जवाब आया है । अध्यक्ष महोदय जवाब आया है । माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि इसे जल्द से जल्द निर्माण करा दिया जाए। जवाब से मैं संतुष्ट हूँ पर इसमें थोड़ा सा जल्दी करा दिया जाए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुजीत कुमार जी।

तारांकित प्रश्न सं0–6, श्री सुजीत कुमार (क्षेत्र सं0–79, गौड़ाबौराम)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : 1– आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2011–12 से केन्द्र सरकार के द्वारा साक्षर भारत कार्यक्रम के नाम से योजना संचालित की गई, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा 01 अप्रैल, 2018 से बंद कर दिया गया है । फलस्वरूप इस कार्यक्रम में कार्यरत प्रेरक एवं अन्य संविदाकर्मी की सेवा समाप्त हो गई है । केन्द्र प्रायोजित यह योजना एक खास कालावधि के लिये ही थी ।

2– आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि योजना अवधि के दौरान संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में शिक्षा प्रेरकों से अपेक्षित आवश्यक सहयोग ली जाती थी ।

3– अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि इस योजना के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों के समायोजन संबंधी दावों को माननीय न्यायालय के द्वारा सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या–22712/2018 में दिनांक–15.11.2022 एवं कतिपय अन्य न्यायादेशों में पारित आदेश के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है । साक्षर भारत कार्यक्रम के शिक्षा प्रेरकों के समायोजन का कोई प्रस्ताव राज्य सकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

टर्न–3/हेमन्त/03.02.2026

अध्यक्ष : पूछिये ।

श्री सुजीत कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी से....

अध्यक्ष : उत्तर मिला है न ?

श्री सुजीत कुमार : जी।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये।

श्री सुजीत कुमार : जी। क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा बिहार में शिक्षा प्रेरक के पद का सृजन...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये न। माननीय सदस्य, जब उत्तर मिल गया है, तो आप सप्लीमेंट्री पूछिये।

श्री सुजीत कुमार : जी। उत्तर मिल गया है और हम उससे संतुष्ट हैं।

अध्यक्ष : ठीक है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–7, श्री फैसल रहमान (क्षेत्र सं0–21, ढाका)</u>

अध्यक्ष : उत्तर मिला है ?

श्री फैसल रहमान : जी नहीं।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, इसका उत्तर हमने दिया है। यहां भी उसी तरह का प्रश्न है कि सरकार ने जो वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट अभिभाषण में भी कहा और माननीय मुख्यमंत्री जी के सात निश्चय–3 में जो हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने की बात कही गयी है, तो हमने सभी जिला पदाधिकारियों से डिटेल्स मांगे हैं। 2013 प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से हम लोग इसे खोलेंगे और बीएसआरडीसी और अन्य एजेंसी से उसका निर्माण करायेंगे और हम लोग तत्काल जहां पर डायरेक्ट या अन्य जगह सुविधा उपलब्ध है वहां विचार कर रहे हैं कि इस सत्र से डिग्री कॉलेज की पढ़ाई भी शुरू की जायेगी। धन्यवाद।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–8, श्री रोहित पाण्डेय (क्षेत्र सं0–156, भागलपुर)</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0–9, श्री अतिरेक कुमार (क्षेत्र सं0–78, कुशेश्वरस्थान)

श्री अतिरेक कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि क्या यह सही बात है कि दरभंगा जिले के कुशेश्वरस्थान में...

अध्यक्ष : उत्तर मिला है न ?

श्री अतिरेक कुमार : जी नहीं, उत्तर नहीं मिला है।

अध्यक्ष : बैठिये। माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : उत्तर स्वीकारात्मक।

उत्तर कंडिका–(2) एवं (3) वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अभिभाषण एवं सात निश्चय–3 के अंतर्गत राज्य के वैसे प्रखण्ड, जहां पूर्व से महाविद्यालय संचालित नहीं है, उन प्रखंडों में महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में विभागीय पत्रांक–40, दिनांक 14.01.2026 द्वारा राज्य के सभी जिला पदाधिकारी से भूमि की उपलब्धता के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी है। इस संबंध में पूर्व में भी हमने सदन को सूचित किया है कि चरणबद्ध तरीके से इसको हम लोग पूरा करेंगे। धन्यवाद।

तारांकित प्रश्न सं0–10, श्रीमती कोमल सिंह (क्षेत्र सं0–88, गायघाट)

(लिखित उत्तर)

सुश्री श्रेयसी सिंह, मंत्री : 1– स्वीकारात्मक ।

2– वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–538, दिनांक–02.02.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि गायघाट प्रखंड के पंचायत जारंग पश्चिमी में एवं बंदरा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत– सुन्दरपुर रतवारा में पूर्व से ही आउटडोर स्टेडियम निर्मित है ।

3– अस्वीकारात्मक । राज्य द्वारा सभी प्रमंडलों में प्रमंडल स्तरीय खेल अवसंरचना का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है । उक्त आलोक में गायघाट प्रखंड में प्रमंडलस्तरीय खेल अवसंरचना निर्माण हेतु 13 एकड़ भूमि चिन्हित किया गया है ।

4– इस खंड का उत्तर कंडिका–02 एवं 03 में सन्निहित है ।

श्रीमती कोमल सिंह : मैं पूछती हूं।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

सुश्री श्रेयसी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो दिया हुआ है ऑनलाईन।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए। उत्तर मिला है न आपको ?

श्रीमती कोमल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर मुझे मिला है उससे मैं असंतुष्ट हूं। कंडिका–2 में मुझे उत्तर दिया गया था कि जारंग पंचायत में और रतवारा पंचायत में स्टेडियम निर्मित है, लेकिन मेरा सवाल है कि जिस स्टेडियम की बात की जा रही है वह जारंग हाईस्कूल और रतवारा हाईस्कूल का फील्ड है,

जहां पर न रनिंग ट्रैक है, न फुटबॉल ग्राउंड है, न चेंजिंग रूम है, न एलईडी फ्लड लाईट्स हैं, न टॉयलेट है। तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि वहां पर उच्चस्तरीय जांच कराकर और इसकी सत्यता के आधार पर वहां स्टेडियम निर्माण करने का कष्ट करें।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

सुश्री श्रेयसी सिंह, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, गायघाट प्रखंड के पंचायत जारंग पश्चिमी में 11.07.2021 को फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण किया गया है जिसकी लागत 1.2 करोड़ की है यानी कि कुल लागत 1 करोड़ 20 लाख की है और माननीय मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत इसको पूर्ण किया गया है। इस बार खेल विभाग ने विधान सभा का सत्र शुरू होने से पहले जो कार्रवाई की उसमें जियो टैगिंग के साथ मेरे पास पिक्चर भी उपलब्ध है, फोटो भी उपलब्ध है। यदि माननीय सदस्या चाहे, तो उनको हम लोग वहां पर विजिट करा सकते हैं और सुझावानुसार कार्रवाई कर सकते हैं।

श्रीमती कोमल सिंह : बहुत–बहुत धन्यवाद। एक और चीज है कि कंडिका–3 में प्रमंडलस्तरीय भूमि चयनित की गयी है स्टेडियम बनाने के लिये। मैं उसके लिए भी माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वहां पर जल्द–से–जल्द समय–सीमा के अंदर स्टेडियम बनाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

अध्यक्ष : दिखवा लीजिए।

सुश्री श्रेयसी सिंह, मंत्री : जी।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–11, श्री संजय कुमार सिंह (क्षेत्र सं0–76, सिमरी बख्तियारपुर)</u>

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सहरसा जिलान्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के मोहमदपुर पंचायत में अवस्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, बड़हकुरवा में कुल नामांकित छात्र/छात्राओं की संख्या–170, पदस्थापित शिक्षक/शिक्षिकाओं की संख्या–07, कुल वर्ग कक्ष की संख्या–02 है, जिसमें पठन–पाठन का कार्य संचालित किया जाता है। विद्यालय परिसर में 01 क्रियाशील शौचालय एवं 01 चापाकल उपलब्ध है। नये वर्ग कक्ष निर्माण हेतु लगभग 2500 वर्ग फीट भूमि उपलब्ध है। विद्यालय में चहारदीवारी का भी अभाव है। आवश्यकतानुसार जो हम लोगों ने आकलन किया और हमने समीक्षा भी की बीएसईआईडीसी से, तो वहां पर 04 वर्ग कक्ष, 02 शौचालय (बालक/बालिका) एवं 320 फीट चाहरदीवारी निर्माण हेतु जिला कार्यालय का पत्रांक 50, दिनांक 30.01.2026 द्वारा प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना से अनुरोध किया गया है। उक्त विद्यालय से संबंधित आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कार्य प्राथमिकता के

आधार पर स्वीकृति के उपरांत 08 माह में पूर्ण कराने के लिए कहा गया है। क्योंकि वास्तव में वहां पर यह कमियां, जो माननीय विधायक ने प्रश्न उठाया है। उसको हम लोग 8 महीना में पूरा करेंगे। धन्यवाद।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : पहले पूछने दीजिए। तीन पूरक पूछने दीजिए न।

(व्यवधान)

अनुमति मिले तब बोलिये। भाई वीरेन्द्र जी, उनके तीन पूरक होने के बाद।

श्री संजय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें भवन बहुत दिनों से बन रहा है, लेकिन वहां का ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। इस पर माननीय मंत्री महोदय, ऐनी गांव है यह, यहां पर काम रूका हुआ है, भवन की कमी है, इस पर ध्यान दिया जाये।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अपने जवाब में भी कहा कि माननीय प्रश्नकर्ता ने ठीक कहा कि अभाव है। हम लोग उस जगह की समीक्षा करके 8 महीने का समय ले रहे हैं, तो उसको पूरा कर लेंगे।

श्री संजय कुमार सिंह : जी धन्यवाद।

अध्यक्ष : बोलिये। क्या कहना चाहते हैं।

श्री भाई वीरेन्द्र : मैंने कहा कि....

अध्यक्ष : आगे भविष्य में आसन से अनुमति लेकर आसन से।

श्री भाई वीरेन्द्र : आसन से अनुमति लेकर ही मैं बोल रहा हूं कि इस सरकार को निदेश देना चाहिए न। सरकार अनुरोध नहीं करती है। सरकार निदेश देती है कि यह आपको करना है।

अध्यक्ष : सुनने में गलती आपको हुई है। निदेश ही है।

तारांकित प्रश्न सं0–12, श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र सं0–87, जाले)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0–13, श्री उपेन्द्र प्रसाद (क्षेत्र सं0–225, गुरूआ)

श्री उपेन्द्र प्रसाद : पूछता हूं।

अध्यक्ष : उत्तर मिला है ?

श्री उपेन्द्र प्रसाद : नहीं मिला है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक।

वस्तुस्थिति यह है कि गयाजी जिला के गुरारू प्रखंडान्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, सोनडीहा में कुल नामांकित छात्रों की संख्या 450, पदस्थापित शिक्षकों की संख्या 18, कमरों की संख्या 12 जिसमें 8 कमरा वर्ग कक्ष हेतु 01 स्मार्ट क्लास, 01 में लाईब्रेरी, 01 में प्रयोगशाला कक्ष एवं शौचालय की संख्या 08 उपलब्ध है। वर्तमान में विद्यालय में 40 जोड़ी बेंच–डेस्क एवं पेयजल हेतु समरसेबुल उपलब्ध है।

इसमें हम पुनः दिखवा लेंगे और जिस चीज की भी कमी होगी उसको हम लोग पूरा कर देंगे। धन्यवाद।

श्री उपेन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, यह विद्यालय उत्क्रमित होने के बाद भी उसी सुविधा से चल रहा है। इसलिए उच्च विद्यालय में उत्क्रमित होने के बाद अतिरिक्त कोई सुविधा मुहैया नहीं करायी गयी है।

अध्यक्ष : समीक्षा कर लीजिए।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि इसकी समीक्षा करके जो अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होगी उसको हम लोग पूरा करेंगे।

तारांकित प्रश्न सं0–14, कलाधर प्रसाद मंडल (क्षेत्र सं0–60, रूपौली)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना के प्रतिवेदनानुसार पूर्णियां जिलान्तर्गत प्रखंड–रूपौली स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय, महबल्ला (Group no SSS-1324) के 10+2 भवन निर्माण हेतु संवेदक कमलेश मेसकोन, पटना के साथ दिनांक 26.10.2021 को एकरारनामा संपादित किया गया था, परंतु संवेदक द्वारा मार्च 2022 से कार्य बिना सूचना के बंद रखा गया, जिससे कार्य प्रगति अत्यंत धीमी रही। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार संवेदक को भुगतान केवल निष्पादित कार्य के अनुपात में किया गया है। संवेदक को नोटिस निर्गत कर विलंब के लिए स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। कार्य में विलंब के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड पूर्णिया के पत्रांक– DMT/PUR/84, दिनांक 01.02.2026 यह सूचना दी गयी है कि संवेदक के द्वारा शेष कार्यों का निर्माण कार्य अगले छः माह में पूरा कर लिया जायेगा।

श्री कलाधर प्रसाद मंडल : माननीय अध्यक्ष महोदय, रूपौली प्रखंड के महाबल्ला गांव के उत्क्रमित विद्यालय में भवन निर्माण 2020 में शुरू हुआ था और आज तक संवेदक के द्वारा उसको पूरा करने का काम नहीं किया गया। बच्चों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बच्चे यत्र–तत्र भटकते हैं। अतः माननीय से निवेदन है कि यथाशीघ्र संवेदक पर कार्रवाई करते हुए भवन निर्माण को तेज गति देकर उसे पूर्ण कराने की कृपा की जाय।

टर्न–4 / संगीता / 03.02.2026

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कहना सही है कि संवेदक की गलती है, उसने काफी समय लिया है । उनको अंतिम चेतावनी के साथ मौका दिया गया है जो शेष काम है उनको 6 माह में पूरा कर लें अन्यथा उनको हमलोग ब्लैकलिस्ट करेंगे तो यह अंतिम मौका उन्होंने मांगा था चूंकि

पूरा टेंडर करना पड़ता तो उसमें और समय लगता इसलिए यह अंतिम मौका है अगर नहीं करेंगे तो प्रगति सही नहीं होगी तो 2 महीना के अंदर ब्लैकलिस्ट करके हमलोग दूसरे से काम पूरा करायेंगे ।

अध्यक्ष : श्री दामोदर रावत जी ।

तारांकित प्रश्न संख्या–15 (श्री दामोदर रावत, क्षेत्र सं0–242, झाझा)
(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय, सिमुलतला, जमुई हेतु सिमुलतला शिक्षा सोसाईटी अन्तर्गत 13 (तेरह) शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी अनुबंध पर तथा 11 (ग्यारह) शिक्षकेत्तर कर्मी दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत हैं । शिक्षकों की कमी के कारण विभिन्न विषयों के 26 (छब्बीस) शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति सिमुलतला आवासीय विद्यालय में की गयी है ।

सिमुलतला आवासीय विद्यालय हेतु सृजित पद के अंतर्गत स्थायी नियुक्ति हेतु 63 (तिरसठ) उच्च माध्यमिक/माध्यमिक शिक्षकों के चयन के लिए विज्ञापन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित की गयी है । उनके द्वारा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम प्रकाशित कर दिया गया है तथा मुख्य परीक्षा लेने की कार्रवाई की जा रही है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री दामोदर रावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, इन्होंने कहा है कि 13 शिक्षक सिमुलतला शिक्षा सोसाइटी के माध्यम से नियुक्त किया गया है और 26 शिक्षक वहां पर डिप्यूटेशन पर कार्यरत हैं । मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि उस विद्यालय की जब स्थापना की गई थी, वह बिहार का एकमात्र विद्यालय था और माननीय मुख्यमंत्री का स्वप्न था कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय समूचे बिहार में अव्वल हो और वहां शिक्षकों की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पायी है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 16.12.2024 में जो रिजल्ट निकला है शिक्षकों का, उसके बाद बी0पी0एस0सी0 ने मेंस का परीक्षा अभी तक नहीं लिया है । कब तक ये परीक्षा करवा लेंगे और कब तक शिक्षकों की नियुक्ति करायेंगे, इसी बात की जानकारी दे दें मंत्री जी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सिमुलतला स्कूल का माननीय सदस्य का कहना सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसके तहत उस स्कूल की स्थापना की गई और वहां पर जो हमलोगों ने अधियाचना भेजी थी तो पुनः हमलोगों ने बी0पी0एस0सी0 से संपर्क किया है कि उसको जल्द से

जल्द करा दें क्योंकि एक बार जब आप अधियाचना भेज देते हैं तो कमीशन का काम होता है । कमीशन ने इसमें निश्चित रूप से विलंब किया है । हमलोगों ने उनसे पुनः आग्रह किया था कि शिक्षकों की कमी को पूरा करें तब तक हम डिप्यूटेशन से काम चला रहे हैं और साथ ही साथ माननीय सदस्य को यह बताना चाहेंगे कि वहां पर जो कुछ कमियां थीं प्रिंसिपल की नियुक्ति वगैरह की तो उसपर भी हमलोग पुनः विचार कर रहे हैं कि और लोगों को वाइडर सर्कल से लाया जाए ताकि उसका काम और अधिक सुचारू रूप आगे बढ़ सके । धन्यवाद ।

श्री दामोदर रावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की नियुक्ति की अधिसूचना कब जारी होगी ?

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अभी वहां पर प्रतिनियुक्ति पर है लेकिन जो ऑरिजल बातें थीं, उसमें जिस तरह के प्रिंसिपल वहां पर हैं, शुरू में ठीक थे लेकिन बाद में हाल में जब डिप्यूटेशन पर थे, कमियां पायी गयीं, जब उसकी समीक्षा की गयी । इसी वजह से ताकि और लोग उसके लिए उपलब्ध हो सकें जैसे कि एक्स मिलिट्री पर्सनल या इस तरह के लोग भी आ सकें ताकि उसका बहुत सुचारू रूप से हो सके तो उसको हम समझते हैं कि जल्द सारी व्यवस्था 15–20 दिनों के अंदर एडवरटिजमेंट निकालकर इंटरव्यू लेकर एक या डेढ़ महीने का समय लगेगा, उसको कर देंगे ।

अध्यक्ष : श्रीमती शालिनी मिश्रा ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–16 (श्रीमती शालिनी मिश्रा, क्षेत्र संख्या–15, केसरिया)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अभिभाषण एवं सात निश्चय–3 के अंतर्गत राज्य के वैसे प्रखण्ड, जहां पूर्व से महाविद्यालय संचालित नहीं है, उन प्रखंडों में महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । इस क्रम में विभागीय पत्रांक–40, दिनांक–14.01.2026 द्वारा राज्य के सभी जिला पदाधिकारी से भूमि की उपलब्धता के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूं आप सबों को कि ये जो ई–टैब हमारे सीट्स पर लगाया है उससे काफी अच्छा हो गया है, सभी प्रश्न और सभी उत्तर दिख रहे हैं और हमलोग तैयारी के साथ काम कर पा रहे हैं । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जिलाधिकारी जी से मंगाया है, सभी जिलाधिकारी से मंगाया है और 13 जगहों पर प्राथमिकता के साथ होगा, पिछले जवाब में मैंने सुना था तो मैं जानना चाहती

हूं कि हमारा केसरिया ब्लॉक और संग्रामपुर ब्लॉक डिग्री कॉलेज के लिए 13 जगहों की प्राथमिकता में है या नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा के दौरान जो उन्होंने घोषणाएं की थी उसमें काम भी लग गया है तो बाकी का हमलोग चरणबद्ध तरीके से ही ले पायेंगे इस वित्तीय वर्ष में और उनका निश्चित रूप से हमलोग ख्याल रखेंगे जब ये चुनाव होंगे तब ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री मनोज विश्वास ।

तारांकित प्रश्न संख्या–17 (श्री मनोज विश्वास, क्षेत्र संख्या–48, फारबिसगंज)

(लिखित उत्तर)

श्रीमती रमा निषाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड–1 अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि विभागन्तर्गत 1. अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय, 2. अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास एवं 3. जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास संचालित है ।

खंड–2 आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय में छात्राओं के नामांकन हेतु माता–पिता का पारिवारिक वार्षिक आय तीन लाख रूपये है ।

अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में नामांकन हेतु छात्र/छात्राओं के लिए कोई पारिवारिक आय सीमा नहीं है, अपितु वैसे छात्र–छात्राओं जिनके अभिभावक का आय कम होगा, उन्हें नामांकन में प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है ।

खंड–3 उपर्युक्त कंडिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है । वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय में छात्राओं के नामांकन हेतु माता–पिता का वार्षिक आय तीन लाख रुपये है, जिसे समाप्त करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री मनोज विश्वास : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो छात्रावास हैं उसमें हमारे यहां से अगर विद्यार्थी पढ़ने के लिए पटना आयेंगे वही विद्यार्थी आयेंगे जो घर से सुखी–संपन्न होंगे तो उसमें आय सीमा 3 लाख कर दिया है । इस आय सीमा को हटाकर मेरिट के हिसाब से उसकी छात्रावास में नियुक्ति हो इसके लिए हम चाहेंगे कि आप सदन के सभी लोग इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्रीमती रमा निषाद, मंत्री : वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय में छात्राओं के नामांकन हेतु माता–पिता का पारिवारिक वार्षिक आय 3

लाख रुपये है। अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में नामांकन हेतु छात्र–छात्राओं के लिए कोई पारिवारिक आय सीमा नहीं है अपितु ऐसे छात्र छात्राओं जिनके अभिभावक का आय कम होगा, उन्हें नामांकन में प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान है ।

श्री मनोज विश्वास : अध्यक्ष महोदय, उसका आय सीमा को समाप्त किया जाए ।

अध्यक्ष : आपका सुझाव है कि मेधा के आधार पर किया जाए ।

श्री मनोज विश्वास : जी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी इसको देख लीजिए ।

श्रीमती रमा निषाद, मंत्री : जी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य सचीन्द्र प्रसाद सिंह ।

तारांकित प्रश्न संख्या–18 (श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, क्षेत्र सं0–16, कल्याणपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अभिभाषण एवं सात निश्चय–3 के अंतर्गत राज्य के वैसे प्रखण्ड, जहां पूर्व से महाविद्यालय संचालित नहीं है, उन प्रखंडों में महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । इस क्रम में विभागीय पत्रांक–40, दिनांक–14.01.2026 द्वारा राज्य के सभी जिला पदाधिकारी से भूमि की उपलब्धता के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई है ।

सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है । मैं माननीय मंत्री से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इन्होंने कहा है कि सभी जिला पदाधिकारी को पत्रांक–40 दिनांक–14.01.2026 से पत्र उपलब्ध करा दिया गया है तो क्या इसमें जो पहले से प्लस टू विद्यालय हैं उसको अपडेट करके डिग्री कॉलेज बनायेंगे या जो प्राइवेट कॉलेज चल रहा है जो उसमें डिग्री ले रहे हैं, उसमें कितना जमीन होगा तो उसको बनाना चाहते हैं कितना जमीन का रिपोर्ट मिलेगा तब ये कॉलेज बनायेंगे, ये जानना चाह रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने शुरू में ही अपने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा था कि ग्रामीण इलाके में 5 एकड़ और शहरी इलाकों में ढाई एकड़ जमीन की उपलब्धता जरूरी है और दूसरा है कि जिस प्लस टू विद्यालय में काफी जमीन उपलब्ध है और वहां पर यह देखा जाएगा कि वहां उनलोगों को खेलने इत्यादि में दिक्कत नहीं हो और तब भी 5 एकड़ या ढ़ाई एकड़ जमीन उपलब्ध हो पाएगी तो उस परिसर में हमलोग बनायेंगे लेकिन फिलहाल किसी भी और जहां तक सत्र का प्रश्न है शुरू करने का तो जहां पर संभव है जो डायट के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहां करेंगे और जहां संभव है कर

पायेंगे उसको हमलोग चिन्हित कर रहे हैं लेकिन प्राइवेट कॉलेज को लेकर वहां शुरू कर देंगे ऐसी व्यवस्था अभी विचाराधीन नहीं है । धन्यवाद ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, हमारा कल्याणपुर ब्लॉक मोतिहारी जिले का पूर्वी चंपारण का सबसे बड़ा ब्लॉक है, 5 लाख से ज्यादा की आबादी उस ब्लॉक की है, 24 पंचायत का ब्लॉक है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कल्याणपुर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज का एक समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं क्या और दूसरा कि जो इन्होंने अहर्ता तय किया है तो पहले से अगर उसमें इंटर कॉलेज प्लस टू चल रहा है तो उसमें जितनी जमीन है उस जमीन को छांटकर इनको ढाई बीघा जमीन चाहिए या फिर 5 बीघा जो शहरी क्षेत्र में पहले से चल रहा है उसके अलावे चाहिए, इसको जरा स्पष्ट करना चाहेंगे ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने स्पष्ट किया कि अगर आप डिग्री कॉलेज ग्रामीण क्षेत्र में खोलना चाहते हैं तो हमें 5 एकड़ जमीन की आवश्यकता पड़ेगी और ढाई एकड़ शहरी क्षेत्र में आवश्यकता पड़ेगी यह हमने कहा है और जहां तक कल्याणपुर का प्रश्न है हमलोग जरूर उसको प्राथमिकता से कोशिश करेंगे कि इसको चरणबद्ध तरीके में लेने का । धन्यवाद ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक समय सीमा तय करा दिया जाए...

अध्यक्ष : श्री आदित्य कुमार ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : एक समयसीमा तय कर दें तो...

अध्यक्ष : सरकार प्रयासरत है ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : कुल 200 से ज्यादा हैं तो एक वर्ष में नहीं हो पाएगा इसलिए हमने 4 वर्ष का समयसीमा तय किया है ।

अध्यक्ष : चरणबद्ध होगा, धैर्य रखिए, होगा ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, होना है धैर्य रखिए, बहुत स्पष्ट कहा है इन्होंने । माननीय सदस्य आदित्य कुमार ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–19 (श्री आदित्य कुमार, क्षेत्र संख्या–92, सकरा)</u>

(लिखित उत्तर)

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंडान्तर्गत डिहूली इशहाक, रूपनपट्टी सहित अन्य पंचायतों में घोड़परास से फसल बर्बादी की क्षेत्रीय कार्यालय में सूचना है, किन्तु हजारों एकड़ में फसल बर्बादी के संबंध में किसी प्रकार की पुष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है ।

वर्ष 2024–25 में मुजफ्फरपुर जिला के सरैया प्रखंड में 14, मोतीपुर में 10, मैनापुर में 51, सकरा में 14, मुशहरी में 35 अर्थात कुल 124 आतंकी घोड़परासों का नियमानुसार आखेट किया गया है ।

राज्य के अंतर्गत सभी मुखिया को उनकी पंचायत की सीमा के अंदर गैर–वन इलाकों में ऐसे घोड़परास तथा जंगली सुअर, जो खेती/बागवानी की फसल तथा मनुष्यों के जान–माल के लिए खतरनाक हो चुके हैं, को आखेट/मारने का आदेश देने हेतु प्राधिकृत किया गया है । इस हेतु घोड़परास के मारने पर अनुज्ञप्तिधारी शूटर को प्रति घोड़परास रू0 750/– (सात सौ पचास रूपये) एवं मारे गये घोड़परास को जमीन में गाड़ने हेतु रू0 1250/– (एक हजार दो सौ पचास रूपये) प्रति तो घोड़परास का प्रावधान किया गया है ।

इसके अतिरिक्त घोड़परास द्वारा फसल नष्ट किये जाने पर 50000/– (पचास हजार) प्रति हेक्टेयर सहाय्य राशि के भुगतान का प्रावधान भी किया गया है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री आदित्य कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है । उत्तर में माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि घोड़परास से फसल बर्बादी की सूचना क्षेत्रीय कार्यालय को है लेकिन हजारों एकड़ में फसल बर्बादी की पुष्ट सूचना नहीं है । महोदय, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं । क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुझे जानकारी मिली है और हमने देखा भी है वहां हजारों एकड़ में लगे फसल को नीलगाय के द्वारा बर्बाद किया गया है । दूसरी बात, उत्तर में यह भी कहा गया है कि सभी मुखिया को खतरनाक हो चुके जंगली सुअर, घोड़परास को मारने हेतु प्राधिकृत किया गया है । महोदय, मुखिया के पास मारने वाले शुटर रहेंगे तब न होगा । हम आग्रह करेंगे कि सरकार वहां के मुखिया को तिथि तय कर लाइसेंसी शुटर उपलब्ध कराए और महोदय, मुजफ्फरपुर जिला में माननीय मंत्री जी के जवाब में कहा गया है कि 2024–25 में 124 घोड़परासों का आखेट किया गया है तो मैं बताना चाहूंगा कि सकरा विधान सभा में एक–एक प्रखंड में हजारों की तादाद में जंगली सूअर हैं तो अगर एक वर्ष में 124 मारे जायेंगे तो भरपाई तो नहीं हो पायेगी तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है, निवेदन है कि उसकी जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था कराई जाय और वहां शूटर की व्यवस्था कराई जाय ।

टर्न–5/यानपति/03.02.2026

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यह भी जानकारी होनी चाहिए और उत्तर में यह लिखा हुआ है, शायद यह सदन को नहीं बता पाए कि आखेट करने के लिए जो भी व्यक्ति हैं उनकी सूची बाजाप्ते जिलाधिकारी, मुखिया के पास दिया गया है और जो किसान लिखित देंगे कि यहां इसके कारण, घोड़पड़ास के कारण फसल नुकसान हो रहा है तो मुखिया स्वतंत्र हैं आखेट करने के लिए और एक घोड़पड़ास को आखेट

करने के लिए 750 रुपये की राशि उनको स्वीकृत है और 1250 रुपये की राशि उनको दफनाने के लिए स्वीकृत है और साथ–साथ जंगली सूअर को आखेट करने के लिए 750 रुपये और दफनाने के लिए 750 रुपये और यदि माननीय सदस्य हजारों एकड़ में कह रहे हैं तो उसकी सूची दें और वन विभाग प्रति हे0 50 हजार रुपये सहायता राशि भी किसान को देने के लिए तैयार है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य का पहले हो जाय ।

श्री आदित्य कुमार : महोदय, मैं सूची उपलब्ध करवा दूंगा और यह भी कहना है कि वर्ष–2024 से 2025 में मात्र 124 नीलगाय की हत्या कराई गई सरकार के आदेश के अनुसार लेकिन वह पर्याप्त नहीं है ।

अध्यक्ष : बैठिए । इस संदर्भ में राज्य के सभी पंचायतों के मुखिया को सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है, आखेट करने वाले की लिस्ट भी वहां पर है । निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा कि आप अपने मुखिया से संपर्क करके और माननीय सदस्य ने कहा है कि ऐसी स्थिति जहां पर है, आपने बताया है, संज्ञान में दिया है और आज यह निश्चित तौर पर जाकर समीक्षा कर लेंगे और जो नुकसान हुआ है उसकी सरकार भरपाई भी करेगी ।

श्री अजय कुमार : महोदय, यह बहुत गंभीर मसला है । हमारा बिहार कृषि प्रधान राज्य है और हमारे कृषि पदाधिकारी क्या कर रहे हैं । कृषि पदाधिकारी जिनको हम नियुक्त किए हैं या प्रखंड कृषि पदाधिकारी वह क्या कर रहे हैं । जिस प्रखंड में नीलगाय या नील बकरी, घोड़पड़ास फसल को नष्ट कर रहा है क्या उसकी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं । एक–एक अंचल में, पूरा–पूरा अंचल प्रभावित है तो हम समझते हैं कि एक–दो किसान की जो लिस्ट मांग रहे हैं सरकार के स्तर से वह इसकी सूची तैयार करके, इसके लिए सरकार के पास कोई ठोस योजना है या नहीं यह मौखिक बात से नहीं होगा कि मुखिया को दिया जायेगा वह करेगा, वह अलग सवाल है, एक्जेक्यूशन सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए, यह अपने हाथ में रखेगी या नहीं यह सवाल है ?

श्री रणविजय साहू : महोदय, सरकार के द्वारा जो पॉलिसी बनाई गई है वह पॉलिसी नीचे में लागू नहीं है । हमारे क्षेत्र में ही नहीं उत्तर बिहार के सभी क्षेत्रों में यही हाल है, किसान बेहाल हैं, हमलोग सड़क से गुजरते हैं, कहीं–कहीं नीलगाय सड़कों पर आ जा रही है, लोग एक्सिडेंट कर जा रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो जा रही है इसलिए सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इसकी कोई ठोस पॉलिसी, ठोस नीति लागू करनी चाहिए ताकि इस समस्या से निजात मिल सके ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, चाहे उत्तरी बिहार हो, दक्षिणी बिहार हो बड़े पैमाने पर घोड़पड़ास से किसानों को परेशानी है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि मुखिया को जिम्मेदारी मिली है यह बात सत्य है महोदय कि पूरे बिहार के एक भी मुखिया को यह जानकारी नहीं है कि उसको मारने के लिए किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है । माननीय मंत्री जी को अखबार के माध्यम से पूरे बिहार को बताना चाहिए और कृषि मंत्री भी यहां बैठे हैं यह निर्णय वन एवं पर्यावरण के बदले कृषि विभाग की यह जिम्मेदारी बनती है कि इसमें हमलोग कौन सा यंत्र, दुनिया में बहुत सारे यंत्र आ रहे हैं उसकी ध्वनि से किसान के खेत में वह भाग रहा है उसकी भी कृषि विभाग को जिम्मेदारी लेनी चाहिए ।

अध्यक्ष : विषय आ गया ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, किसान की जो क्षति हो रही है कृषि विभाग उसकी जिम्मेदारी ले कि उसकी कितनी फसल बर्बाद हुई है और बी0ए0ओ0 उसको वेरिफाई करके उसको मुआवजा दें ।

अध्यक्ष : कुंदन जी, संक्षेप में बोलिए, विषय आ गया है ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, शूटर की कमी है, उसकी व्यवस्था की जाय । इन्होंने बताया है कि प्रक्रिया क्या है, इतने रुपये देना है दूसरा यह कहते हैं फसल मुआवजा का भी प्रावधान है, किसानों को पता नहीं है, मंत्री जी को बताना चाहिए अभीतक कितने लोगों को मुआवजा दिया गया है ।

अध्यक्ष : उसका उपाय किया जा रहा है, जल्दी ही विज्ञापन निकाला जायेगा । पटेल जी, आप बोल लीजिए ताकि एक बार जवाब हो जायेगा । आप बोलिए ।

श्री सिद्धार्थ पटेल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पहले भी आया था और हम घोड़पड़ास की समस्या से आक्रांत हैं । हमारे वैशाली की तरफ भी किसानों की यह मांग थी तो पिछले सत्र में हमलोगों ने यह मांग रखी थी, सरकार की तरफ से यह जवाब आया था कि मुखिया को यह अधिकार दिया गया है कि वह लिखकर वन विभाग के पदाधिकारी को देंगे और उसके बाद वह शूटर बहाल करके उसको मारने की व्यवस्था करेंगे । वैशाली में काफी संख्या में घोड़पड़ासों को मारा गया और उसको दफनाया गया । एक निवेदन माननीय मंत्री जी से है कि मुआवजा देने की व्यवस्था जो की गई है उसको करवाया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों की चिंता उचित है और यह बिहार के लिए निश्चित तौर पर एक गंभीर विषय है । पूर्व कृषि मंत्री के नाते हमने भी इसपर कई विभागों से, जुड़े हुए विभागों को लेकर बैठक भी किए थे और अभी वर्तमान कृषि मंत्री जी से हमने कहा कि इसको एग्रिकल्चर विभाग, ठीक बोले नेता विपक्ष की ओर से

पूर्व कृषि मंत्री जी कि एग्रिकल्चर मिनिस्टर इसको गंभीरता से लें । सदन के माध्यम से मेरा एक आग्रह है कि हम नीलगाय शब्द का उपयोग न करें क्योंकि उससे एक भावना जुड़ती है, हम घोड़पड़ास, नील बकरी इन शब्दों का ही प्रश्न में और जवाब में उपयोग करें क्योंकि कहीं–न–कहीं उसके कारण उसकी वृद्धि और संरक्षण में लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं तो यह आग्रह है कि आपकी तरफ से एक निर्देश जाना चाहिए, आसन से महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बात आ गई है ।

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य को यह जानकारी होनी चाहिए कि वन विभाग में उसको घोड़पड़ास की संज्ञा दी जाती है । नीलगाय नहीं घोड़पड़ास इसलिए हमारे जवाब में भी घोड़पड़ास है ।

अध्यक्ष : तिवारी जी, आप बोलिए ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में माननीय मंत्री जी ने जो भी जवाब दिया है सदन में उसमें एक विषय, एक प्रश्न उठता है कि क्या मुखिया के द्वारा यदि आखेट कराया गया है और आजकल जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि उसके पैसे का भुगतान नहीं हुआ और उसके कारण मुखिया लोग कहते हैं कि हम यह काम नहीं करायेंगे । उस स्थिति में सरकार कौन सा ऐक्शन प्लान लेगी इसको कराया जाय । दूसरी बात कि आम आदमी को पता ही नहीं है कि किसको सूचना देनी है तो उसके लिए कोई हेल्पलाईन नंबर जारी हो, इस हेल्पलाईन नंबर पर एक आम किसान भी, अपने खेत में से और उसपर कंप्लेन दर्ज कराए । यह बहुत बड़ा विषय है माननीय अध्यक्ष महोदय । इसपर माननीय मंत्री जी का स्पष्ट मंतव्य आए तो अच्छा है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यों का सुझाव आया है । सरकार समीक्षा करे इस विषय को और निश्चित तौर पर इस समस्या के निदान का प्रयास करे ।

टर्न–6 / मुकुल / 03.02.2026

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–20, श्री आलोक कुमार सिंह (क्षेत्र सं0–210 दिनारा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : उत्तर स्वीकारात्मक ।

उत्तर कंडिका–(2) एवं (3)

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अभिभाषण एवं सात निश्चय–3 के अंतर्गत राज्य के वैसे प्रखंड, जहां पूर्व से महाविद्यालय संचालित नहीं है, उन प्रखंडों में महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । इस क्रम में विभागीय पत्रांक–40,

दिनांक–14.01.2026 द्वारा राज्य के सभी जिला पदाधिकारी से भूमि की उपलब्धता के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई है ।

श्री आलोक कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आया है लेकिन दिनारा विधान सभा में और रोहतास जिला के अगल–बगल में कई जगहों पर डिग्री कॉलेज की कमी है । राज्य में 534 प्रखंड में 398 प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है तो क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताना चाहेंगे कि दिनारा विधान सभा में जो उनका उत्तर आया है कि जिला अधिकारी को मैंने पत्र लिखा है और उस पत्र से हमलोग कार्य कर रहे हैं लेकिन दिनारा विधान सभा के अगल–बगल में डुमरावं, कराकाट, करहगर तमाम विधान सभा में हर प्रखंड में महाविद्यालय डिग्री कॉलेज नहीं है तो कब तक दिनारा विधान सभा में डिग्री कॉलेज खोलने की व्यवस्था की जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने पूर्व में भी डिग्री कॉलेज के संबंध में जो सरकार की नीति है उसका जिक्र किया है कि हमलोग चरणबद्ध तरीके से उसको पूरा करेंगे, 213 जगहें तो और भी बातें हमने कही हैं और निश्चित रूप से माननीय सदस्य आश्वस्त रहें कि उनके क्षेत्र को भी टेकअप किया जायेगा और यह सरकार की जो नीति है कि उन्नत शिक्षा, उज्ज्वल भविष्य उसके तहत हमलोग उस पर निश्चित रूप से तेजी से काम करेंगे ।

डॉ0 रामानन्द यादव : अध्यक्ष महोदय, सीरियल नम्बर–21 में मेरा नाम है, आपके यहां ऑर्डर पेपर भी है, इसको देख लिया जाए । ऐसी गलती करने वाले पर कार्रवाई की जाए ।

अध्यक्ष : ठीक है । हम इसको दिखवाते हैं । माननीय सदस्य, निश्चित तौर पर गलत हुआ है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–21, श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता (क्षेत्र सं0–11 सुगौली)</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना पूरक प्रश्न पूछ लीजिए ।

माननीय मंत्री जी आप जवाब बता दीजिए ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड–1 एवं 2 उत्तर स्वीकारात्मक।

खंड–3 वर्तमान वर्ष में इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां यह बड़ी आस्था का प्रश्न है, हमारा आपसे यही आग्रह है कि उस राशि को बढ़ाया जाय । मंत्री जी, उसके लिए कुछ जगह बनाइये ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अगर कोई प्रस्ताव आयेगा तो विभाग उसपर विचार करेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप लिखकर प्रस्ताव दे दीजिए ।

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हम लिखकर माननीय मंत्री जी को प्रस्ताव दे देते हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या–22, श्रीमती बेबी कुमारी (क्षेत्र सं0–91, बोचहां)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार, पटना के अंतर्गत वर्तमान में दो राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान, मुजफ्फरपुर जिला में संचालित है यथाः–

1–राजकीय पॉलिटेक्निक, मुजफ्फरपुर (नया टोला, तकनीकी चौक, मुजफ्फरपुर)

2–राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, मुजफ्फरपुर (बेला रोड, नारायणपुर, अनंत, मुजफ्फरपुर)

यह दोनों संस्थान मुसहरी प्रखंड में अवस्थित है। राजकीय पॉलिटेक्निक, मुजफ्फरपुर की प्रवेश क्षमता 390 एवं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, मुजफ्फरपुर की प्रवेश क्षमता 360 है। इन संस्थानों में जिले के अन्य प्रखंडों के छात्र–छात्राएं भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर नामांकन ले सकते हैं। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत बोचहां विधान सभा क्षेत्र में राजकीय पॉलिटेक्निक स्थापित करने का प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप अपना पूरक प्रश्न पूछें ।

श्रीमती बेबी कुमारी : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आया है लेकिन यह पॉलिटेक्निक कॉलेज नगर में है, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि बोचहां विधान सभा में एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है तो काफी बच्चों को तकनीकी पढ़ाई में बहुत कठिनाई होती है । हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि बोचहां में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज देने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने अनुरोध किया है, उसपर हम आवश्यकतानुसार विचार करेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या–23, श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र सं0–20, चिरैया)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि विद्यालय में वर्तमान में 02 वर्ग कक्ष अच्छी स्थिति में है, जिसमें पठन–पाठन संचालित है ।

BSEIDC से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विद्यालय में कुल–06 (2+2+2) वर्ग कक्ष तथा चहारदीवारी कुल–140 फीट का निर्माण कार्य कराने हेतु भूमि उपलब्ध है ।

सरकार के द्वारा ऐसे विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से भवन निर्माण, चहारदीवारी एवं अन्य असैनिक कार्य कराया जा रहा है । वर्ग कक्ष निर्माण एवं चहारदीवारी निर्माण कार्य कराने हेतु प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरान्त उक्त निर्माण कार्य अगले छः माह में करा लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना पूरक प्रश्न पूछें ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस काम को थोड़ा जल्दी करा दिया जाए । वहां पर बच्चों को पढ़ने–लिखने में बहुत दिक्कत होती है, वहां पर रूम थोड़ा बढ़ा दिया जाए, चहारदीवारी हो जाए । माननीय मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद है कि उन्होंने संतोषजनक जवाब दिया है । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या–24, श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र सं0–75, सहरसा)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि सहरसा कोशी प्रमंडल का मुख्यालय है । राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य के सभी प्रमंडलों में न्यूनतम एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है । कोशी प्रमंडल में बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा स्थापित है, जो वर्तमान में संचालित है । संप्रति सहरसा में अलग से विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जवाब प्राप्त हुआ है । सहरसा मुख्यालय के बजाय मधेपुरा में यूनिवर्सिटी की स्थापना की गयी है लेकिन लगातार सहरसा के लोगों के द्वारा, संगठनों के द्वारा जन–आंदोलन होते रहे हैं कि सहरसा में विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए । क्या सरकार विचार कर सकती है कि एक और यूनिवर्सिटी सहरसा के मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में निर्माण हो सकता है । दूसरा यह है कि अगवानपुर में वहां एक कृषि महाविद्यालय है, इस कृषि महाविद्यालय को कृषि यूनिवर्सिटी में हमलोग कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, यह मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अपनी मांग रखी है अलग से विश्वविद्यालय स्थापना करने की फिलहाल तो उसपर विचार नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय खोलने के लिए बहुत सारी प्रक्रियां हैं, वर्तमान में स्टेट यूनिवर्सिटीज 15 हैं इनको हमलोग सही तरीके से संचालित कर रहे हैं और साथ ही साथ जब डिग्री कॉलेज हरेक प्रखंड में खुल जायेगा तो जो दूरी थी बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए तो वह भी कम हो जायेगी तो तत्काल विचाराधीन नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने कितना स्पष्ट जवाब दिया है कि विचार किया जायेगा, पहले प्रखंड में खुलने दीजिए ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा जी ने सहरसा में विश्वविद्यालय खोलने के लिए शिलान्यास किया था और हमें लगता है कि वहां दो निजी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज भी हैं और वह सहरसा मुख्यालय में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, डिग्री कॉलेज कब खुलेगा, न खुलेगा वहां एम0एल0टी0 कॉलेज है जिसमें स्थापना शिलान्यास किया गया था, इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी वहां पर मौजूद है, आप स्वीकृति दे देंगे तो खुल सकता है ।

तारांकित प्रश्न संख्या–25, श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र सं0–207, चेनारी)

(लिखित उत्तर)

सुश्री श्रेयषी सिंह, मंत्री : अस्वीकारात्मक ।

जिला पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक–26, दिनांक–31.01.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि

1. चेनारीः– चेनारी प्रखंड अंतर्गत स्वामी आत्म विवेकानंद महार उच्च विद्यालय, रेडिया में स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

2. शिवसागरः– शिवसागर प्रखंड अंतर्गत शिवसागर और रायपुर चोर में स्टेडियम का निर्माण किया गया है ।

3. रोहतासः– रोहतास प्रखंड के तुम्बा में स्टेडियम निर्माणाधीन है ।

4. नौहट्टाः– नौहट्टा प्रखंड अंतर्गत उल्लहीबनाही में स्टेडियम बना हुआ है ।

इस खंड का उत्तर कंडिका–02 में सन्निहित है ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : अध्यक्ष महोदय, जवाब प्राप्त है । इसमें हमने दिया था, अपने विधान सभा के चार प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण का, जिसमें जवाब आया हुआ है कि चारों प्रखंड में स्टेडियम निर्माण है लेकिन सिर्फ क्या चहारदीवारी का निर्माण कर देने से स्टेडियम बन जाती है । महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां पर सिर्फ चहारदीवारी है और जवाब में आया है कि चारों प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

सुश्री श्रेयषी सिंह, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, चहारदीवारी की जो योजना है उसको निश्चित रूप से रिवाइज किया जा सकता है । विशेषकर मुझे लगता है कि इनका प्रखंड जो शिवसागर प्रखंड है उसमें मुख्यमंत्री खेल विकास योजनांतर्गत 2009 में स्टेडियम बना था तो निश्चित रूप से वहां पर जीर्णोद्धार किया जा सकता है और माननीय सदस्य की क्या आवश्यकता है, अगर वे स्पेसिफिक रूप

से बताने का कष्ट करेंगे तो निश्चित रूप से खेल विभाग करने का काम करेगा।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : अध्यक्ष महोदय, 2009 में जो स्टेडियम बना चाहरदीवारी सिर्फ हुई है और आजतक उसमें मिट्टीकरण का कार्य नहीं किया गया है । हर वर्ष हमलोग देखते हैं कि जब भी खेल होता है या बच्चे खेलने जाते हैं काफी गडढ़ा है, पानी लगा हुआ है, बच्चों का पैर मुचक जाता है, टूट जाता है तो इस तरह की काफी परेशानियां होती हैं । अगर स्टेडियम का निर्माण करना है तो उसमें मिट्टीकरण होनी चाहिए, पानी के निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए । हमारे विधान सभा के अंतर्गत किसी भी प्रखंड में जहां भी स्टेडियम का निर्माण हुआ है सिर्फ चाहरदीवारी कर दी गई है उसके अलावा वहां कोई व्यवस्था नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप वहां पर जन सुविधा, मतलब मैदान तो है, चाहरदीवारी है, ट्रैक होना चाहिए, शौचालय होनी चाहिए, रोशनी की व्यवस्था हो, पीने के पानी का प्रबंध हो, खिलाड़ियों के रहने के लिए वहां पर व्यवस्था हो । इन सारी चीजों को सुनिश्चित करने के लिए नीति बना लीजिए । खेलो इंडिया के तहत भारत सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्रीजी ने, बिहार में बहुत अच्छा खेल हुआ था और बिहार सरकार की प्राथमिकता भी है । वर्ल्ड लेवल का नालंदा में महिला हॉकी चैम्पियनशिप हुआ था । सरकार की प्राथमिकता में है, माननीय मंत्रीजी, एक बार बता दीजिए ।

सुश्री श्रेयषी सिंह, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, चेनारी विधान सभा अंतर्गत चार प्रखंड है । चेनारी प्रखंड में 24.11.2025 को स्वामी आत्मा विवेकानंद महार उच्च विद्यालय में स्टेडियम निर्माण कार्य प्रगति पर है यानी ऑन गोइंग कार्य है । जिसमें जिस व्यवस्था की आवश्यकता माननीय सदस्य बता रहे हैं उसमें उन सभी चीजों की व्यवस्था की जायेगी । निश्चित रूप से 24.11.2026 तक यह कार्य भी संपन्न किया जायेगा । शिव सागर प्रखंड के बारे में मैंने बताया कि विभाग संवेदनशील है कि अगर 2009 में कोई स्टेडियम बना था तो उसमें बाउंड्री बना था, मंच बना था साथ ही स्टैंड बना था । अगर आज जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है तो निश्चित रूप से जीर्णोद्धार किया जा सकता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, रोहतास प्रखंड की यदि बात करें तो फुटबॉल स्टेडियम जो कि 07.05.2026 में जिसका वर्क अलॉट हुआ है 27.05.2026 में तो कंप्लीट होना है, तो यह ऑन गोइंग प्रोजेक्ट जो है उनका तो माननीय सदस्य खुद ही जाकर निरीक्षण कर सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मिथुन कुमार ।

तारांकित प्रश्न संख्या–26, श्री मिथुन कुमार (क्षेत्र सं0–158, नाथनगर)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : 1. उत्तर अस्वीकारात्मक ।

2. एवं 3. वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिला अंतर्गत जगदीशपुर प्रखंड में तेजनारायण बनैली महाविद्यालय, जगदीशपुर, सुन्दरवती महिला महाविद्यालय, जगदीशपुर, मारवाड़ी महाविद्यालय, जगदीशपुर, भागलपुर नेशनल महाविद्यालय, जगदीशपुर एवं तेजनारायण बनैली विधि महाविद्यालय, जगदीशपुर एक अंगीभूत महाविद्यालय के रूप में संचालित है ।

उक्त प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना पूरक प्रश्न पूछ लीजिए । हालांकि इस संदर्भ में सब विषय आ चुका है, अगर कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं ।

श्री मिथुन कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो उत्तर दिया गया है, वह भागलपुर जिलान्तर्गत सभी डिग्री कॉलेज आते हैं, जैसा कि सरकार का सुझाव है कि हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए तो इस उत्तर से हम असंतुष्ट हैं तो क्या माननीय मंत्री महोदय बताना चाहेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने अपने उत्तर में स्पष्ट लिखा है कि भागलपुर जिला अंतर्गत जगदीशपुर प्रखंड में तेजनारायण बनैली महाविद्यालय, जगदीशपुर, सुन्दरवती महिला महाविद्यालय, जगदीशपुर, मारवाड़ी महाविद्यालय, जगदीशपुर, भागलपुर नेशनल महाविद्यालय, जगदीशपुर एवं तेजनारायण बनैली विधि महाविद्यालय, जगदीशपुर एक अंगीभूत महाविद्यालय के रूप में संचालित है ।

उक्त प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

तत्काल कोई योजना नहीं है वहां खोलने की और जहां महरूम है जो ऐसे प्रखंड जहां है ही उनको हमलोग पहले लेंगे ।

टर्न–7 / अभिनीत / 03.02.2026

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायं । अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएंगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–3 फरवरी, 2026 के लिए माननीय सदस्य श्री अरूण सिंह से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । आज दिनांक–3 फरवरी, 2026 को सदन में वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए

आय–व्ययक का उपस्थापन एवं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद–विवाद निर्धारित है ।

अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम 6(3) एवं 47(2) के तहत् नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, इसको पढ़वा दिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है, पढ़ दीजिए ।

श्री अरूण सिंह : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम–98 के अंतर्गत मैं सदन का ध्यान एक अत्यंत गंभीर, तात्कालिक एवं जनहित से जुड़े विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं तथा इस विषय पर चर्चा हेतु सदन की समस्त कार्यसूचियों को स्थगित कर बहस कराए जाने की मांग करता हूँ ।

सदन अवगत है कि जहानाबाद जिले के पतियामा गांव तथा औरंगाबाद जिले की नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ पटना के शंभू एवं क्रमशः परफेक्ट हॉस्टल में बलात्कार एवं हत्या जैसी जघन्य घटनाएँ घटित हुई हैं । ये घटनाएँ राज्य में महिलाओं एवं छात्राओं की सुरक्षा, कानून–व्यवस्था तथा पुलिस–प्रशासन की गंभीर विफलता को उजागर करती है, यह अत्यंत चिंताजनक है कि शुरू से ही पुलिस एवं प्रशासन का रूख इन मामलों में नकारात्मक रहा है। पुलिस–प्रशासन पर इन जघन्य अपराधों को दबाने, बलात्कार–हत्या की घटनाओं से इनकार करने तथा इनमें शामिल प्रभावशाली एवं रसूखदार व्यक्तियों को बचाने के गंभीर आरोप लगे हैं । जनांदोलनों और व्यापक जनदबाव के बाद ही राज्य सरकार को सी0बी0आई0 जांच की अनुशंसा करनी पड़ी है, किन्तु न्याय की निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए मात्र सी0बी0आई0 जांच की अनुशंसा पर्याप्त नहीं है । आवश्यक है कि यह जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी सीटिंग जज के निर्देशन एवं निगरानी में कराई जाए तथा जांच के लिए एक निश्चित समय–सीमा निर्धारित की जाए ताकि पीड़ित परिवारों को शीघ्र न्याय मिल सके और मामलों को लंबित रखने की प्रवृत्ति पर रोक लगे ।

अतः छात्राओं की सुरक्षा एवं न्याय सुनिश्चित करने के लिए इन मामलों की न्यायालय के प्रत्यक्ष निर्देशन में समयबद्ध जांच, निजी हॉस्टलों की निगरानी हेतु एक प्रभावी नियामक संस्था के गठन तथा सरकारी छात्रावासों को शीघ्र खोलने जैसी ज्वलंत मांगों पर सदन का कार्य स्थगित कर विस्तृत बहस कराए जाने की मांग की जाती है ।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिये जाएंगे ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, बहुत ही गंभीर विषय है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको हमने पढ़ने का अवसर दिया है । सरकार ने संज्ञान लिया है ।

(व्यवधान)

अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

श्री राहुल कुमार : महोदय, बच्चियों का मामला है, विशेष बहस के लिए सरकार से अनुरोध कर रहे हैं । कम–से–कम विशेष बहस करा दीजिये ।

अध्यक्ष : सरकार ने संज्ञान लिया है, सरकार कार्रवाई भी कर रही है ।

श्री राहुल कुमार : महोदय, सरकार जब कार्रवाई कर ही रही है तो विशेष चर्चा से क्या दिक्कत है। सरकार इसमें बताये कि क्या कर रही है ? हमलोग भी बतायेंगे कि सरकार कहां गलत कर रही है ।

अध्यक्ष : सूचना अमान्य कर दिया गया है, उसके बाद भी मैंने पढ़ने का अवसर दिया है। सरकार ने संज्ञान लिया है ।

श्री राहुल कुमार : महोदय, ठीक है लेकिन आपके सरंक्षण की आवश्यकता है । विपक्ष के लोग हैं आपके संरक्षण की आवश्यकता है । आपसे विशेष आग्रह है कि सरकार को आप निर्देशित करें कि इस पर विशेष चर्चा कराये ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, सरकार को इसे संज्ञान में लेने के लिए कहा जाय और इस पर विशेष बहस कराने के लिए कहा जाय ।

अध्यक्ष : आपका विषय सरकार के संज्ञान में आ गया है । विश्वास कीजिए, निश्चित कार्रवाई होगी । अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

शून्यकाल

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला अंतर्गत केवटी विधान सभा क्षेत्र के सिंघवाडा प्रखण्ड के पंचायत–हरपुर के फतेहपुर में बागमती नदी में हर वर्ष बाढ़ आने के कारण मिट्टी का कटाव अधिक होता है, जिसे रोकने के लिए प्रोटेक्शन वॉल अति आवश्यक है। जनमानस के हित को देखते हुए यथाशीघ्र बनाने की कृपा करें ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक खेत तक किसानों को सिंचाई हेतु बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य को शीघ्र पूरा करने हेतु कार्य में तेजी लाने की मांग करता हूं ।

श्री रणविजय साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, बक्सर जिला के किरनी निवासी पप्पु कुमार साह की 14 वर्षीय पुत्री के साथ दिनांक–17/01/2026 को दबंगो द्वारा दुष्कर्म किया गया, जिसका महिला थाना कांड सं0–05/26 है।

अतः घटना में शामिल गिरफ्तार अपराधियों की स्पीडी ट्रायल से सजा एवं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग करता हूं ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, पटना जिलांर्तगत दुल्हिनबाजार प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भरतपुरा बनने के बाद प्रखंड मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की मान्यता समाप्त कर दी गई है, जिससे आम जनता को इलाज में भारी कठिनाई हो रही है ।

अतः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुल्हिनबाजार को पुनः संचालित करने की मांग करता हूं ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिलान्तर्गत विभूतिपूर दलसिंहसराय, मोहनपुर, पूसा, मोहिउद्दीननगर सहित 20 प्रखंडों में धान खरीद की स्थिति खराब है । महज 55 प्रतिशत धान खरीद की गई है, जबकि 97,500 मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य 28 फरवरी तक का है ।

मैं सरकार से शेष धान को अविलम्ब खरीदने की मांग करता हूँ ।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है जिस वजह से स्थानीय विद्यार्थी उच्च शिक्षा सह डिग्री लेने से वंचित रह जा रहें हैं ।

अतः सरकार से सोनबरसा बाजार में जनता द्वारा दी गई बेसकीमती जमीन पर डिग्री कॉलेज खोलने की सरकार से मांग करती हूं ।

श्रीमती अनीता देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, नवादा जिलान्तर्गत पकरीवरावाँ बाजार में एस०एच०–8 के किनारे बने नाला में कीचड़ भर जाने से नाला का गंदा पानी सड़क पर जम गया है तथा कई घरों में गंदा पानी घुस गया है जिससे वहाँ के नागरिक काफी परेशान हैं ।

अतः उक्त नाला को यथाशीघ्र साफ करवाने की मांग करती हूं ।

श्री शुभानंद मुकेश : अध्यक्ष महोदय, कहलगांव NTPC में कार्यरत कुशल कामगारों से प्रत्येक छः माह पर नया चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाता है, जिससे प्रक्रियात्मक देरी के कारण उनकी कार्यनिरंतरता भंग होती है ।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि बार–बार प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर केवल प्रथम नियुक्ति के समय ही प्रभावी बनाया जाय ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली प्रखण्ड में अवस्थित माँ नकटो भवानी मंदिर, देवीगंज के पर्यटकीय विकास हेतु सांस्कृतिक कैलेंडर में शामिल करते हुए प्रति वर्ष 01 जनवरी को नकटो महोत्सव सरकारी स्तर पर आयोजित करने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, बेहतर कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास, समय और ईंधन की बचत एवं व्यापार में सुगमता हेतु 500.89 करोड़ रुपये के लागत से सारण एवं मुजफ्फरपुर जिला सीमा पर अवासित चंचालिया (तरैया) तथा फतेहाबाद (पारू) दियारा में बन रहे महासेतु चंचलिया दियारा पहुँच पथ को जनहित में राज्य उच्च पथ–104 तरैया से जोड़े ।

टर्न–8 / सुरज / 03.02.2026

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कुढ़नी प्रखंड में एस0डी0पी0ओ0 का अपना भवन नहीं है जो तुर्की थाना में चलता है । मैं सरकार से कुढ़नी थाना के पीछे अवस्थित सरकारी जमीन में भवन बनाने की मांग करता हूं ।

श्री विनय कुमार चौधरी : अध्यक्ष महोदय, दरभंग जिला के बहेड़ी प्रखंड के जुरिया में नया प्राथमिक विद्यालय सृजित हो ।

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी : अध्यक्ष महोदय, दिनांक–02 फरवरी 2026 को आयोजित हुई बिहार इंटरमीडिएट–2026 की परीक्षा में अल्प समय की देरी से पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा में शमिल होने से वंचित कर दिया गया है ।

अतः आग्रह होगा कि सरकार वैसे सभी परीक्षार्थियों (वंचित) को एक अवसर देते हुए पुनः परीक्षा आयोजित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना चाहेंगे ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया में निराश्रित गोवंश के कारण सड़क दुर्घटनाएं, फसल क्षति एवं जन सुरक्षा की गंभीर समस्या बराबर बनी रहती है ।

अतः मैं सरकार से पूर्णिया में गोवंश के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु गोवंश संरक्षण केन्द्र स्थापित करने की मांग करता हूं ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के कल्याणपुर विधान सभा सहित सम्पूर्ण जिला में 52271 हेक्टेयर में अतिवृष्टि से धान के फसल क्षति की विस्तृत रिपोर्ट जिला पदाधिकारी ने सरकार को भेजा है ।

कृषकों के फसल क्षति के शीघ्र भुगतान हेतु कृषि इनपुट स्वीकृत करने हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्री मो0 मुर्शीद आलम : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट प्रखंड के महलगांव ग्राम पंचायत के बकरा नदी पर अवस्थित करहरा पुल वर्ष–2017 में आयी भीषण बाढ़ से ध्वस्त हो गया है ।

अतः उक्त पुल का निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री कलाधर प्रसाद मंडल : अध्यक्ष महोदय, प्रखंड–बड़हरा कोठी, जिला–पूर्णियां अंतर्गत बाबा बरूणेश्वर स्थान बहुत ही ऐतिहासिक धर्मस्थली है, जहां पूरे बिहार एवं अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं का आना–जाना लगा रहता है ।

अतः उक्त बाबा स्थान को पर्यटन स्थल बनाने की मांग करता हूं ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला संचालन समिति के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत अनुशंसित क्रमांक 3, 4 एवं 5 पर अंकित बिक्रमगंज प्रखंड के कंडाडीह, घोषियाकला ग्राम के मल्लाह मुहल्ला एवं सिकरिया नगर परिषद् क्षेत्रांतर्गत काव नदी पर पुल का निर्माण कार्य कराने की सदन के माध्यम से मांग करता हूं ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, बिहपुर विधान सभा अंतर्गत बिहपुर प्रखंड के अमरपुर गांव में उत्क्रमित उच्च मा0 वि0 में आने–जाने के लिए बच्चों को रास्ता नहीं है।

अतएव यथाशीघ्र विद्यालय में जमीन अधिग्रहण का रास्ता बनवाए जाने की मांग सरकार से करता हूं ।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं लिये जायेंगे ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उस पर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री मंजीत कुमार सिंह, जनक सिंह एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (स्वास्थ्य विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मंजीत कुमार सिंह अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक जिला में मेडिकल कॉलेज की स्थापना नीति के अनुरूप दिनांक–05.09.2023 को कैबिनेट की बैठक में गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी और इसके निर्माण के लिए 2 अरब 99 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई थी । साथ ही गोपालगंज मेडिकल कॉलेज को 2025–26 सत्र से शुरू होने वाले मेडिकल कॉलेजों में शामिल किया गया था । पिछले वर्ष समाहर्त्ता, गोपालगंज के पत्रांक–X2-VII-23/2023-1840/रा. दिनांक–25.05.2025 द्वारा अपर मुख्य

सचिव, स्वास्थ्य विभाग, पटना को माँझा प्रखंड के धनखर/उमर मठिया में उपलब्ध 24 एकड़ 37 डि0 सरकारी भूमि पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु प्रस्ताव अनुशंसा के साथ भेजी थी । बावजूद इसके अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है ।

अतएव गोपालगंज जिलावासियों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने के लिए गोपालगंज मेडिकल कॉलेज का निर्माण यथाशीघ्र शुरू करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, समय चाहिये ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

सर्वश्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, केदार प्रसाद गुप्ता एवं चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (कृषि विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ वर्तमान में करोड़ों किसान ले रहे हैं । इस योजना के कार्यान्वयन हेतु आवेदक का पात्रता निर्धारण के लिए उसका नाम सरकारी रजिस्टर में जमीन विवरणी सहित दर्ज होना चाहिए था, लेकिन इस संबंध में कोई अपेक्षित निर्णय नहीं लिया गया और मनमाने ढंग से आवेदक का चयन कर योजना का लाभ दिया जा रहा है । वर्तमान में इस योजना अंतर्गत लाभुकों की संख्या में फार्मर आई0डी0 जेनरेट नहीं होने के कारण लाभार्थी की संख्या में भारी कमी होने जा रही है ।

अतः अत्यंत लोकहित में वर्तमान में किसान निधि सम्मान योजना पा रहे सभी किसानों को भविष्य में इस लाभ को अनवरत प्रदान किए जाने हेतु उनका नाम सरकारी रजिस्टर में दर्ज करने के लिए सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री रामकृपाल यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण दिया है । मैं आपके समक्ष सदन को कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है । इसका कानून भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के आलोक में किया जाता है । इस योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार योजना का लाभ उन्हीं किसान परिवारों को देय है जिनके स्वंय के नाम से जमाबंदी है । वर्तमान में भारत सरकार के दिशा–निर्देश के आलोक में राज्य के सभी पी0एम0 किसान के लाभार्थी का फार्मर रजिस्टर तैयार किया जाना है । राज्य के सभी जिलों के सभी अंचलों में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य विशेष अभियान चलाकर कृषि विभाग द्वारा तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्य किया जा रहा है ।

इस कार्य के लिये तृतीय चरण का विशेष अभियान दिनांक–02.02.2026 से दिनांक–06.02.2026 तक जारी है । इसमें कृषि विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पदाधिकारी/कर्मी सम्मलित रूप से कार्य कर रहे हैं । अब तक पी0एम0 किसान के किसी भी लाभार्थी को फार्मर आई0डी0 नहीं बनाने के कारण इस योजना के लाभ से वंचित नहीं किया गया ।

(क्रमशः)

टर्न–9/धिरेन्द्र/03.02.2026

....क्रमशः.....

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : महोदय, वैसे किसान जिनकी जमाबंदी उनके पूर्वजों के नाम पर है, उन सभी किसानों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से स्वयं के नाम से जमाबंदी हस्तांतरित कराने तथा उसके उपरांत फार्मर आई॰डी॰ बनाये जाने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार भी किया जा रहा है । साथ ही, ऐसे लाभुकों का कार्य प्राथमिकता के आधार पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा करते हुए फार्मर आई॰डी॰ बनाया जा रहा है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के अंतर्गत जो ऑपरेशनल गाइडलाईन बना था, उसके अंतर्गत लाभुक का चयन किया गया लेकिन जो गाइडलाईन बना था, उसके क्लॉज 5. 3 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि Benefit will be allowed in those cases where transfer of ownership of cultivable land takes place on account of succession due to death of the landowner. However, those eligible farmers whose names have been entered in the land record after 01.12.2018 till 01.02.2019 shall be eligible for the benefits from the date of entry of land rights in the land records. In such cases where, transfer of ownership of cultivable land has happened due to any reason which could be purchase, succession, will, gift, etc., between 01.12.2018 and 31.01.2019, the installment pertaining to the 4-monthly period/trimester December, 2018 - March, 2019 during the financial year (2018-19) shall be proportionate amount from date of transfer till 31.03.2019 with respect to the 4 months period.

अब ये कह रहे है कि लाभ दिया जा रहा है, ठीक है । हम यह कह रहे हैं कि फार्मर को आगे लाभ नहीं मिलने की संभावना है, ये जिस प्रकार से आई॰डी॰ जनरेट करा रहे हैं तो एक समय–सीमा, जैसा ये बता रहे हैं कि इन्होंने शुरू कराया है तो इसकी क्या समय–सीमा है ? पहले तो आई॰डी॰ जनरेट नहीं हुआ, किसानों को सीधे लाभ दे दिया गया, अब आई॰डी॰ जनरेट कर किसानों को लाभ दिया जायेगा तो जिस फार्मर के नाम पर जमीन नहीं

होगा, जो लैंड ऑनर नहीं होगा, उसको कैसे लाभ दे पायेंगे ? हम यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं । इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी जुड़ा हुआ है । हम स्पष्ट रूप से चाहेंगे कि कितने दिनों के अंदर किसानों को आई॰डी॰ जनरेट कर दिया जायेगा ताकि सभी फार्मर को लाभ मिलेगा चूंकि यह मुद्दा पूरे बिहार का मुद्दा है, सभी जगह यह प्रॉब्लम है और सभी किसानों को जिनके नाम पर जमीन नहीं है, जिनके बाप–दादा के नाम पर जमीन है या जो बटाई लिये हुए हैं और उनको भी किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है उनको लाभ नहीं मिलने की संभावना है तो मंत्री जी इसको जरा स्पष्ट कराना चाहेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : महोदय, साफ तौर पर मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ । उन्होंने सही कहा कि पूरे बिहार के किसानों की नजर है सरकार पर । बिहार में अभी तक का जो प्रोग्रेस हुआ है उसकी जानकारी मैं आपके माध्यम से सदन को देना चाहता हूँ । बिहार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वर्तमान में 73 लाख 37 हजार 270 किसानों को सम्मान निधि के योजना का लाभ मिल रहा है । प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी तक कुल 21 किश्त जारी हुए हैं, इसमें 30,093 करोड़ रुपये की राशि किसानों के खाते में भेज दी गयी है । वर्तमान में भारत सरकार की जो एग्री स्टॉक योजना के अंतर्गत राज्य के सभी रैयत किसानों का फार्मर आई॰डी॰ बनाया जाना है इसके लिए कृषि विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग संयुक्त रूप से प्रयास कर रही है कि हम प्रत्येक गांव में कैम्प लगाकर फार्मर आई॰डी॰ बनाये । लगातार अभियान चल रहा है, अभी तक कुल 31 लाख 12 हजार 581 किसानों का फार्मर आई॰डी॰ बनाया जा चुका है । जिन किसानों के पास जमीन का कागजात उपलब्ध है उनका आई॰डी॰ तुरंत बनाया जा रहा है, जिसके पास कागजात की कुछ समस्या है उसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा विशेष अभियान भी चालने का काम किया जा रहा है ताकि कागजात की जो समस्या है उससे उनको निजात मिल जाय । सभी किसानों का फार्मर आई॰डी॰ बनेगा सरकार इसके लिए दृढ़संकल्प है और मैं सदन के माध्यम से माननीय सदस्य एवं राज्य के तमाम अन्नदाता किसानों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि किसी भी पात्र किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जायेगा । राज्य में विशेष अभियान के तहत 06 जनवरी, 2026 से 11 जनवरी, 2026 तक तथा 17 जनवरी, 2026 से 21 जनवरी, 2026 तक कैम्प लगाया गया है । पुनः 02 फरवरी, 2026 से 06 फरवरी, 2026 तक सभी अंचलों में विशेष अभियान के तहत कैम्प का आयोजन किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के द्वारा बहुत स्पष्ट उत्तर दिया गया है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, मैं आपके माध्यम से....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण में जिन माननीय सदस्यों का नाम है वही बोल पायेंगे ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, मंत्री जी के संज्ञान में भी देना चाहता हूँ कि अभी कई ऐसे किसान सम्मान निधि लेने वाले लोगों का नाम इसमें से कटा है । कई टीचर इसका लाभ ले रहे थे, कई इनकम टैक्स पेयी इसका लाभ ले रहे थे तो पहले इसका रजिस्टर नहीं बना। किन–किन लोगों को इसका लाभ देना था इसका भारत सरकार ने गाइडलाईन बना दिया लेकिन इसमें बिहार सरकार ने स्पष्ट गाइडलाईन नहीं बनाया तो क्या इस बार स्पष्ट रूप से गाइडलाईन ये बनाना चाहते हैं कि जो टीचर्स हैं या फिर इनकम टैक्स पेयी हैं या उस प्रकार के दूसरे लोग हैं जो इस किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं, जिनका नाम छटने से जो हो–हल्ला हंगामा कर रहे हैं, पेपर में आये दिन आ रहा है तो इस पर कोई स्पष्ट नीति सरकार बनाना चाहती है ? मैं जानना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : सरकार का जवाब स्पष्ट आया है कि सरकार के दोनों विभाग किसानों के हित में कृषि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अभियान चला रहा है। 33 लाख किसानों का आई॰डी॰ बन गया है । यह अभियान चल रहा है और मैं समझता हूँ कि जल्द ही इस काम को पूरा किया जायेगा ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, मंत्री जी कितने दिनों के अंदर इस अभियान को पूरा करायेंगे ? एक समय–सीमा निर्धारित कराया जाय ।

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : महोदय, शीघ्र ही यह काम संपन्न हो जाय उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार गंभीर है ।

(व्यवधान)

इस ध्यानाकर्षण में जिनका नाम है वही बोलेंगे ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, किसानों को योजना का लाभ मिले, निरंतर इसका लाभ मिलता रहेगा, इसके लिए माननीय मंत्री इसका कोई समय–सीमा निर्धारित कर दें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी चिंता सही है, सरकार संवेदनशील है । जल्द–से–जल्द काम होगा, सरकार लगी हुई है ।

(व्यवधान)

मैं कहना चाहूंगा कि ध्यानाकर्षण में जिनका नाम है वही बोलेंगे । श्री रजनीश जी का नाम है, आप बोलिये ।

श्री रजनीश कुमार : महोदय, इसमें जो मूल प्रश्न है और हम यह जानना चाहते हैं कि पहले फार्मर आई॰डी॰ क्या कंप्लसरी नहीं था ? पहले जमीन का स्वामित्व किसानों का उनके वंशावली के आधार पर निर्धारित हो जाता था और उन्हें

किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता था । अभी हाल में जो परिवर्तन हुआ है, उसमें फार्मर आई॰डी॰ बनाना है और फार्मर आई॰डी॰ तभी बनेगा जब किसान के अपने स्वयं के नाम पर जमाबंदी कायम रहेगा और बिहार की जो स्थिति है बहुत बड़ा जमीन और बहुत सारे किसान, हम समझते हैं कि उनके दादा–परदादा, पूर्वजों के नाम पर जमीन है यह एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है और माननीय मंत्री जी ने ठीक कहा कि इसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भी लगा हुआ है लेकिन जब तक यह प्रक्रिया बिहार में पूरी न हो जाय कि सभी रैयतों के नाम पर उनका जमाबंदी कायम हो जाय तब तक के लिए क्या सरकार ऐसी व्यवस्था जो पूर्व में थी वंशावली के आधार पर, वह बनाकर रखना चाहती है ? मैं यह जानना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, वाजिब चिंता है । मैं आपको इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो आशंका आपके मन में है उन सारी आशंकाओं को दूर कर के सभी किसानों तक यह लाभ पहुँचे उसके लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी । जितना जल्द हो सके इस पर कार्रवाई करेगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अजय बाबू, आप सिनियर मेंबर हैं । आप जानते हैं कि जिनका नाम ध्यानाकर्षण में होता है उनको पूरक पूछने का अवसर मिलता है ।

अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–10 / अंजली / 03.02.2026

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब वित्तीय कार्य लिये जाएंगे ।

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2026–27 का आय–व्ययक विवरणी सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

महोदय, आपकी अनुमति से में वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए राज्य का वार्षिक आय–व्ययक (बजट) अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

मैं बिहार की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस सरकार को पुनः अपना जनादेश प्रदान किया है, जिससे बिहार को आर्थिक रूप से सशक्त, सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण एवं समावेशी विकास वाला विकसित राज्य बनाने के हमारे संकल्प को नई ऊर्जा मिली है ।

महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रस्तुत केंद्रीय बजट वर्ष 2025–26 में बिहार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना, आई०आई०टी० पटना के विस्तार, खाद्य प्रसंस्करण संस्थान, हवाई अड्डा विकास एवं प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को मिले सहयोग हेतु मैं राज्य की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ । विशेष रूप से पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहन देने हेतु राज्यों को प्रदान की गई ब्याज–मुक्त ऋण सहायता ने बिहार की विकास परियोजनाओं को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सशक्त आधार प्रदान किया है ।

महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व और इतना ही नहीं पांच बड़े चीज, सबसे पहला ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और तब सम्मान, ये पांच तत्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी में जो निहित है, विकसित बिहार, समृद्ध बिहार, ताकतवर बिहार के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा । दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्र सरकार के समक्ष बिहार की बात प्रभावी ढंग से रखने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ । आपके निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, बिहार की प्राथमिकताओं को महत्त्व देते हुए, राष्ट्रीय प्रगति के अनुरूप राज्य को विकास की मुख्यधारा में आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है । यह साझा संकल्प विकसित और आत्मनिर्भर बिहार के लक्ष्य को मजबूती देगा तथा विकसित भारत की यात्रा में बिहार की भूमिका को सशक्त बनाएगा ।

महोदय, एक तरफ जहाँ भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार की आर्थिक विकास दर भी तेज गति से बढ़ने वाले राज्यों में शामिल है । वर्ष 2025–26 के लिए अनुमान है कि बिहार की अर्थव्यवस्था 14.9 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ेगी ।

महोदय, न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर चलते हुए बिहार सरकार ने सात निश्चय–1 और सात निश्चय–2 के माध्यम से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आधारभूत संरचना में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं । अब सात निश्चय–3 (वर्ष 2025–2030) के संकल्प के साथ बिहार को देश के अग्रणी विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा गया है । इस संकल्प के अंतर्गत राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, एक करोड़ रोजगार अवसर सृजित करना और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं । अब तक 1 करोड़ 56 लाख से अधिक महिला सदस्यों को 10,000 (दस हजार) रुपये की सहायता दी जा चुकी है । साथ ही, उनके व्यवसाय को और आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए 2 (दो) लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी ।

जाति आधारित जनगणना में चिन्हि्त 94 लाख गरीब परिवारों को लघु उद्यमी योजना के माध्यम से सशक्त बनाने का संकल्प है । साथ ही, हॉट–बाजार के विकास से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा । उद्योगों में 50 लाख करोड़ रुपये के निजी निवेश आकर्षित करने, चौथे कृषि रोडमैप से किसानों की आय बढ़ाने, मखाना उत्पादन, डेयरी उद्योग और मत्स्य एवं पशुपालन को प्रोत्साहित करने, प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज स्थापित करने के लिए जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशियलिटी स्तर तक ले जाने, पाँच नए एक्सप्रेस–वे और सौर ऊर्जा विस्तार करने, शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास उपलब्ध कराने तथा पर्यटन और खेलों को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने को लेकर सरकार संकल्पित है । ''सबका सम्मान जीवन आसान'' (Ease of Living) के अंतर्गत बिहार सरकार वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ उनके घर पर उपलब्ध कराएगी और संपत्ति पंजीकरण की सुविधा भी घर पर ही प्रदान करेगी, जिससे सभी नागरिकों का जीवन सरल, सम्मानजनक और सुरक्षित होगा । महोदय, बिहार का बजट आकार पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, जो वर्ष 2004–05 के 23,885 (तेईस हजार आठ सौ पचासी) करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2026–27 में 3,47,589.76 करोड़ रुपये (तीन लाख सैंतालीस हजार पाँच सौ नवासी करोड़ छिहत्तर लाख रुपये) तक पहुँच गया है । यह वृद्धि राज्य की विकास, अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्रों में निवेश करने की बढ़ी हुई क्षमता को दर्शाती है । इस दिशा में आगे बढ़ते हुए बिहार को केंद्र सरकार से सतत् और सशक्त सहयोग की अपेक्षा है जिसमें पर्याप्त कर–बंटवारा, केंद्र प्रायोजित स्कीमों हेतु

अधिक वित्तीय आवंटन, बड़े अवसंरचना एवं कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए विशेष सहायता के साथ–साथ राज्य की बाढ़ और सुखाड़ जैसी संरचनात्मक चुनौतियों के समाधान हेतु नदियों के परस्पर जोड़ जैसी राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में केंद्रीय सहयोग अपेक्षित है । ऐसा सहयोग बिहार की विकास यात्रा को नई गति देगा और जल प्रबंधन, कृषि उत्पादकता तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण में दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करेगा तथा राज्य समावेशी विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ सकेगा तथा विकसित भारत के संकल्प के साथ समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बिहार के लक्ष्य की ओर निर्णायक कदम रख सकेगा ।

अध्यक्ष महोदय, इस दृष्टि और संकल्प के साथ अब मैं वर्ष 2026–27 के बजट का सारांश आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ ।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में बिहार राज्य का बजट आकार 3,47,589.76 करोड़ रुपये (तीन लाख सैंतालीस हजार पाँच सौ नवासी करोड़ छिहत्तर लाख रुपये) है, जो वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट आकार 3,16,895.02 करोड़ रुपये (तीन लाख सोलह हजार आठ सौ पन्चानवे करोड़ दो लाख रुपये) से 30,694. 74 करोड़ रुपये (तीस हजार छः सौ चौरानवे करोड़ चौहत्तर लाख रुपये) अधिक है ।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में वार्षिक स्कीम का बजट अनुमान 1,22,155. 42 करोड़ रुपये (एक लाख बाइस हजार एक सौ पचपन करोड़ बयालीस लाख रुपये) है, जो वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अनुमान 1,16,750 करोड़ रुपये (एक लाख सोलह हजार सात सौ पचास करोड़ रुपये) से 5,405.42 करोड़ रुपये (पाँच हजार चार सौ पाँच करोड़ बयालीस लाख रुपये) अधिक है ।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 2,25,434.34 करोड़ रुपये (दो लाख पचीस हजार चार सौ चौंतीस करोड़ चौतीस लाख रुपये) है, जो वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अनुमान 2,00,135. 42 करोड़ रुपये (दो लाख एक सौ पैंतीस करोड़ बयालीस लाख रुपये) से 25,298.92 करोड़ रुपये (पचीस हजार दो सौ अन्ठानवे करोड़ बानवे लाख रुपये) अधिक है ।

वर्ष 2026–27 में कुल व्यय में स्कीम व्यय 35.14 प्रतिशत तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 64.86 प्रतिशत है ।

महोदय, वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल पूंजीगत व्यय 63,455.84 करोड़ रूपये (तिरसठ हजार चार चौ पचपन करोड़ चौरासी लाख रुपये) अनुमानित किया गया है जो कि कुल व्यय का 18.26 प्रतिशत है, जिसमें पूंजीगत परिव्यय– वर्ष 2026–27 में 39,377.06 करोड़ रुपये (उनतालीस हजार तीन सौ सतहत्तर करोड़ छः लाख रुपये) का पूंजीगत परिव्यय अनुमानित किया गया है, जिसमें सामान्य सेवाओं में 6,117.30 करोड़ रुपये (छः हजार एक सौ

सतरह करोड़ तीस लाख रुपये), सामाजिक सेवाओं में 7,434.80 करोड़ रूपये (सात हजार चार सौ चौंतीस करोड अस्सी लाख रूपये) एवं आर्थिक सेवाओं में 25,824.96 करोड़ रुपये (पचीस हजार आठ सौ चौबीस करोड़ छियानवे लाख रुपये) की राशि प्रस्तावित है ।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल राजस्व प्राप्तियाँ 2,85,277.12 करोड़ रुपये (दो लाख पचासी हजार दो सौ सतहत्तर करोड़ बारह लाख रुपये) अनुमानित है जो कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट से 2,60,831.44 करोड़ रुपये (दो लाख साठ हजार आठ सौ एकतीस करोड़ चौवालीस लाख रुपये) से 24,445.68 करोड़ रूपये (चौबीस हजार चार सौ पैंतालीस करोड़ अरसठ लाख रुपये) अधिक है ।

(क्रमशः)

टर्न–11 / पुलकित / 03.02.2026

(क्रमशः)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में 65,800 करोड़ रुपये (पैंसठ हजार आठ सौ करोड़ रुपये) प्राप्त होने का अनुमान है, जिसमें 50,000 करोड़ रुपये (पचास हजार करोड़ रुपये) वाणिज्यकर, 10,000 करोड़ रुपये (दस हजार करोड़ रुपये) स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क, 5,000 करोड़ रुपये (पाँच हजार करोड़ रुपये) परिवहन शुल्क एवं 800 करोड़ रुपये (आठ सौ करोड़ रुपये) भू–राजस्व से प्राप्त होगा ।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में 9,402.99 करोड़ रुपये (नौ हजार चार सौ दो करोड़ निन्यानवे लाख रुपये) प्राप्त होने का अनुमान है, जो कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अनुमान 8,220.57 करोड़ रुपये (आठ हजार दो सौ बीस करोड़ संतावन लाख रुपये) की तुलना में 1,182.42 करोड़ रुपये (एक हजार एक सौ बेरासी करोड़ बयालीस लाख रुपये) अधिक है। इसमें खनन से 4,200 करोड़ रुपये (चार हजार दो सौ करोड़ रुपये), ब्याज प्राप्तियों से 2,570.08 करोड़ रुपये (दो हजार पाँच सौ सत्तर करोड़ आठ लाख रुपये) शामिल है।

वर्ष 2026–27 में राजस्व अधिशेष 1,143.19 करोड़ रुपये (एक हजार एक सौ तैंतालीस करोड़ उन्नीस लाख रुपये) अनुमानित है । वित्तीय वर्ष 2026–27 में 39,111.80 करोड़ रुपये (उनचालीस हजार एक सौ ग्यारह करोड़ अस्सी लाख रुपये) राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 13,09,155 करोड़ रुपये (तेरह लाख नौ हजार एक सौ पचपन करोड़ रुपये) का 2.99 प्रतिशत है ।

समेकित निधि में राशि वित्तीय वर्ष 2026–27 में सकल (Gross) व्यय 3,53,045.15 करोड़ रुपये (तीन लाख तिरपन हजार पैंतालीस करोड़ पन्द्रह

लाख रुपये) प्रस्तावित है जिसमें निवल (Net) व्यय 3,47,589.76 करोड़ रुपये (तीन लाख सैंतालीस हजार पाँच सौ नवासी करोड़ छिहत्तर लाख रुपये) है। विदित है कि विनियोग विधेयक में सकल (Gross) व्यय प्रस्तावित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में सकल व्यय 3,53,045.15 करोड़ रुपये (तीन लाख तिरपन हजार पैंतालीस करोड़ पन्द्रह लाख रुपये) में मतदेय राशि 3,02,242.13 करोड़ रुपये (तीन लाख दो हजार दो सौ बयालीस करोड़ तेरह लाख रुपये) एवं भारित राशि 50,803.02 करोड़ रुपये (पचास हजार आठ सौ तीन करोड़ दो लाख रुपये) है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने मेरा भाषण पूर्ण एकाग्रता से सुना है। इसके लिए मैं सदन के सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं वर्ष 2026–27 की वार्षिक वित्तीय विवरणी एवं अन्य बजट दस्तावेजों को सदन के समक्ष उपस्थापित कर रहा हूँ । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

<u>माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद–विवाद</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय राज्य के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद–विवाद प्रारंभ होगा, इसके लिए दिनांक– 03 फरवरी, 2026 एवं 05 फरवरी, 2026 कुल दो दिन निर्धारित है ।

माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी जी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेशन करने की अपनी इच्छा की सूचना दी है तथा माननीय सदस्य, श्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा द्वारा इनके अनुमोनद का अनुरोध किया गया है । वाद–विवाद एवं सरकार के उत्तर के लिए चार घंटे का समय उपलब्ध है । कुछ समय बजट प्रस्तुत करने में व्यतीत हुआ है । अगर आवश्यकता पड़ी तो इस कार्य के लिए निर्धारित समय में बढ़ोत्तरी की जाएगी। विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार के उत्तर के लिए भी समय दिया जाएगा :–

भारतीय जनता पार्टी	– 88 मिनट
जनता दल (यू)	– 84 मिनट
राष्ट्रीय जनता दल	– 25 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)	– 18 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	– 6 मिनट
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा	– 5 मिनट
ए0आई0एम0आई0एम (AIMIM)	– 5 मिनट
राष्ट्रीय लोक मोर्चा	– 4 मिनट
सीपीआई (एम0एल0)	– 2 मिनट
सीपीआई (एम0)	– 1 मिनट
बहुजन समाज पार्टी	– 1 मिनट

इंडियन इंक्लूसिव पार्टी	– 1 मिनट
कुल	– 240 मिनट

माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदस्यगण इस अभिभाषण के लिए राज्यपाल के कृतज्ञ हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात प्रारंभ करने के पहले बिहार के बारे में दो लाइन बोलना चाहता हूं–

''नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है बिहार,
शिक्षा, पथ और उद्योग से सजेगा बिहार।
तरक्की की राह पर अग्रसर है बिहार,
देश के विकास में निज बांटेगा आधार,
देश के विकास में निज बांटेगा आधार ।''

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के समवेत अधिवेशन में प्रस्तुत अभिभाषण का पूरे आत्मविश्वास, पूरे सम्मान और पूरे राजनीतिक संकल्प के साथ समर्थन करता हूं ।

यह अभिभाषण केवल सरकार की नीतियों का विवरण नहीं है, बल्कि बिहार के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक पुनर्निर्माण की जीवंत गाथा है। यह अभिभाषण बिहार की सच्ची कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसे बिहार की जनता रोज अपने जीवन में महसूस कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय, बिहार ने इतिहास भी देखा है, उपेक्षा भी देखी है और संघर्ष भी देखा है । एक समय ऐसा था जब बिहार की पहचान उसकी संभावनाओं से नहीं, बल्कि उसकी समस्याओं से की जाती थी । लेकिन आज, माननीय अध्यक्ष महोदय, वही बिहार अपनी पहचान सुशासन, सामाजिक न्याय और विकास की निरंतरता से बना रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के यशस्वी नेतृत्व में, लगातार विकास की ओर, उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है ।

अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में, लगातार 2005 में जो 23 हजार करोड़ के आस–पास बजटीय प्रावधान हुआ करता था, अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने जो 2026–27 का बजट पढ़ा है, उसमें 3 लाख 47 हजार करोड़ से ज्यादा बजटीय प्रावधान उन्होंने कहा है । कहां से कहां हमारा बिहार बढ़ रहा है और 2025–26 से 2026–27 में लगभग 10 प्रतिशत बजटीय

उपबंध बढ़ा है । अध्यक्ष महोदय, यह हमारे बिहार के विकास की गाथा की लकीर दिखाई पड़ रही है ।

अध्यक्ष महोदय, कल ही माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन के समक्ष आर्थिक सर्वेक्षण सदन के पटल पर रखा था । अध्यक्ष महोदय, बिहार में उस सर्वेक्षण से पता चलता है, बिहार देश में सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्य में शामिल है । विकास दर राष्ट्रीय औसत से भी हमारी विकास दर ज्यादा है। कभी हमारे आंकड़े के कारण देश पीछे रह जाता था, आज हमारे आंकड़े के कारण देश आगे बढ़ रहा है । अध्यक्ष महोदय, यह हमारे बिहार के विकास की गाथा लिखी जा रही है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : राहुल जी, शांत रहिये ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, राज्य का आंतरिक राजस्व सालाना 12.9 फीसदी की दर से बढ़ रहा है । बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति 6 साल में दुगुनी हुई है । अध्यक्ष महोदय, बिहार का आर्थिक विकास भी तेजी से हो रहा है ।

2005 में प्रति व्यक्ति आय 7,840 रुपये थी, जो कल के ताजा सर्वेक्षण में 76,490 रुपये पहुंच गयी, पर–कैपिटा इनकम यह पता चलता है और बिहार की विकास दर बड़े राज्यों में तमिलनाडू को छोड़ दें, तो बिहार की विकास दर 13.1 प्रतिशत दर्शायी गयी है, जो देश में तमिलनाडु के बाद बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा है ।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के लिए कानून का राज उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है । हम अगर इतिहास देखें, तो कोई भी राज पूर्णतः अपराध मुक्त हो, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अपराध तो अपराधी के मन में बसता है । लेकिन अध्यक्ष महोदय, बिहार में संगठित अपराध बंद हो गए और हमारी सरकार अपराध पर नियंत्रण कर रही है और हमारी सरकार यह काम पूरी दृढ़ता से कर रही है ।

हमने पुलिस तंत्र को सुदृढ़ किया, उन्हें आधुनिक अस्त्र–शस्त्र दिए जा रहे हैं, आधुनिक वाहन दिए जा रहे हैं । पुलिस तंत्र को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी छूट मिली हुई है ।

(क्रमशः)

टर्न–12 / हेमन्त / 03.02.2026

श्री संजय सरावगी : (क्रमशः) : अपराधियों का मनोबल गिर रहा है। पुलिस नियंत्रण के लिए संजीदगी से प्रयासरत है। अध्यक्ष महोदय, 2005 में बिहार की अपराध दर 4.4 प्रतिशत थी, जो अब घटकर 2 प्रतिशत रह गयी है। हमारे पुलिस बलों की संख्या जो 2005 में 42 हजार थी, जो अब बढ़कर 1.35 लाख हो गयी और महिला पुलिस में पूरे देश में बिहार नंबर वन पर है, यह मैं आपको बताना

चाहता हूं । महिलाओं की जो कानून–व्यवस्था में सहभागिता है। साथ ही, महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा आंकड़ा यह दिखायी पड़ रहा है। सदन के माध्यम से यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार की सोच है कि जो अपराध करेंगे उनकी जगह सलाखों के पीछे होगी। पुलिस उसको कतई नहीं छोड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, कोई राज्य महिला सशक्तिकरण के बगैर कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने महिला सशक्तिरण की दिशा में अनेक सफल प्रयास किये हैं और महिला सशक्तिरण की हम बात करें, तो 2006 में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पंचायती राज में 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया, 2007 में नगर निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठकर नहीं बोलिये। मौका मिलेगा आपको।

श्री संजय सरावगी : जिसके कारण आज महिलाएं बराबर की भागीदार तो हैं ही, साथ ही बिहार की सत्ता में बराबर का संचालन करने का भी काम हमारी महिलाएं कर रही हैं। आज हजारों की संख्या में महिला मुखिया हैं, सरपंच हैं, जिला परिषद् की अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, महापौर हैं, उप महापौर हैं, जो बिहार की सत्ता के संचालन में बिहार को आगे बढ़ाने का काम बिहार की महिलाएं कर रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने का जो प्रावधान किया गया, उसमें 1.56 करोड़ महिलाओं को हम लोगों ने 10,000 रूपये रोजगार के लिए दिए और अगर वो रोजगार सही तरह से करेंगी, तो 2 लाख तक उनको और वित्तीय सहायता सरकार देगी। यह कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा जा सकता था अध्यक्ष महोदय। लेकिन आज हमारी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए और महिलाओं को नौकरी नहीं, महिलाएं रोजगार देने में, रोजगार को सृजन करने के लिए आज हमारी सरकार लगातार काम कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में और हमारे यशस्वी अनुभवी नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार की प्रगति की चर्चा अब देश ही नहीं, दुनिया में भी हो रही है। बिहार का युवा अब अंगड़ाई ले रहा है। दुनिया बिहार की मेधा का लोहा तो पहले से ही मानती थी, अब बिहारी अपने श्रम के बदौलत अपनी संस्कृति और सभ्यता को देश के कोने–कोने में ले जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, अब हमारी सरकार ने बिहार के युवाओं को अपने राज्य की तरफ मोड़ने का काम शुरू कर दिया है। अब अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी रोजगार देंगे, यह हमारी सरकार ने सात निश्चय में तय किया है। उसके लिए कैबिनेट से मुख्य

सचिव की अध्यक्षता में हम लोगों ने कमेटी का भी निर्माण किया। अध्यक्ष महोदय, हम जो कहते हैं, वही करते हैं। यह कई मामलों में हम लोगों ने दिखाया भी है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को, जो हम लोगों ने कहा है सरकारी नौकरी और उनको रोजगार देंगे, तो सरकार ने अलग से रोजगार एवं युवा कौशल विभाग का भी गठन किया है और उसके लिए अलग से मंत्री और प्रधान सचिव की भी नियुक्ति सरकार ने की है। अध्यक्ष महोदय, पहले बिहार के लोग नौकरियों के लिए राज्य से बाहर चले जाते थे, अब बाहर के लोग भी सरकारी नौकरियों के लिए बिहार आ रहे हैं, यह दिखाई पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय। अब अगर किसी को टीन का चश्मा आँख में लगा हुआ है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, क्या कोई इनकार कर सकता है ? आप जिस क्षेत्र से आते हैं, गया जी से। अध्यक्ष महोदय, तीन – साढ़े–तीन– चार घंटे गया जी जाने में लग जाते थे। अब आप जरा सोचिए, एक आम इंसान भी अब डेढ़ घंटे में गया जी पहुँच रहा है, यह हमारी सरकार के जो काम हैं, जो दूरदृष्टि है, वो दिखाई पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, सड़क जो बनती है, क्या इस सड़क पर किसी खास दल, धर्म, मजहब, जाति के लोग ही चलेंगे ? विपक्ष के हमारे साथी उस पर नहीं चलेंगे क्या ? यह जो कह रहे हैं, तो क्या इनके मतदाता उस पर नहीं चलेंगे ? अध्यक्ष महोदय, यह सड़क सभी के लिए है, सभी जात और धर्म के लिए है। अध्यक्ष महोदय, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उप–मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के किसी कोने से हम 4 घंटे में पटना राजधानी पहुँच रहे हैं, यह हमारा विकास दिखाई पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, जहाँ कभी सड़क में गड्ढा था, गड्ढे में सड़क थी, यह दिखाई नहीं पड़ रहा था। आज स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो और एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है। आज पटना–पूर्णिया–बक्सर–भागलपुर एक्सप्रेस हाईवे, आमस, दरभंगा, जिस कंस्टीच्यूंसी से मैं आता हूं, दरभंगा से आता हूं, जाकर देखिए कहाँ से कहाँ विकास आज मिथिला का हो रहा है, आमस–दरभंगा एक्सप्रेस हाईवे, गोरखपुर–सिलीगुड़ी, रक्सौल–हल्दिया एवं वाराणसी–गया जी–कोलकाता सहित छह एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जा रहा है। गंगा पर सात नए पुल का निर्माण हो रहा है और सात अन्य निर्माणाधीन भी हैं। वहीं कोसी, गंडक, सोन, बागमती और फल्गु जैसी प्रमुख नदियों पर भी पुलों की संख्या दोगुनी हो गई है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं आज अंतिम व्यक्ति तक ले जाने के लिए कृतसंकल्पित हैं। यही कारण है कि अब हम हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं, बड़े–बड़े अस्पताल बनाए जा रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मौका मिलेगा आप लोगों को भी। तब रखियेगा अपनी बात को।

श्री संजय सरावगी : माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने बिहार को दो एम्स दिए हैं। एक पहले पटना में एम्स दिया गया और अभी हाल–फिलहाल में ही दरभंगा में भी एक एम्स देकर जम्मू–कश्मीर के बाद बिहार एकमात्र राज्य है, जहाँ दो–दो एम्स भारत सरकार ने दिये हैं। हर जिले में जीएनएम कॉलेज खोले जा रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूँ जो लोग हल्ला कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ डिस्टर्ब भी कर रहे हैं और हल्ला भी कर रहे हैं। 2005 में..

(व्यवधान)

सुनिए–सुनिए, 2005 में सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए प्रति माह, प्रति अस्पताल 39 मरीज आते थे। कितने आते थे अध्यक्ष महोदय? 39 मरीज आते थे। जबकि कल के आर्थिक सर्वेक्षण में जो आंकड़ा आया है, उसमें 39 से हम 12,000 से भी ज्यादा पहुँच गए। यह हमारे सरकारी अस्पतालों में आम जनता का विश्वास दिखाई पड़ रहा है, यह परिलक्षित हो रहा है। कहाँ 39 और कहाँ 12,000 से ज्यादा! यह इनको दिखाई नहीं पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, चश्मा टीन का है, ओरिजिनल चश्मा लगाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इनके 15 साल के शासनकाल में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला, वह छः के छः मेडिकल कॉलेज ही रह गए। अब बढ़कर 15 हो गये सरकारी मेडिकल कॉलेज, 21 निर्माणाधीन हैं और 21 के अलावा 7 और स्वीकृत किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, यह हमारे स्वास्थ्य विभाग की गाथा हो रही है। एक भी राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बिहार में नहीं था। आज दो–दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एक गया में, एक मोतिहारी में। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, निफ्ट है, चंद्रगुप्त इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना में है, आईआईएम बोधगया में है, आईआईटी भागलपुर की स्थापना भी हुई है। जहाँ एक भी राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय स्तर के संस्थान, देश की आजादी के बाद इन्हीं के गठबंधन ने ज्यादा से ज्यादा राज किया, लेकिन बिहार में एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं दिया। आज मैंने उदाहरण के रूप में 10 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के संस्थान गिनाए हैं, तब भी इनको लगता है दिखाई नहीं पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आज हमारी सरकार पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा देने में लगी है।

(क्रमशः)

टर्न–13 / संगीता / 03.02.2026

श्री संजय सरावगी (क्रमशः) : अध्यक्ष महोदय, मैं मिथिला से आता हूं । जानकी मईया जनकजननी जानकी मईया के धर्म की कर्म सिली, जहां उनकी जन्म स्थली पुनौराधाम में है, मिथिला के मुख्यालय दरभंगा से ही मुझे वहां का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है । अध्यक्ष महोदय, माता सीता मिथिला की ही नहीं, बिहार की ही नहीं पूरे सनातन धर्म के लिए पूरे भारत के लिए जगतजननी माता जानकी गौरवशाली है। उनके प्रकाट्य स्थली पर, पुनौराधाम में जहां माता जानकी का प्रकटीकरण हुआ था, वहां हमारी सरकार अयोध्या में श्रीराम मंदिर की तर्ज पर माता जानकी का भव्य मंदिर और कॉरीडोर का निर्माण करा रही है उसके लिए एक हजार करोड़ के आसपास राशि स्वीकृत की है...

(व्यवधान)

इनको बर्दाश्त नहीं होगा अध्यक्ष महोदय, एक बार बोलिए जगतजननकी मईया सीता की जय । अध्यक्ष महोदय, यह सीतामढ़ी वैश्विक पर्यटन पर उभरकर सामने आएगा और वहां आर्थिक समृद्धि भी आएगी । रोजगार तथा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा । आज अहिल्या स्थान का भी विकास हो रहा है, कुशेश्वरस्थान जो बाबा वैद्यनाथ के बाद दूसरा बाबा का स्थान है वहां भी माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे प्रगति यात्रा में, वहां भी काम में हाथ लग गया 50 करोड़ रुपया वहां भी दिया गया । गयाजी में आपके क्षेत्र में विष्णुपद मंदिर और बोधगया का भी आज विकास तेजी से हो रहा है । मैं बोधगया गया था जब मैं राजस्व मंत्री था, फल्गु नदी में, पूरे देश के लोग जब आते थे पितृ पक्ष में तो फल्गु नदी से बूंद दो बूंद पानी नहीं निकलता था, आज दो से तीन फीट पानी है पूरे गयाजी में, गंगा का जल आज घर–घर जा रहा है, यह हमारी सरकार की देन है और पूरे विश्व से, पूरे देश से लोग अपने पूर्वजों का तर्पण करने के लिए आते हैं । अध्यक्ष महोदय, वहां क्या कोरिडोर बना है जाकर इनलोगों को देखना चाहिए जो लोग हल्ला–गुल्ला कर रहे हैं एक बार जरूर जाकर आज देखें । एक समय था जब लोग शाम में 7 बजे खाना खाकर सो जाते थे और इसलिए सो जाते थे 7 बजे क्योंकि अगर जागेंगे तो उनको दिया जलाना पड़ेगा और इसके कारण किरोसीन तेल ज्यादा लगेगा, अब वह समय खत्म हो चुका है । अब घर–घर बिजली पहुंच चुकी है, सौ प्रतिशत घरों में आज बिजली पहुंच चुकी है, गांव का स्वरूप बदल रहा है, गांव बिजली की आपूर्ति की वजह से सुविधायुक्त हो गए हैं और अभी कल जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत तीगुनी हो गयी है यह भी हमारे विकास की जो रूपरेखा है वह दिखाता है । अध्यक्ष महोदय, अभी इन लोगों को नहीं पता चलेगा, बिजली तो देते नहीं थे और

राशि दुगुना–तीगुना आता था बिजली बिल और हमारी सरकार ने 125 यूनिट बिजली प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता को फ्री भी कर दिया और अभी मैं आंकड़ा देख रहा था 3–4 दिन पहले, पूरे बिहार में एवरेज 40 प्रतिशत लोगों को एक रूपया भी बिजली बिल नहीं आ रहा है यह हमारी सरकार की ही देन है और जो भी चाहेंगे....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृप्या शांति बनाए रखें । आप बोलिएगा जब मौका मिलेगा ।

श्री संजय सरावगी : उन सबके घरों में सोलर पैनल लगेगा और वह भी भारत सरकार ने 50 परसेंट सब्सिडी भारत सरकार उसपर दे रही थी, हमारी सरकार ने 50 प्रतिशत को 100 प्रतिशत कर दिया, घरों पर सोलर पैनल लगेंगे । बिजली बचाओ, पैसा पाओ, सोलर पैनल में अगर 125 यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा तो उनके खाते में वह बिजली जाएगी, यह हमारी सरकार चहुंमुखी विकास की ओर अग्रसर हो रही है । पटना–गया में पहले से ही हवाई सेवा चल रही थी । माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी सोच के तहत अब दरभंगा और पूर्णिया से भी विमान उड़ रहे हैं, देश के कोने–कोने में चाहे बैंगलोर जाना हो, मुम्बई जाना हो, कलकत्ता जाना हो, दिल्ली जाना हो, हैदराबाद जाना हो, 2 से 3 घंटे में पहुंच जा रहे हैं और दरभंगा में तो जल्द ही अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट भी होने वाला है, यह आपके माध्यम से मैं पूरे बिहार को बताना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, 14 सौ करोड़ से बड़ा टर्मिनल दरभंगा में बन रहा है । आज मिथिला कहां से कहां पहुंच गया, हमारी सरकार का कहना है कि मिथिला के विकास के बिना बिहार का विकास नहीं हो सकता तो मिथिला का चहुंमुखी विकास माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उपमुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हो रहा है । अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता भी है किसान को आगे बढ़ाना और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिथिला के मखाना को विश्व का मखाना बना दिया । आज माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व के किसी देश में जाते हैं तो मखाना साथ में लेकर जाते हैं और साथ में ही लेकर नहीं जाते हैं बल्कि भेंट भी मखाना करते हैं कि हमारे मिथिला का मखाना सुपरफुड विश्व का मखाना हो गया, किसानों की आय बढ़ रही है । मैं अभी प्रधानमंत्री जी से मिलने गया था, जब मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बना था, उन्होंने चर्चा की, किसानों की चर्चा की और किसानों की चर्चा के साथ–साथ मिथिला के मखाना के किसानों की विशेषकर के चर्चा की कि पहले क्या रेट मिलता था मखाना का, अभी क्या दर मिल रहा है, पहले से कितना उत्पादन बढ़ रहा है यह प्रधानमंत्री जी की किसानों के प्रति और मिथिला के प्रति सोच को दर्शाती है कि मैं मिलने गया और वे चर्चा कर रहे हैं किसानों की...

(व्यवधान)

लेकिन देखिए, इन लोगों को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि मिथिला और बिहार का क्यों विकास हो रहा है । अध्यक्ष महोदय, आज कुछ लोग...

(व्यवधान)

ये देखिए सवाल उठा रहे हैं अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : कृपया टोका–टोकी न करें ।

श्री संजय सरावगी : सवाल उठाना लोकतंत्र में...

(व्यवधान)

फिर बोल रहे हैं...

अध्यक्ष : सौरभ जी, बैठे–बैठे मत बोलिए । माननीय सदस्य आग्रह है मत बोलिए । बैठिए ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं इन लोगों को बताना चाहता हूं । सवाल उठाना लोकतंत्र में स्वाभाविक है । उठाना भी चाहिए लेकिन जवाब सुनने का साहस भी होना चाहिए। जब बिहार पिछड़ा हुआ था, तब चुप्पी थी अब बिहार आगे बढ़ रहा है तो बेचैनी है । असल समस्या यह नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, असल समस्या यह है कि काम दिख रहा है यह इनकी बेचैनी है । आज कहां से कहां बिहार पहुंच गया, आज कहीं जाइए, सिमरिया धाम जाइए अध्यक्ष महोदय, क्या गंगा नदी के किनारे आज वहां बना है, क्या वहां जो पुल बना है, डेढ़ घंटा में बेगूसराय पहुंच जाते थे, ये बैठे हुए हैं, वहां के माननीय विधायक डेढ़ घंटा में पहुंच रहे हैं तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है लगता है ये पुराना ही बेगूसराय का रोड खोज रहे हैं ऐसा मुझे लगता है । मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बोलने के लिए तो बहुत समय है लेकिन और लोगों को भी बोलना है। मैं केवल महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण यह स्पष्ट करता है कि यह सरकार न्याय के साथ विकास के मार्ग पर अडिग है । समाज का कोई वर्ग कोई क्षेत्र कोई व्यक्ति पीछे न छूटे यही हमारी सरकार का संकल्प है यह सरकार वादों की नहीं काम की राजनीति करती है । परिणाम बोलते हैं और परिणाम ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है यह दिखाई पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय । अंत में मैं सदन से आग्रह करता हूं कि बिहार की जनता ने जिस विश्वास के साथ इस सरकार को जनादेश दिया है उस विश्वास का सम्मान करते हुए हम सभी महामहिम राज्यपाल के इस अभिभाषण का समर्थन करें ताकि बिहार विकास, सम्मान और समावेश के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे । बस, दो लाईन और कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा । जानकी के संस्कार मतलब मईया सीता के संस्कार, गंगा की धार, ज्ञान की पावन धरा, नालंदा का सम्मान, विद्यापति की बोली, महापुरूषों का धाम, ज्ञान और वीरगाथा गूंज रहा बिहार । बहुत, बहुत धन्यवाद आपने मुझे जो समय दिया अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा ।

टर्न–14 / यानपति / 03.02.2026

श्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री संजय सरावगी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का मैं अनुमोदन करता हूं । अध्यक्ष महोदय, सरावगी साहब ने बहुत सारी चीजों पर अपनी बात रख दी है और उसको फिर दुहराना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं । विधान मंडल के संयुक्त अधिवेशन में माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा जो संबोधन किया गया है उनका मैं आभारी हूं और धन्यवाद प्रस्ताव पर अनुमोदन करता हूं, प्रस्ताव के अनुमोदन की जिम्मेदारी मुझे एन0डी0ए0 सरकार के मुखिया एवं हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूं । एक बात जरूर कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जबसे सत्ता संभाली है उनका सभी धर्मों सभी वर्गों का मान–सम्मान करने की फिक्र करने का और खासतौर से महिलाओं की सुरक्षा और उनके विकास की चिंता सबसे ज्यादा रही है और इसी के संदर्भ में हमारे नेता ने अपनी सुख–सुविधा को त्यागकर के दोहन करनेवाली संपत्ति अर्जित करने का माध्यम न बनकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्गों के उत्थान की दिशा में कारगर कदम उठाया है और सबसे ज्यादा उन्होंने महिलाओं पर उनके विकास, तरक्की लड़कियों की पढ़ाई–लिखाई वगैरह सब चीजों पर उन्होंने बहुत बढ़िया से जिम्मेदारीपूर्वक निर्वाह किया है । हम आपके माध्यम से सदन के सदस्यों को एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि सदन में बहुत सारे लोग हैं, अनुभवी हैं सबको बोलना है अब सब लोग अपनी बात रखेंगे लेकिन 2005 के पहले जो बिहार की स्थिति थी वह बहुत ही खराब थी, 2005 में पहली बार हमलोग...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बोलिए ।

श्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा : 2005 में हमलोग एम0एल0ए0 बनकर आए थे...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया शांति बनाए रखें ।

श्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा : हमारे यहां तत्कालीन एस0पी0 काजमी साहब थे...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यों से आग्रह है कि बीच में न बोलें ।

श्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा : लड़कियों की परीक्षा हो रही थी, 1990 की बात मैं बोल रहा हूं, 2000 की बात छोड़ दीजिए । मैंने काजमी साहब से कहा कि हमारे यहां लड़कियों का सेंटर है जगदीशपुर में, उदाहरण दे रहे हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शांति बनाए रखिए, बीच में टोका–टोकी मत कीजिए । भगवान जी, बोलिए ।

श्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा : ये लोग हल्ला करने के आदी हैं । बहुत से सदस्य तो सदन में रहते नहीं हैं, हम तो इन्हीं की बात बोल रहे हैं । 2005 की बात छोड़िए, 1990 की बात मैं बोल रहा हूं । किस तरह से तरक्की किया, आप भी 1990 में आये होंगे, हम भी 1990 में जीतकर आए थे तो 1990 में जब हमलोग जीतकर आए थे, तात्कालिक एस0पी0 हमारे काजमी साहब थे तो हमलोग गए कि लड़कियों का सेंटर पड़ा है उस सेंटर पर महिला पुलिस लगा दीजिए ताकि किसी तरह की दिक्कत नहीं हो । महोदय, काजमी साहब का उस समय का बयान था कि महिला पुलिस हमारे जिला में एक भी नहीं है, एक भी नहीं थी 1990 में, आपकी सरकार बनी थी और सरकार बनने के बाद हमने यह सवाल उठाया था कि विधि–व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाय । उस वक्त से आज की तारीख में महिलाओं की जो पुलिस में बहाली हुई, नौकरियों में महिलाओं का जो आरक्षण हुआ उसकी प्रगति की चर्चा कई साथियों ने कर दिया । हमारे सरावगी साहब ने किया है और आज महिला सिपाहियों की संख्या इतनी बढ़ी है कि हम समझते हैं कि उसका जिक्र नहीं किया जा सकता । उन्होंने ठीक ही कहा है कि पूरे देश में प्रथम स्थान है बिहार में महिलाओं का और यह देन सिर्फ एन0डी0ए0 सरकार और खासकर नीतीश कुमार जी की देन है । नीतीश कुमार जी ने उस दिशा में काम किया है । बच्चियों को पढ़ने के लिए, उस वक्त भी हमलोग एम0एल0ए0 थे तो हमलोग देखते थे, कहीं कोई हाईस्कूल में, मिडिल स्कूल में लड़कियों की संख्या बहुत कम थी लेकिन जबसे पोशाक योजना चली, छात्रवृत्ति योजना चली, शिक्षकों की बहाली, साईकिल योजना चली तब हम समझते हैं कि हजारों हजार लड़कियां पढ़ने की दिशा में कारगर कदम उठाई हैं । और जब पढ़ाई पढ़ेगा तब न आदमी की तरक्की होगी तो उस समय हमलोगों ने देखा था । पोशाक का मामला, बालिका शिक्षा के मामले में, बेटियों को शिक्षा के मामले में बहुत हद तक प्रगति की बिहार ने और आज उसका नतीजा है कि शिक्षकों की बहाली में, पुलिस की बहाली में, क्लर्क में, मेडिकल में, दारोगा में 35 प्रतिशत आरक्षण देने से संख्या बढ़ी है । एक बहुत बड़ा सम्मान बढ़ा है । फिर पंचायती राज में जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया उसका भी बेनेफिट बहुत ज्यादा मिला । नीतीश कुमार जी की सरकार ने 2006 में कई मामलों में, आधी आबादी के लिए बहुत सारा कानून बना । आरक्षण सहित अन्य भी कानून बने हैं और 1 करोड़ 40 लाख दीदियों का जो, समूह के गठन के बाद जीविका दीदी को दिया गया है, अब ये लोग क्या प्रचार करते थे, हमलोग चुनाव में घूम रहे थे तो प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी का बयान आया था हमारे इलाका में कि यदि सरकार हमारी बनती है तो हम 30 हजार रुपया देंगे, नीतीश कुमार जी तो 10 हजार ही दे रहे हैं और लोगों ने प्रचार इतना

गलत किया, हमलोग जाते थे तो ये लोग बोलते थे कि पैसा लौटाना पड़ेगा । ये लोग प्रचार किए थे कि चुनाव में सरकार बन रही है और तेजस्वी जी का तो बयान आया था...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया शांति बनाए रखें, आपको भी मौका मिलेगा ।

श्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा : कि लोग नकली फॉर्म भरवाकर लोगों को डिस्टर्ब करते थे । प्रचार करते थे कि पैसा लौटाना पड़ेगा और जब हमलोगों की सरकार बन गई, ये लोग आपस में, गठबंधन लड़ता था, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कांग्रेस से बनेगा, आर0जे0डी0 से बनेगा, माले से बनेगा किनसे बनेगा इनका आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा था । सरकार बनने के बाद जो विपक्ष में लोग थे इनका यही काम था, कोई मतलब जनता से लेना–देना नहीं था और मेरे नेता माननीय नीतीश कुमार जी चुनाव जीते, चुनाव खत्म होने के बाद यात्रा पर निकल गए जानने के लिए कि क्या दुख है, क्या तकलीफ है, हमारे नेता दुख तकलीफ समझते हैं, जानते हैं और उसी के अनुसार नीति निर्धारण करते हैं । उन्होंने चुनाव में कई जगह घोषणा की थी उसको भी पूरा करने की दिशा में बढ़ रहे हैं । मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे यहां चुनाव में गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, लंबे समय से, जिस तरह से अयोध्या में मंदिर बनाने की चर्चा लंबे समय से चलती थी और माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में मंदिर का निर्माण हो गया और उसी तरह 1857 विद्रोह के नायक बाबू कुंवर सिंह की जन्मस्थली जगदीशपुर लंबे समय से पर्यटन स्थल बनेगा, पर्यटन स्थल बनेगा, इसकी तरक्की की जायेगी, विकास किया जायेगा आजतक उसकी चर्चा नहीं हुई । मैं शुक्रगुजार हूं नीतीश कुमार जी का कि नीतीश कुमार जी गए थे चुनाव प्रचार में, जनता के डिमांड पर उन्होंने कहा कि आपके क्षेत्र में हमलोग पर्यटन स्थल विकसित करेंगे और आज इनकी घोषणा के बाद उसका प्रारूप तैयार होने लगा । पदाधिकारी लग गए, कला संस्कृति विभाग भी लग गया, पर्यटन विभाग भी लग गया तो यह काम हो रहा है ।

(क्रमशः)

टर्न–15 / मुकुल / 03.02.2026

क्रमशः

श्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा : तो माननीय नीतीश कुमार जी काम के रूप में जाने जाते हैं, भाषण के रूप में नहीं जाने जाते हैं और आपलोग जिसके नेतृत्व में काम करते हैं वह दूसरा उसका हिसाब है, उस हिसाब की बात कीजिएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जायेगा । नीतीश कुमार जी.....

(व्यवधान)

एक बात समझ लीजिए, आर0जे0डी0 को भ्रष्टाचार पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है ।

अध्यक्ष : कृपया आपस में बात नहीं करें । माननीय सदस्यों से आग्रह है कि शांति बनाये रखें।

(व्यवधान)

श्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा : आपके राज में भ्रष्टाचार बढ़ा है, भ्रष्टाचार के आप जननी हैं, लूट–पाट बढ़ी है और आज उसका नतीजा है कि हमको तो नहीं कहना चाहिए लेकिन माननीय लालू जी.....

(व्यवधान)

क्या लालू जी स्वतंत्रता सेनानी में जेल गये थे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठकर नहीं बोलें ।

श्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा : किस केस में जेल गये थे, आप बताइये । कौन सा युद्ध हुआ था, कौन सी लड़ाई हुई थी । कोई लड़ाई में जेल गये थे । हुजूर, भ्रष्टाचार के मामले पर इन लोगों को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है । भ्रष्टाचार पर मत बोलिए । भ्रष्टाचार को उन्मूलन करने का हथियार नीतीश कुमार ने अपनाया है और आहिस्ते–आहिस्ते जितने जनता की चोरी करने वाले लोग हैं, जनता का पैसा लूटने वाले लोग हैं अब उनकी जगह हुजूर सदन में नहीं होगा, सदन से बाहर होगा । इसलिए आपको छटपटाने की जरूरत नहीं है, आप हल्ला मत कीजिए, ध्यान से जनता का जो फैसला है उसे स्वीकार करना चाहिए और जनता ने स्वीकार किया, हमलोगों के काम को अपनाया और सब नीतीश कुमार के नेतृत्व में एन0डी0ए0 की सरकार बनाया । वैसी स्थिति में आपको कहां दिक्कत हो रही है, आप बहुत दूर हैं, दिल्ली बहुत दूर है, आप बाहर ही रहियेगा ।

(व्यवधान)

आपके नेता कह रहे हैं कि हम बाहर ही रहेंगे ।

अध्यक्ष : भगवान जी, भगवान बाबू, आप आसन की ओर देखिए ।

श्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा : हुजूर, माननीय विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कि अब हम 100 दिन नहीं बोलेंगे । पब्लिक कह रही थी कि 100 दिन नहीं बोलिएगा कि 100 दिन हाउस में नहीं जाइयेगा कि 100 साल तक हाउस में नहीं जाइयेगा । पब्लिक सवाल कर रही है, यह मेरा सवाल नहीं है हुजूर, यह सवाल है इनलोगों । अध्यक्ष महोदय, हम विपक्ष के साथियों से आग्रह करना चाहते हैं कि माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है, सागर में गागर है, उन्होंने सब चीजों पर कहा है और सबकी तरक्की की बात उन्होंने कही है । इसलिए सर्वसम्मति से इस भाषण का समर्थन करना चाहिए और इस भाषण के आलोक में सब लोग अपना समर्थन दें और बिहार की तरक्की की बात सोचिए । आपका भी औलाद है पढ़ने वाला, कितना बढ़िया माननीय मुख्यमंत्री जी ने

कहा 534 ब्लॉक है और सभी ब्लॉक में डिग्री कॉलेज बनेगा तो उनमें किसका बेटा पढ़ेगा, आपका बेटा नहीं पढ़ेगा, हर घर में बिजली है नहीं पढ़ेगा जी, किसका बेटा नहीं पढ़ेगा ।

(व्यवधान)

तो इसका समर्थन तो कीजिए । अरे, ये लोग तो चरवाहा विद्यालय भी खोला तो वह चला कहां । हमें एक जगह भी बताइये कि चरवाहा विद्यालय खुला । हमलोग तो लम्बे समय से हैं और कई साथी भी हैं एक जगह भी बता दें कि चरवाहा विद्यालय खुला है । अब माननीय नीतीश कुमार जी ने जो घोषणा किया है उस घोषणा पर सरकार अमल करती है, नीतीश कुमार जी स्वयं अमल करते हैं । हुजूर, इसलिए विकास के मामले पर.....

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक एक सीनियर मेम्बर हैं, मंत्री रह चुके हैं और पहले ये एक क्रांतिकारी पार्टी भाकपा (माले) के सदस्य हुआ करते थे और उसी रूप में इस सदन में आये थे और मैं कहता हूं कि इनकी ये क्रांतिकारी भाषा आज किस तरह से दक्षिणपंथी सोच की भाषा बदल गयी, यह बहुत निंदनीय है महोदय । माननीय लालू प्रसाद जी जो इस सदन में नहीं हैं, उनका नाम लेकर ये बात बोल रहे हैं और उन्होंने इनको पार्लियामेंट.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आलोक जी, आपकी बात हो गयी, अब आप बैठ जाइये । भगवान बाबू, आप आसन की ओर देखिए ।

श्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, हम जो बोल रहे हैं, भले ये समर्थन करें या न करें, लेकिन भीतर से सब समर्थन है । माले के साथी थे बाहर जो कुछ बोल ले लेकिन सच्चाई से इंकार नहीं कर सकते, जनसंहार का सबसे ज्यादा विरोध कौन कर रहा था, जनसंहार का इसी सदन में, यहां से टांग करके फेंका जा रहा था माननीय सदस्य को और सबसे ज्यादा माले के साथी थे और कहते थे कि लालू के राज में जनसंहार हुआ, 101 लोगों का जनसंहार हुआ, 100 से ज्यादा लोग गिनाते थे आप उधर कैसे चले गये, कौन सा टेबलेट आपको मिल गया । इसलिए इस सदन में जितने मेम्बर हैं, सत्तापक्ष और विपक्ष हों सब लोग सरकार के अंग माने जाते हैं लोकतंत्र में । इसलिए जो बात सही है उसका समर्थन करना चाहिए, जो गलत है उसका विरोध कीजिए, सरकार तो सब सुनने के लिए तैयार है, दो–दो, तीन–तीन, चार–चार माननीय मंत्री बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी भी थे और जितना आप बोलने जा रहे हैं उससे पहले सब काम हो रहा है, आपके बोलने के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने घुम–घुमकर पूरे बिहार में । आप क्या जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब यात्रा में जाते हैं तो पूरी खाने थोड़े ही जाते हैं आपलोगों के जैसा, दूध पीने थोड़े ही जाते हैं, ये बिना दूध पीये हुए घूमते हैं, एक रोटी खाकर के घूमते हैं । किस जनता को रोटी नहीं मिल रहा है, कौन लोग किस समस्या से जूझ रहे हैं इस

बात की तहकीकात करने के लिए जाते हैं और उसी के आधार पर बजट का निर्माण होता है, काम होता है । यह बात दिमाग में कहां से आयी महिलाओं को 10 हजार रुपया, तो कुछ लोगों ने कहा कि सेंधमारी हो रही है, इसमें कहां सेंधमारी, 10 हजार रुपया, 2 लाख रुपया । यह क्या केवल जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के लोगों को पैसा मिला है, अरे सबसे ज्यादा आप लोगों को ही मिला है ।

(व्यवधान)

हुजूर, ये लोग गांव में जाएं, इनलोगों को जनता खोज रही है, बता देते हैं । सबसे ज्यादा जिस जाति की आबादी है हुजूर, उसी जाति का सी0एम0 है, यह आर0जे0डी0 के लोग बोल रहे हैं इनका ढेर सी0एम0 लोग है और ढेर पैसा लिया है लोग जीविका दीदी से तो वो लोग पूछता है कि अब का बोल आ तारा, नीतीश कुमार तो दे देलन अब उ का करबा तोहरा अब, पब्लिक बोल रही है सर । हुजूर, पब्लिक बोल रही है कि ये लोग गद्दारी करते हैं । नीतीश कुमार सबके लिए हैं और सब काम कर रहे हैं । ये लोग बोलते हैं और जब ये लोग बोलते हैं तो पब्लिक पूछती है कि भाई अब काहे बोल रहे हैं । नीतीश कुमार जी ने जो कहा वह किया, ये लोग जो कहें क्या किये आज तक । यह लोग उदाहरण देते हैं, साथी कई लोगों ने उठाया है कि भाई चरवाहा विद्यालय । हम यह जानना चाहते थे कि एक भी बिहार में बताइयेगा 38 जिला है, एक भी बताइये । हमलोगों ने कहा, नीतीश कुमार जी ने कहा कि हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा, हर पंचायत में 10+2 विद्यालय खुलेगा, खुला है, साढे आठ हजार विद्यालय खुला है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अनुमति लेकर बोलिए, बिना अनुमति के मत बोलिए ।

श्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, हम इनको कहना चाहते हैं कि जो सच्चाई है वही बोलें, नहीं तो अब तो ये 72 से 25 पर आ गये हैं, अबकी बार यदि नीतीश कुमार जी का डंटा चला तो आप सदन से आउट हो जाइयेगा, इसमें कहीं से दो राय नहीं है, बढिया से रहिये । सही बात जनता में बोलियेगा तो जनता आपका समर्थन करेगी, हमलोग भी सही बात ही बोलते हैं, सरकार में भी कोई गलती बात होती है तो हमलोग माफी मांग लेते हैं, लेकिन आपलोग कभी माफी नहीं मांगते हैं । इसलिए माफी नहीं मांगते हैं कि आपलोगों को आदत नहीं है, माफी मांगने का संस्कार और संस्कृति नहीं है । हम कह रहे हैं कि आप इस संस्कृति को बहाल कीजिए, गलत को गलत कहिये, सही को सही कहिये । इसलिए हुजूर, मैं सत्तापक्ष और विपक्ष की तरफ से आपसे आग्रह करता हूं कि इनलोगों को भी मनाइये, यह सदन है, सत्य बोलने का सदन है, झूठा परोसने का सदन नहीं है । हुजूर, मैं आपसे आग्रह करना

चाहता हूं कि इन लोगों को भी मनाइये, सलाह दीजिए कि जो बात बोलिये अब सही बोलिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : राहुल जी, बैठकर मत बोलिए, बिना आसन की अनुमति के नहीं बोलिए मेरा आपसे आग्रह है ।

श्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा : कौन बात की मेहरबानी, अरे हम जो बात बोल रहे हैं, आप भी तो हम लोग के साथ ही थे ।

अध्यक्ष : भगवान बाबू, आप आसन की ओर देखिए ।

श्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा : माननीय सदस्य, राहुल जी आपके इलाके में क्या हो रहा था । राहुल जी, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, भोजपुर, रोहतास सबसे ज्यादा जनसंहार वहां होता था, आज एक भी जनसंहार हो रहा है ।

टर्न–16 / सुरज / 03.02.2026

(व्यवधान)

अध्यक्ष : राहुल जी बिना आसन की अनुमति के मत बोलिये । भगवान बाबू आप आसन की ओर देखिये ।

श्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा : आप बताइये कई जगहों पर रेप होता था तो एफ0आई0आर0 इनके राज में नहीं होता था । थानेदार कहते थे कि कागज नहीं है, लोग बोलते थे कागज नहीं है...

(व्यवधान)

आपके राज में भी हमलोग एम0एल0ए0 रहे हैं । एम0एल0ए0 की बात कोई सुनता नहीं था । थाना में लोग जाते थे तो बोलते थे कागज नहीं है...

अध्यक्ष : भगवान बाबू, आप आसन की ओर देखिये ।

श्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा : जी, हुजूर सब बात ठीक है । अब हम समाप्त करेंगे लेकिन इन लोगों को सलाह दे दीजिये कि कम से कम असत्य लोग न परोसें, सही बात बोलिये...

(व्यवधान)

आपके हुकूमत में गौतम शिल्पी कांड हुआ था । अब सब बात मत कहवाइये..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया बैठ जाएं ।

श्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा : सब खोलवाइयेगा तो नंगा हो जाइयेगा...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपका भाषण समाप्त हुआ ।

श्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा : और कलेक्टर की बीबी । यह हमारे राज्य में नहीं हो रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य भगवान बाबू...

(व्यवधान)

श्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा : नीतीश कुमार के राज में 24 घंटा में कार्रवाई हो रही है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य भगवान बाबू आप आसन की ओर देखिये ।

श्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा : हुजूर इन लोगों को बोलिये । हम आसन की तरफ ही देख रहे हैं । ये लोग सब गड़े हुये भूत उखाड़ रहे हैं । गड़े हुये भूत उखाड़ेगें तो नंगा यही लोग न होंगे । हमलोग थोड़े नंगा होने वाले हैं । हमारे राज में सब कार्रवाई होती है । इसलिये हम तो माले के साथी लोग से भी कहेंगे कि आप भी अपना बात बोलियेगा तो स्थिर से ही बात बोलियेगा । नहीं तो फिर कहानी शुरू हो जायेगा पहले वाला तो बड़ा दिक्कत है । हुजूर आपने हमको समय दिया इसके लिये आपको धन्यवाद करता हूं । यही कहकर के अपनी बात समाप्त करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल से संशोधन प्राप्त हुये हैं जो नियमानुकूल है । सदन की राय से इनके संशोधनों को पढ़ा हुआ माना जाता है ।

क्र0सं0	प्रस्तावक सदस्य का नाम	प्रस्तावित संशोधन
1.	श्री तेजस्वी प्रसाद यादव स०वि०स० नेता विरोधी दल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़े जायें :- किन्तु खेद है कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित विषयों का उल्लेख नहीं है :- 1. कि जब भारत सरकार द्वारा 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा समाप्त की जा चुकी है, इस परिस्थिति में 2023 में हुए जातिगत सर्वे के आधार पर राज्य में पिछड़े, अतिपिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए कुल 85 प्रतिशत आरक्षण लागू की जाएगी एवं इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराकर केन्द्र सरकार से अनुरोध की जाएगी; 2. कि प्रतिवर्ष राज्य के 25 लाख बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में नौकरियाँ एवं रोजगार दी जाएगी; 3. कि नीट की तैयारी कर रही छात्रा सहित राज्य के अन्य स्थानों पर हो रही प्रतिदिन बलात्कार की घटना को रोका जाएगा; 4. कि राज्य की लचर विधि एवं प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा; 5. कि राज्य के बेरोजगारों को इस वित्तीय वर्ष 10 लाख सरकारी नौकरियाँ दी जाएगी; 6. कि राज्य को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित विशेष पैकेज एवं विशेष राज्य का दर्जा दिलायी जाएगी; 7. कि राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं आर्थिक न्याय प्रदान करने हेतु महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रूपये दिए जायेंगे; 8. कि राज्य के दिव्यांगजन, विधवा एवं वृद्धजनों के सामाजिक सुरक्षा हेतु प्रदान की जानेवाली पेंशन की राशि प्रतिमाह 1500 रूपये की जाएगी; 9. कि राज्य की महिलाओं को आसमान छूती मंहगाई से राहत देने हेतु प्रति गैस सिलेंडर का मूल्य 500 रूपये निर्धारित की जाएगी; 10. कि स्मार्ट मीटर से परेशान जनता को राहत दी जायेगी तथा प्रति परिवार प्रत्येक माह 200 यूनिट मुफ्त बिजली की आपूर्ति की जाएगी; 11. कि राज्य के किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य दिलाने हेतु प्रत्येक उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) दिलाया जाएगा; 12. कि राज्य के जीविका दीदीयों की सेवा को नियमित करते हुए राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा;

13. कि राज्य में नियमित हो रही हत्या, लूट, चोरी, डकैती, रंगदारी, अपहरण, , बलात्कार आदि घटना को रोका जाएगा तथा राज्य में निम्न स्तर पर पहुँच चुकी विधि व्यवस्था में सुधार किया जाएगा;
14. कि दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, महिलाओं एव अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को खत्म किया जाएगा एवं ऐसे दमनकारी ताकतों पर प्रभावी नियंत्रण किया जायेगा साथ ही इनके तमाम स्रोतों को जड़ मूल से उखाड़ फेंका जाएगा;
15. कि पुलिस प्राथमिकी दर्ज नहीं कर राज्य में अपराध की घटनाओं को झुठलाने में लगी है जिसके कारण अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है । पुलिस सही अपराधी को पकड़ने के बजाय बलि का बकरा ढूढ़ कर जांच की दिशा को भटकाने का कार्य करती है, सरकार द्वारा ऐसी कार्यशैली को बर्दाश्त नही किया जाएगा;
16. कि गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों को पुलिसिया तंत्र द्वारा तंग नहीं किया जायेगा तथा पुलिस द्वारा अपने कस्टडी में लेकर प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
17. कि कानून व्यवस्था कायम करने हेतु भूमि सुधार तथा सामाजिक सुधार किए जायेंगे;
18. कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण व्यवस्था लागू की जाएगी;
19. कि राज्य के सभी संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा;
20. कि निजी एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों में नामांकन एवं नियुक्तियों में आरक्षण नियमावली को लागू की जाएगी;
21. कि राज्य में बैकलॉग रिक्तियों को अनारक्षित करने की परम्परा को खत्म किया जायेगा;
22. कि राज्य की सरकारी नौकरियों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु राज्य के स्थायी निवासियों के लिए डोमिसाईल नीति लागू करते हुए 85 प्रतिशत सीट आरक्षित की जाएगी;
23. कि देश भर में बिहारी माइग्रेन्ट श्रमिकों की संख्या को कम किया जायेगा एवं राज्य से बाहर पलायन कर रहे बिहार के युवाओं एवं मजदूरों पर रोक लगाने हेतु प्रभावी कदम उठाया जायेगा साथ ही उन्हें राज्य में ही नौकरी तथा रोजगार दिया जाएगा;
24. कि राज्य की योजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु आवश्यक कार्यबल अगले 6 माह में उपलब्ध कराया जायेगा तथा गरीबों से संबंधित योजनाओं में कटौती नहीं की जायेगी;
25. कि हर घर को नल का जल योजना सहित मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना में भारी पैमाने पर हो रही लूट-खसोट पर रोक लगायी जाएगी;
26. कि सामाजिक न्याय एवं धर्मनिरपेक्षता के आन्दोलन से कमजोर और अभिवंचित वर्गों में आयी सामाजिक-राजनीतिक चेतना को विकसित करने और उसे मूर्तरूप देने हेतु ठोस कार्यक्रम बनाया जायेगा;
27. कि अंधविश्वास, जातिवाद और सांप्रदायवादी ताकतों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का आर्थिक उन्नयन हेतु कार्य किए जाएगें;

28. कि ग्रामीण क्षेत्रों के खेतिहर-मजदूरों और अन्य पेशागत समूहों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा तथा राज्य में खेतिहर मजदूरों और असंगठित मजदूरों के शोषण को रोकने और उन्हें बेहतर जिंदगी जीने के अवसर उपलब्ध कराने हेतु अविलम्ब कारगर कदम उठाये जायेंगे साथ ही परम्परागत पेशे से जुड़े बढ़ई, नाई, लोहार, कुम्हार, बुनकर, धुानकर, चूड़ीवाल, मछुआ, चौरसिया, कामगार एवं रंगरेज भाईयों को उनके आर्थिक विकास के लिये समुचित साधन दिये जायेंगे;
29. कि प्रदेश को जाति और साम्प्रदायिक उन्माद की राजनीति से मुक्त किया जायेगा एवं सामाजिक सामंजस्य एवं सामाजिक समरसता के साथ-साथ सामाजिक न्याय एवं धर्म निरपेक्षता को सही स्वरूप में कार्यान्वित किया जायेगा;
30. कि आजतक प्रदेश के गौरवमय इतिहास का आंशिक ही उद्‌भेदन किया जा सका है। आज भी राज्य के वैसे अनेकों गढ़ जो इतिहास को छिपाये हुए है, उन्हें उजागर किया जायेगा तथा इन गढ़ों को अतिक्रमण से तत्काल मुक्ति दिलाई जायेगी;
31. कि जीएसटी के कारण छोटे व्यवसायियों एवं उद्यमियों को हो रही घाटे की भरपाई राज्य सरकार करेगी;
32. कि शेड सहित नये श्मशान घाट का निर्माण कराया जाएगा एवं सभी श्मशान घाटों की घेराबन्दी कराई जाएगी;
33. कि राज्य में भू-जल स्तर काफी नीचे चला गया गया है, उन इलाकों को चिन्हित कर डीप बोरिंग करायी जाएगी एवं जल पुनर्भरण की व्यवस्था की जाएगी;
34. कि महत्वपूर्ण पदों पर भी अल्पसंख्यक, दलित, महादलितों एवं अति पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारियों को पदस्थापित किया जायेगा;
35. कि अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ योजनाओं की संपूर्ण राशि को ससमय खर्च किया जायेगा;
36. कि अलग से वस्त्र मंत्रालय एवं बुनकर आयोग का गठन किया जायेगा साथ ही नयी प्राथमिक हस्तकरघा बुनकर सहयोग समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू की जायेगी तथा बुनकरों के कल्याणार्थ पूर्व में गठित हस्तकरघा निदेशालय को पुर्नःगठित किया जायेगा;
37. कि अस्पतालों में यूनिफार्म, परदा, गौज एण्ड बैंडेज इत्यादि हस्तकरघा बुनकरों से क्रय किया जायेगा तथा हस्तकरघा बुनकरों के कल्याणार्थ हस्तकरघा निर्मित जनता धोती-साड़ी योजना लागू किया जायेगा;
38. कि बंद पड़ी सभी सूत मिलों को चालू किया जायेगा एवं बिहारशरीफ तथा भागलपुर में क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग समिति लिमिटेड की खाली पड़ी जमीन को हस्तकरघा कम्पलेक्स बनाते हुए पर्यटन सर्किट से जोड़ा जायेगा साथ ही खादी ग्रामोद्योग को सक्रिय किया जायेगा एवं भागलपुर सिल्क इंस्टीच्यूट को युनिवर्सिटी का दर्जा दिया जायेगा;
39. कि बुनकरों को मिल की दर पर धागा सीधे उपलब्ध कराया जायेगा और उनके बनाये कपड़ों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री के लिए बिहार के निर्यातकों को प्रोत्साहन दिया जायेगा;

40. कि सिल्क सूत की सस्ते मूल्य पर सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेशम कीट एवं कंबल-चादर बुनने के लिए भेड़ पालन को बढ़ावा दिया जायेगा;
41. कि पावरलूम बुनकरों पर दशकों से बकाया बिजली बिल माफ किया जायेगा एवं भविष्य में मुफ्त बिजली मुहैया करायी जायगी;
42. कि महिला हिंसा को रोकने हेतु प्रखंड स्तर पर एक त्वरित रिस्पॉस टीम का गठन किया जायेगा तथा जेन्डर बजट की राशि को बढ़ाया जायेगा;
43. कि महिला कामगार एवं असंगठित क्षेत्र की कामगार महिला के नियमित रोजगार एवं कौशल विकास हेतु ठोस कदम उठाया जायेगा;
44. कि राज्य के सभी कार्यालयों में महिला कर्मी के बच्चों के लिए पालना घर बनाया जाएगा;
45. कि सभी शहरी गरीबों के लिए आवास का इंतजाम किया जायेगा;
46. कि प्रत्येक शहरी चौक-चौराहे सहित आईसोलेटेड स्थानों पर कार्यरत महिला पुलिस कर्मियों एवं आमजनों हेतु स्वच्छ शौचालय का निर्माण कराया जाएगा;
47. कि किसानों को उसके उत्पादन का सही दाम मिले एवं किसानों को अपने उत्पाद के भंडारण एवं बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध कराने हेतु कृषि उत्पाद बाजार समिति का पुर्नगठन किया जायेगा तथा किसानों के फसल को उचित मूल्य पर हर हाल में क्रय किया जायेगा;
48. कि किसानों के फसल के लिए फसल बीमा योजना को प्रभावी बनाया जायेगा;
49. कि किसानों को आसान शर्तों एवं सही समय पर बैंकों से रियायती दर पर ऋण मिले इस दिशा में कार्य किए जायेगे तथा किसानों के पूर्व के कर्जों को माफ किया जायेगा;
50. कि किसानो को सही समय और अनुदानित दर पर सिंचाई साधन, खाद, बीज, कीटनाशक दवाई उपलब्ध करायी जायेगी;
51. कि राज्यकृत बैंकों और सहकारी संस्थाओं द्वारा कृषि ऋण एवं अन्य तरह के ऋणों के प्राप्ति में व्याप्त भ्रष्टाचार से किसानों को मुक्ति दिलाएगी;
52. कि कृषि रोडमैप को ईमानदारी से धरातल पर लागू किया जायेगा;
53. कि राज्य के मरणासन्न सहयोग समितियों को पुर्नजीवित किया जायेगा तथा इसे स्वार्थी तत्वों से मुक्ति दिलाई जायेगी;
54. कि वैश्वीकरण के इस दौर में कुटीर उद्योग को जिंदा रखने हेतु इसका नवनिर्माण, संरक्षण और बढ़ावा दिया जायेगा;
55. कि भूमि सुधार हेतु गठित आयोग के रिपोर्ट को लागू करने के लिए भू-हदबंदी कानून में भू-हदबंदी की सीमा घटाई जायेगी और इसे सख्ती से लागू किया जायेगा;
56. कि राज्य के गरीबों के लिए राज्य से बाहर पलायन को रोकने हेतु सरकारी योजनाओं में प्रदत्त न्यूनतम मजदूरी हर स्थिति में खेतिहर मजदूरों और कुशल मजदूरों को उपलब्ध कराया जायेगा;
57. कि राज्य में पिछले 15 वर्षों में लगभग 80 महा घोटालों में गबन की गई राशि की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराते हुए दोषियों को सजा सहित उसकी परिसम्पत्तियों को जब्त किया जायेगा;

58. कि राज्य में जन वितरण प्रणाली को राज्य की जनता की आवश्यकता के अनुरूप किया जायेगा तथा इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण किया जायेगा;
59. कि राज्य में प्रशासन के सभी स्तरों पर हो रही खुलेआम घूसखोरी पर रोक लगाते हुये जनता को राहत दिलाई जाएगी;
60. कि राज्य में कल कारखानों एवं कुटीर उद्योगों का जाल बिछा दिया जायेगा;
61. कि पशुपालकों से दूध, किसानों से तुरंत खराब होनेवाली सब्जियाँ, फलों आदि का सरकार द्वारा उचित मूल्य पर क्रय किया जायेगा तथा प्रखंड स्तर पर दूध एवं दूध से बनी सामग्री तथा फल-सब्जी को संरक्षित रखने हेतु प्रखंड स्तर पर मिनी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जायेगा;
62. कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के जीवन स्तर की बेहतरी के लिए पशुपालन एवं ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया जायेगा;
63. कि सिंचाई हेतु किसानों को सही वक्त पर निशुल्क सतत् बिजली उपलब्ध करायी जायेगी;
64. कि सोन नहर का पक्कीकरण किया जायेगा;
65. कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों को समुचित सुरक्षा प्रदान किया जाएगा एवं अपराधी द्वारा मारे जाने पर उनके परिजनों को मुआवजा, बीमा लाभ एवं पारिवारिक पेंशन सुविधा प्रदान की जाएगी;
66. कि फुटपाथी दुकानदारों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए नही हटाया जायेगा;
67. कि पूर्व सैनिकों को केन्द्र की भाँति राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण दिया जायेगा तथा राज्य के शहीद सैनिक/अर्द्धसैनिकों के परिवार को 10 डिसमिल आवासीय भूखंड दिया जायेगा;
68. कि राज्य मे स्वीकृत पद के विरूद्व संविदा पर नियुक्ति की प्रथा को समाप्त किया जायेगा तथा जीविका कर्मियों एवं जीविका दीदियों के मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा;
69. कि सरकारी नौकरियों में प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी और राज्य के मेहनती एवं मेधावी छात्रों को नौकरी से वंचित करने हेतु बनाए गए अंक आधारित नियुक्ति नियमों को समाप्त करते हुये बीपीएससी एवं बीएसएससी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जायेगा और नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु परीक्षा कैलेन्डर जारी किया जाएगा;
70. कि राज्य में महिलाओं को 35 प्रतिशत दी जानेवाली आरक्षण सिर्फ राज्य की स्थानीय महिलाओं को ही दिया जायेगा;
71. कि राज्य में फर्जी डिग्री लेकर नौकरी पाने वाले पर सख्त कार्रवाई की जायेगी;
72. कि बेरोजगार युवकों के कौशल विकास के लिए विशेष कार्यक्रम को प्रभावी बनाया जायेगा;
73. कि बिहार के सभी गाँवों के सभी घरों में स्वच्छ शौचालय योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जायगा एवं व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जायेगा;
74. कि लेखकों, कलाकारों और पत्रकारों के पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जायेगी;
75. कि कौशल विकास कर प्रतिवर्ष लाखों युवाओं को कुटीर उद्योग स्थापित करने हेतु लोन दिया जायेगा;

76. कि प्रत्येक बाढ़ ग्रस्त प्रखंडों में उँचा चबूतरा एवं शेड बनाकर स्थायीं गृहत शिविर स्थापित किया जायेगा;
77. कि राज्य को बाढ़ और सुखाड़ से सदा-सदा के लिए मुक्ति दिलायी जाएगी;
78. कि राज्य के सभी दियारा क्षेत्रों में नदियों से हो रहे कटाव से बचाव हेतु सम्यक प्रभावी कदम उठाए जायेंगें एवं कटाव स्थलों पर बोल्डर पीचिंग की जाएगी;
79. कि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाया जायेगा;
80. कि स्टूडेन्ट केडिट कार्ड की सीमा बढ़ाई जायेगी एवं इसका लाभ सभी योग्य लाभार्थी को बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया जायेगा;
81. कि राज्य में खेल-कूद के विकास के लिए प्रखंड स्तर पर स्टेडियम का निर्माण कराया जायेगा;
82. कि विश्वविद्यालयों में परीक्षा ससमय लेते हुए सत्र को नियमित किया जायेगा;
83. कि महाविद्यालयों/चिकित्सा महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के खाली पड़े पदों पर आयोग के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा कराकर शीघ्र नियमित नियुक्तियाँ की जाएगी;
84. कि डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट जैसे पदों पर संविदा के आधार पर न कर आयोग के माध्यम से परीक्षा आयोजित कर नियुक्तियाँ की जाएगी;
85. कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु दी जानेवाली छात्रवृति ससमय एवं पूर्ण राशि प्रदान किया जायेगा;
86. कि कुपोषण एवं टी०बी० को खत्म करने हेतु योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा;
87. कि नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ के प्रशिक्षण हेतु राज्य के सभी जिला में सरकारी प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेगें;
88. कि अति पिछड़ा जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों को प्रधानमंत्री आवास योजना (इंदिरा आवास) प्राथमिकता के आधार पर मुहैया कराया जायेगा;
89. कि प्रतिवर्ष भिखारी ठाकुर पुरस्कार एवं हीरा डोम पुरस्कार प्रदान किया जायेगा एवं बिहार लोक साहित्य को बचाने के लिए फेलोशीप अवार्ड शुरू किया जायेगा;
90. कि वायुप्रदूषण पर निगरानी रखने हेतु एयर क्वालिटी मॉनीटरिग स्टेशन, गंगा व जल प्रदूषण मॉनीटरिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जाएगी तथा वायु प्रदूषण निगरानी हेतु विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी;
91. कि अल्पसंख्यक समाज में बालिकाओं की शिक्षा दर बढ़ाने के लिए मध्य/उच्च उर्दू कन्या विद्यालय खोले जायेंगे;
92. कि अल्पसंख्यक विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों तथा मदरसा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सरकारी विद्यालयों के समान वेतन एवं अन्य सुविधाएँ दी जायेगी साथ ही संविदा पर कार्यरत कर्मियों को समान काम के लिए समान वेतन दी जायेगी;
93. कि सभी कब्रिस्तानों को अतिक्रमण से मुक्त कराकर घेराबंदी करायी जायेगी ;
94. कि अल्पसंख्यकों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के निजी एवं सार्वजनिक हितों के प्रति भेदभाव बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी;

95. कि प्रत्येक पंचायत में एक मॉडल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी;
96. कि बाबा साहेब अम्बेडकर, दशरथ मांझी, ई० पेरियार, कांशीराम, राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी, ज्योतिबा फुले और संत रविदास जी जैसे महापुरूषों की जीवनी और आदर्शों को स्कूली पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा;
97. कि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के नौकरी पेशा लोगों को भी प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा;
98. कि बिहार में कार्यरत सभी टोला सेवकों, ममता कर्मियों, आशा कर्मियों, जीविका दीदियों, मध्याह्न भोजन योजना की रसोईयाँ अन्य संविदा आधारित सेवकों को नियमित करते हुए मासिक वेतनमान निर्धारित किया जाएगा;
99. कि विकास मित्रों को पंचायत सेवकों की तर्ज पर वेतनमान दिया जायेगा;
100. कि खास महाल की अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराई जाएगी;
101. कि पशुधन बीमा योजना एवं राईट टू एनीमल हेल्थ योजना लागू की जाएगी;
102. कि राज्य के विभिन्न स्थलों को चिन्हित करते हुए फूड प्रोसेसिंग एवं आई०टी० पार्क की स्थापना की जाएगी;
103. कि राज्य में पदस्थापित पदाधिकारियों, कर्मचारियों को जातीय आधार पर तंग तबाह नही किया जाएगा तथा खासकर जिलों एवं प्रखंडों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियमानुसार कार्य करने दी जाएगी;

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, नेता विरोधी दल 05 फरवरी को बोलेंगे । माननीय सदस्य श्री मनोहर प्रसाद सिंह जी। आपका समय 06 मिनट है ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में सरावगी जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसके विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी–बड़ी बातें कही गयी और बहुत बड़े–बड़े सपने दिखाये गये और विकास की बहुत सी बातें की गयी । मैं सदन से सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के विषय में उनका क्या कहना है...

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखें । सुनिये ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी–भी नामांतरण के लिये कम से कम 20 हजार रुपये लिये जाते हैं, तभी नामांतरण होता है । परिमार्जन के लिये रुपये लिये जाते हैं । मैं और कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये 10 हजार से कम रुपये नहीं लिये जाते हैं, जब तक नहीं दिया जायेगा उसका नामांकित नहीं होगा । यह स्थिति है । इस भ्रष्टाचार में किस तरह सुशासन की बात कही जा सकती है ।

महोदय, शिक्षा के विषय में कहा जा रहा है कि बहुत शिक्षक की बहाली हुई लेकिन शिक्षक का जो स्थानांतरण हुआ, अब स्थानांतरण के बाद ऐसी स्थिति आ गयी है कि शिक्षक लोग जो यू0पी0 वगैरह के थे सबको बार्डर में पदस्थापित कर दिया गया है और यहां स्कूल खाली हो गया है । अब एक स्कूल में एक शिक्षक, दो शिक्षक ही रह गये हैं । कम से कम उसकी व्यवस्था कर देनी चाहिये कि जहां कम शिक्षक हैं दूसरे जगह से भेजा जाए । पहले जो स्थिति थी वही स्थिति आ गयी है । इसलिये शिक्षा के विषय में मैं यह कहना चाहता हूं ।

हेल्थ के विषय में कहा गया कि बहुत से रोगी आते हैं इलाज कराने के लिये । सबसे बड़ी बात यह है कि इलाज कराने के लिये क्या आयेंगे, वहां तो दवाई ही नहीं मिलती है । डॉक्टर ही नहीं रहते हैं तो ईलाज क्या करायेंगे । डॉक्टर की इतनी कमी है कि अनुमंडलीय अस्पताल, मनिहारी में 22 डॉक्टर की पदस्थापना होनी चाहये, वहां 04 डॉक्टर हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बिना अनुमति के मत बोलिये, बैठिये ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : अब 04 डॉक्टर से कैसे वहां के सेवाएं चल सकती है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठकर मत बोलिये ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : इसलिये जहां डॉक्टर नहीं हैं डॉक्टर भेजे जाएं । प्राथमिक उपचार केन्द्र है वहां पर भी डॉक्टर नहीं है । जहां लेडी डॉक्टर होनी चाहिये वहां लेडी डॉक्टर नहीं है । स्वास्थ्य के विषय में भी यही स्थिति हो गयी है ।

दूसरी स्थिति यह है कि नल–जल–योजना की बात कही गयी। नल–जल–योजना के बारे में कहा गया है कि सब जगह नल–जल पहुंचा दिया गया । लेकिन जहां नल है वहां जल नहीं है और जहां जल है वहां नल नहीं है । सब जगह सिर्फ खड़ा कर दिया गया है, कहीं चलता नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली के संबंध में यह बात कही जा रही है कि घर–घर बिजली पहुंचा दी गयी है । लेकिन कई जगह ऐसा है कि तार ही नहीं गया है और जहां तार गया है वहां पोल है ही नहीं । बांस के खंभे पर तार लटका कर लोग ले गये हैं ।

(व्यवधान)

दूसरी बात है । मैं अभी की बात बोल रहा हूं । 125 यूनिट बिजली बिल फ्री कर दिया गया है लेकिन उनको इतना बिल आता है कि हालत खराब हो जाता है । 25 हजार, 30 हजार बिल आता है एक गरीब का जो दो बल्ब जलाता है और बिजली का बिल लिये लोग दौड़ा फिरता है । हमलोगों से कहता है तो हमलोग जे0ई/एस0डी0ओ0 कहते हैं कि इसको देखिये, इसमें

संशोधन करिये । गरीब आदमी इतना बिल कहां से देगा तो उसमें लोग संशोधन करते हैं । बिजली की भी यही स्थिति है ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री रामकृपाल यादव, मंत्री : बिजली बिल 25 हजार, 30 हजार आ रहा है । आपके पास कोई एग्जाम्पल है तो दे दीजिये ।

अध्यक्ष : मनोहर बाबू...

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : मैं एग्जाम्पल दे दूंगा । मैं इतना एग्जाम्पल दूंगा की आपके समझ में नहीं आ पायेगा ।

अध्यक्ष : मनोहर बाबू, जो हमारी जानकारी है कि सरकार शिविर भी लगा रही है और मैं शिविर में स्वंय भी गया था । बिल में जहां त्रुटि होती है तो हर जिले में ऊर्जा विभाग के द्वारा शिविर लगाकर आवेदकों की सुनवाई सुनी जाती है ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : यह ठीक बात है । मैं इसका समर्थन करता हूं ।

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

हमलोग कहीं शिविर नहीं देखते हैं । हमलोगों के यहां जो जनता आती है उसको हमलोग जुनियर इंजीनियर के पास भेजते हैं, एस0डी0ओ0 के पास भेजते हैं, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास भेजते हैं और कहते हैं कि देखिये गरीब आदमी कहां से इतना बिल देगा । तो वह लोग कैसे–कैसे सुधार करके उसको थोड़ा–सा राहत देते हैं । लेकिन समान्य रूप से मैं यह कह रहा हूं कि इस तरह की बात होती है । इसलिये जो बात कही जा रही है जैसे मैं कहता हूं कि कटाव है । कटाव की इतनी समस्या है कि गांव का गांव कट गया । मैंने विधान सभा में भी प्रश्न उठाया था जो दुरियाई पंचायत में हुआ था । सदन में कहा गया कि नहीं उसका कटाव हमलोग रोक देंगे ।

(क्रमशः)

टर्न–17 / धिरेन्द्र / 03.02.2026

....क्रमशः....

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : महोदय, कटाव जब शुरू हुआ तो मैंने फिर कहा कि कटाव हो गया है, इसको चालू कीजिये नहीं तो फिर कट जायेगा । अभी 100 घर कट गये हैं और वह पूरा का पूरा गांव कटने की स्थिति में है । अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है । अभी भी कहा जाता है कि 15 करोड़ की योजना भेजी गयी है, स्वीकृति मिलेगी तब उस पर काम होगा ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके पास मात्र एक मिनट का वक्त है ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : महोदय, ठीक है । चनपटिया विधान सभा में कमारबाग थाना, मानव तस्करी की बात कही गयी है चनपटिया विधान सभा के अंतर्गत । महोदय, यह सही है कि सरकार के द्वारा जो काम होता है हमलोग उसकी प्रशंसा करेंगे लेकिन जो काम जनता के लिए होना चाहिए वह काम नहीं होगा तो हमलोग निश्चित रूप से उसकी आलोचना करेंगे और निश्चित रूप से

उनकी जो त्रुटि है उसको बतायेंगे । महोदय, कुछ इस तरह की त्रुटियां हैं, अब जैसे विस्थापित लोग 20–20, 25–25 साल से बैठे हुए हैं लेकिन किसी को भी मकान नहीं दिया जा रहा है और न ही जमीन दी जा रही है । अब बेचारे विस्थापित कहां जायं । बांध पर बैठे हुए हैं 20–20, 25–25 वर्षों से, इस पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए । महोदय, इसीलिए जो प्रस्ताव दिया गया है मैं उसका विरोध करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि जो जनसमस्या है, उन जनसमस्याओं को दूर करने का प्रयास करें और सिर्फ कागजी कलम चलाने से काम नहीं चलेगा, जो वास्तविकता है स्थानीय स्तर पर जो काम होना चाहिए, वह होना चाहिए । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता जी, आप अपना पक्ष रखें । आपके पास नौ मिनट का वक्त है ।

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आसन के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूँ और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूँ कि आज मुझको उन्होंने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया ।

महोदय, इस सदन में काफी देर से इस विषय पर चर्चा हो रही है और राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बात रखने की बात है तो मैं इसके समर्थन में आज खड़ा हूँ । सबसे पहले इस अभिभाषण में स्पष्ट है कि किस प्रकार से 10 हजार रुपया प्रत्येक महिलाओं को देकर रोजगार सृजित करने का काम किया गया है । यह सोच आप लोगों को आ भी नहीं सकती है । आपलोग उसको महीना, दो हजार का फार्म भरवा रहे थे....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, टोका–टोकी नहीं कीजिये । आपका जब वक्त आयेगा, तब आप बोलेंगी ।

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता : महोदय, घूस देने के लिए दो हजार का फार्म भरवा रहे थे लेकिन हमारी सरकार ने यह सोची कि हम इनको स्वावलंबी बनायें और इनको रोजगार दें । इसलिए उनको दस हजार रुपया इनिशियल पैसा दिया और आगे की ओर फिर उनको दो लाख रुपया जो रोजगार करेगा उनको देने के लिए कमर कसी हुई है । आपका अभी ही पसीना छूट रहा है जब दो लाख रुपया उन महिलाओं को मिलेगा और वे जब बिहार के विकास में भागीदार बनेंगी तब आपको समझ में आयेगा कि बिहार कहां जा रहा है । आपलोगों की समझ से यह बाहर का विषय है । महोदय, मैं इस योजना की भूरि–भूरि प्रशंसा करता हूँ ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठे–बैठे नहीं बोलें ।

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता : महोदय, प्रदेश की आधी आबादी को जिस प्रकार से सरकार ने इसमें जोड़ने का काम किया वह काफी ही सराहनीय काम है और प्रदेश के विकास के लिए दूसरी जो बिजली, बिजली जो प्रदेश के विकास के लिए होता है उसको हर घर बिजली पहुंचाने का काम इन्होंने किया है । हर घर बिजली पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया और वही काम, बात नहीं रूकी है श्रीमान्, अब लोग हमलोगों से यह पैरवी करते हैं कि हमारे खेतों में जो बिजली है उसके वोल्टेज को ठीक करवा दीजिये ताकि मोटर ठीक से चले । घर की बिजली की बात अब समाप्त हो गई अब खेतों की बिजली की बात चल रही है कि इस खेत में बिजली भिजवा दिया जाय, उस खेत में बिजली भिजवा दिया जाय । यह जो सरकार है, पिछली सरकार और इस सरकार में बहुत अंतर है । सरकार जो अब बोलती है उसको करती है, सरकार ऐसा नहीं है कि कुछ बोल दिया जैसे अभी चर्चा चल रही थी कि बहुत से चरवाहा विद्यालय, ये किया, वो किया । सरकार बोलती नहीं है, जो सरकार बोलती है उसको धरती पर लागू कर के बताने का काम करती है । महोदय, हम किसानों की आमदनी को दोगुना करना चाहते हैं तो उस पर हम काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से किसान की आमदनी दोगुनी होगी, उसका सबसे ज्यादा खर्च पटवन में आता था और उस पर हमलोगों ने विचार किया कि उसको जब हम बिजली दे देंगे तो उसके पटवन का खर्च शून्य हो जायेगा और तब जाकर उसकी आमदनी दोगुनी होगी, इसलिए इस विषय को समझने की आवश्यकता है । 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया और सात निश्चय–3, इसको पूरी समझने की आवश्यकता है । सात निश्चय–3 देखा जाय, इसमें साफ–साफ है रोजगार, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, मजबूत आधार और सबका सम्मान ease of living ये सात चीजें हैं । इस सोच की सराहना यहां से की जानी चाहिए जो इस सोच के तहत रोजगार और आय को दोगुनी करना । रोजगार और आय कैसे दोगुनी होगी ? उसका यही है कि जब हमारे घर की महिलायें भी उसमें सहयोगी बनेंगी तो आय दोगुनी होगी और उसी का यह स्वरूप है और उसके बाद से आप देखिये उद्योग....

(व्यवधान)

आप तो चाह ही रही हैं कि महिलाओं को घर में बंद कर हमलोग रखें, ऐसा नहीं होने जा रहा है । अब महिलायें इस सरकार में कदम से कदम मिलाकर साथ चलती हैं और इस देश और राज्य के विकास में हाथ बंटाती हैं ये महिलाओं की अब स्थिति है । दूसरी बात आ रही है कि जब आप जाइयेगा गांव देहात में तो पहले क्या स्थिति थी, जब रास्ते में याद होगा भूल जाते थे, गाड़ी अगर कुहासा में आपकी पड़ गयी तो कहीं एक डिबरी लौकती थी, उस डिबरी को देखकर आदमी वहां जाता था और पूछता था कि फलना गांव का रास्ता हम भूल गईल बानी, केने जाई, अभी क्या स्थिति है ? गांव में बत्ती तो

छोड़ दीजिये, हर गांव में अब ए॰सी॰ लग रहा है, ए॰सी॰ लगाने का काम चल रहा है । फ्रिज, ए॰सी॰ ये गांव देहात में, गांव से पलायन रूका है, बिजली होने के चलते वहां रोजगार सृजित हो रहा है, मेरे मित्रों इसको समझने की आवश्यकता है । सबका साथ, सबका विकास, विशेष कर पिछड़े, अति–पिछड़े दलित सभी को साथ लेकर चलने वाली जो यह सरकार है, ये हमारे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की भी यही आशा थी और इसी से यह मिलता जुलता विकास है कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जिस झोपड़ी में कोई रौशनी करने वाला नहीं है । ये शुरू से हमलोगों का ऐम रहा और उसका ही नतीजा है कि आज हम इस सरकार के साथ अडिग एन॰डी॰ए॰ के रूप में खड़े हैं, हमारी पार्टी खड़ी है और इसके साथ कदम से कदम मिलाकर बिहार के विकास के लिए काम करने का संकल्प ले रही है । अब आप आइये, उद्योग में पहला कैबिनेट जब इस सरकार का हुआ तो पहले कैबिनेट में सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम 25 चीनी मिल खोलेंगे, इसको समझने की आवश्यकता है । सरकार कितनी संकल्पित है कि 25 चीनी मिल, अब हम इस विवाद में नहीं जाना चाहेंगे कि कब बंद हुआ, कैसे बंद हुआ, किस समय में बंद हुआ, यह दूसरा विषय है । कब बंद हुआ, कैसे बंद हुआ, किन कारणों से बंद हुआ, यह तो आप बताइयेगा ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शांति बनाये रखें ।

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता : महोदय, लेकिन हमको इसको खोलना है । हमलोगों ने यह संकल्प लिया है कि चीनी मिलों को खोलेंगे....

(व्यवधान)

सभी चीनी मिलों को, 25 चीनी मिल हमलोग नया सृजित करेंगे और उस दिशा में कार्रवाई प्रारंभ है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आसन की ओर देखें ।

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता : महोदय, आज हम इथनॉल बनाने में देश के अव्वल राज्यों में आ चुके हैं । यह चीज आपको समझ में नहीं आयेगा । उद्योग जो है इथनॉल बनाने में हम देश के अव्वल राज्यों में आज हैं, इस चीज को समझने की आवश्यकता है, ये आपके समझ से बाहर है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप शांति बनायें ।

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता : महोदय, लौरिया खुला, सुगौली में एच॰पी॰सी॰एल॰ खुला है मेरे मित्रों, इसको समझने की आवश्यकता है । हम संकल्प लिये हैं कि हर....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आसन की ओर मुखातिब हों । आसन की ओर देखकर बोलिये ।

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता : महोदय, सरकार ने संकल्प लिया है कि हर जगह पर हम बियाडा के माध्यम से उद्योग लगायेंगे और उद्योग के लिए जमीन चिन्हित किया जा रहा है । मैं यहां से सदन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, नेता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वी चम्पारण में उद्योग के लिए जमीन नहीं था लेकिन वहां भी 1300 एकड़ जमीन हमारे रामगढ़वा में चिन्हित कर लिया गया है । हम अभी पीछे हैं और हमारे काम करने की सरकार की क्षमता आगे की ओर चल रही है इसको समझने की आवश्यकता है । हम उद्योग लगाने का संकल्प ले रहे हैं, हम उसको सड़क से जोड़ने का संकल्प ले रहे हैं, सरावगी जी, वरीय नेता इसी विषय को कह रहे थे कि बड़ी–बड़ी सड़कों को रक्सौल से और...

(व्यवधान)

टर्न–18 / अंजली / 03.02.2026

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना आसन ग्रहण करें, आपका समय हो गया है । माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं । आपका समय हो गया है ।

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता : मैं आसन के प्रति अपना धन्यवाद और अपने नेता के प्रति धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहां समाप्त करता हूं कि जो विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के रूप में हमारे नेता लेकर के चल रहे हैं ।

उपाध्यक्ष : आप बैठ जाएं माननीय सदस्य ।

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता : उसी के समरूप यह सरकार चल रही है ।

उपाध्यक्ष : अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता : कदम से कदम मिलाकर के सरकार के साथ चलने का काम करेंगे । धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मो॰ तौसीफ आलम जी, आप अपना पक्ष रखें । आपके पास 5 मिनट का वक्त है ।

श्री मो॰ तौसीफ आलम : जी हुजूर । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने ख्याल का इजहार करने के लिए खड़ा हुआ हूं । माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार का बयान होता है । आज पूरे बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है । महोदय, चूंकि 5 मिनट का समय है, सब बात बोलनी पड़ेगी । हमारे सीमांचल किशनगंज के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, जबकि पूरे हिंदुस्तान लेवल पर देखा जाय स्वास्थ्य विभाग पर, तो पूरे हिंदुस्तान लेवल में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट हमारे किशनगंज जिला सीमांचल में पाया जाता है । एक भी कैंसर हॉस्पिटल वहां नहीं है, न ही वहां कैंसर की कोई दवाई मुहैया कराई जाती है और हमारे किशनगंज में खासकर देखा जाय बाढ़ क्षेत्र है, वर्ष 2017 में जब बाढ़ आई थी तो पूरा किशनगंज जिला बाढ़ से प्रभावित हो गया था, 104 जगह जो रोड की

कटिंग हुई है धरातल में आज तक वहां कटा हुआ है और खासकर के हमारे क्षेत्र में, 7 पंचायत में नदी कटाव है । 7 पंचायत हर साल नदी कटाव से पीड़ित हो जाता है, गांव का गांव काटकर लेकर चला जाता है और जल संसाधन मंत्री जी भी हैं, मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हर साल नदी कटाव में बोरा से, बांस से जो बांधा जाता है, यह फौरी तौर पर बनाया जाता है और दूसरा बरसात में फिर से बनाया जाता है तो मैं चाहूंगा कि बोल्डर पिचिंग का निर्माण हो ताकि हमेशा के लिए जो बाढ़ पीड़ित की समस्या आती है वह न आए और दूसरी बात और भी है जो कि उद्योग से है । हमारे किशनगंज जिला में एक भी उद्योग नहीं खोला गया है, किशनगंज सीमांचल को हमेशा इग्नोर किया जा रहा है । माननीय राज्यपाल महोदय जी बहुत सारे भाषण किए हैं, बहुत अच्छी बात है लेकिन जो कमी है हमारे बिहार में उसको हम छिपा नहीं सकते हैं । हमारे नीट छात्रा के साथ जो घटना हुई है इसको हम छिपा नहीं सकते हैं, पूर्णियां में दिन–दहाड़े जो मर्डर हुआ है, आज तक अपराधी पकड़ा नहीं गया । इसी तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं जैसे कि हमारे क्षेत्र में प्रदूषण से अपंग बच्चा पैदा होता है और नस्ल और फसल दोनों खराब हो जाता है, कम से कम 5 सौ भट्टा हमारे जिला में है और नियम के तहत नगर में भट्टा नहीं होना चाहिए । हमारे बहादुरगंज क्षेत्र में कम से कम 25 भट्टा है, क्या सरकार इस पर ध्यान देगी ? दूसरा यह है कि हमारे क्षेत्र में आम नहीं होता है, कटहल नहीं होता है और जो बच्चे पैदा होते हैं वह अपंग पैदा होते हैं इसलिए हम चाहेंगे कि इसका भी उसमें कोई प्रावधान लाए सरकार जिससे वहां जो ईंटा तस्करी होती है, बिहार में बनता है और बंगाल तस्करी होता है उसको रोका जाय, उसके लिए सरकार को भी ध्यान देना चाहिए था और रहा सवाल हमारे क्षेत्र का खासकर के जो सात पंचायत हैं जिसके बारे में मैंने जिक्र किया मैं गांव गिनाना चाहूंगा पत्थरगट्टी में दिघलबैंक प्रखंड आता है, पत्थरगट्टी में एक गांव है जो कटाव से नदी में चला गया है, आज तक वह गांव बांधने का काम नहीं हुआ है । दूसरा है, मटियारी पंचायत, उसके बाद है महेशबथना पंचायत, उसके बाद है खारीटोला, बोचागाड़ी, सतमेरी, लौचा, यूनिस टोला, इसी तरह से पूरा गांव नदी की कटाव के चपेट में है । मैं चाहूंगा कि सरकार उसके लिए, बोल्डर पिचिंग के लिए कुछ लाए ताकि हमारा गांव बच जाए और रहा सवाल हमारे जिला में ज्यादातर जो केवाला होता है, जो म्यूटेशन होता है, केवाला में उर्दू से लिखा हुआ है, हम चाहेंगे कि रजिस्ट्री ऑफिस में उर्दू ट्रांसलेटर हो ताकि जो पुराना केवाला है उसमें उर्दू में लिखा जाय । थाना में भी इसी तरह से उर्दू में अगर कोई दरखास्त जाता है तो उसमें नकार दिया जाता है, उसको फेंक दिया जाता है, हम चाहेंगे कि उर्दू ट्रांसलेटर का भी थाना में...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके पास मात्र एक मिनट का वक्त है ।

श्री मो॰ तौसीफ आलम : ठीक है । अब रहा सवाल, बिहार के बहुत सारे मसले हैं जिसमें मैं बोलना चाहूंगा कि किसानों को उनके उत्पादन के लिए सही मूल्य नहीं मिल रहा है, मक्का, हमारे किशनगंज जिला में जो मक्का की खेती होती है उसके लिए वहां कोई फैक्ट्री नहीं है, हम चाहेंगे कि वहां उद्योग का निर्माण हो ताकि वहां के किसानों को सही, उचित मूल्य मिल सकें । अस्पतालों में जो चिकित्सालय है वहां दवाई उपलब्ध नहीं किया जाता है, खासकर कुत्ता काटने वाले मरीज जाते हैं, सांप काटने वाले मरीज जाते हैं, बहादुरगंज में इस तरह के मामले आये हैं, बहादुरगंज अस्पताल में सांप काटने वाला दवाई नहीं मिली जिसके कारण वहां का मरीज मर गया, हम चाहेंगे कि यह अस्पताल जो बहादुरगंज का है, इसमें जो डॉक्टर पदस्थापित था उसकी जवाबदेही बनती है जबकि नियम है कि हर अस्पताल में सांप काटने वाली और कुत्ता काटने वाली दवाई होनी चाहिए । उसकी जान चली गई इसका जिम्मेवार कौन है ? बिहार सरकार है या उसके पदाधिकारी हैं, अगर उनके पदाधिकारी है तो वह जवाब दे या उन पर आवश्यक कार्रवाई हो ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री मो॰ तौसीफ आलम : ठीक है हुजूर मैं करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, यही कहूंगा कि बहुत सारे मसले हैं लेकिन 5 मिनट का ही समय था लेकिन इतना ही कहूंगा जो बात हमने कही है इस पर कुछ अमल हो तो अच्छी बात है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अरूण बाबू । आप अपना पक्ष रखें । आपके पास में 2 मिनट का वक्त है ।

श्री अरूण सिंह : जी–जी । उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण में जिन बातों पर बहुत जोर दिया गया है वह है वर्ष 2005 के बाद बिहार के विकास का रफ्तार बढ़ा है । एक है कानून का राज स्थापित हुआ है और तीसरा है कि दृढ़ इच्छा शक्ति वाली यह सरकार है इसी के इर्द–गिर्द पूरी बात राज्यपाल के अभिभाषण में है । मैं कहना चाहता हूं कि 2005 के बाद भूमि सुधार आयोग का गठन हुआ था डी॰ बंधोपध्याय के नेतृत्व में । डी॰ बंधोपध्याय के नेतृत्व में जो भूमि सुधार आयोग का गठन हुआ उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है । यह क्यों हुआ ? मैं बताना चाहता हूं, उस समय जो भू–माफिया हैं उनके दबाव में ये सारी चीजें रोक दी गईं । इच्छा शक्ति तो पता चल गई, कैसी इच्छा शक्ति है । (क्रमश :)

टर्न–19 / पुलकित / 03.02.2026

(क्रमश:)

श्री अरूण सिंह : महोदय, दूसरा है कि सरकार आजादी के तुरंत बाद भूमिहीनों के आवास के लिए 1948 में एक कानून पी.पी. एक्ट बना था । खुद ये सरकार बार–बार कहती रही है विधानसभा के अंदर कि हम पांच डिसमिल जमीन भूमिहीनों को

बसने के लिए देंगे । इसके बाद उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बार–बार कहा है कि सरकार जब तक बसाएगी नहीं तब तक उजाड़ेगी नहीं। लेकिन कानून का पालन नहीं हो रहा है । उजाड़ दिया जा रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं, नया नाम आया है बुलडोजर । बुलडोजर से ढाह दिया गया है। कौन सा राज है ? कौन सा कानून का पालन कर रहे हैं ? कह रहे हैं कि कानून का राज है । किस कानून की बात कर रहे हैं आप ? कानून तो हम नहीं देख रहे हैं कोई कानून है ।

हम देख रहे हैं कि उनके हितों की रक्षा, बिहार सरकार अपनी हितों की भी रक्षा नहीं कर पा रही है । जैसे मांग पर आधारित मनरेगा योजना था, उसके स्वरूप बदल दिए गए । मैं नाम पर कोई बहस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वह मांग पर आधारित कानून था और बिहार के लिए ज्यादा प्रभावशाली था । उस कानून को बदल दिया गया । एक शब्द बिहार की सरकार यह बात बोलने के लिए तैयार नहीं हुई कि ये गलत है ।

(व्यवधान)

मांग पर आधारित खत्म कर दिया गया और 40 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार को देना पड़ेगा । कहां से देगा ? बिहार सरकार के पास पैसे नहीं हैं। ये तो बिहार के लिए, झारखंड के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए योजना थी।

उपाध्यक्ष : अरूण बाबू, आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री अरूण सिंह : लेकिन सरकार इस पैसे पर बोली नहीं ।

उपाध्यक्ष : कृपया आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, विश्वविद्यालय खोलने की बात थी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन वह नहीं हुआ । फिर नए उद्योग कहीं लगे नहीं । न चीनी मिल खुली, न डालमियानगर उद्योग जैसे पुंज खुले । कहां कोई नया उद्योग लगा ?

(व्यवधान)

धान अधिप्राप्ति पर न किसान खुश हैं, पैक्स अध्यक्ष के लोग तो रो रहे हैं कि हमारा अभी तक किसी ऑफिस में अटैच नहीं हो पाया ।

उपाध्यक्ष : अरूण बाबू अपना आसन ग्रहण करें ।

माननीय सदस्य श्री बबलू कुमार जी, आपके पास पांच मिनट का समय है ।

श्री बबलू कुमार : धन्यवाद सर । सर्वप्रथम हम अपने नेता नीतीश कुमार जी और खगड़िया विधानसभा की जनता का आभार प्रकट करते हैं कि हमें महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर समर्थन में हमें बोलने का मौका मिला ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सरकार की नीतियों, योजनाओं एवं भविष्य की प्राथमिकताओं का स्पष्ट उल्लेख किया गया है । मैं इस अभिभाषण पर अपनी कुछ बातें सदन के समक्ष रखना चाहता

हूँ । मैं इस गरिमामय सदन के माध्यम से राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करता हूं और यह अभिभाषण केवल औपचारिक वक्तव्य नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य का रोडमैप है ।

मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को नमन करता हूं जिनके मार्गदर्शन में और सहयोग से बिहार में अभूतपूर्व विकास कार्य संभव हो पाया है । केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से आज बिहार विकास की तेज रफ्तार पकड़ चुका है । माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने आगामी 5 वर्षों में 2025 से 30 के लिए श्सात निश्चय–3 के रूप में एक स्पष्ट विजन प्रस्तुत किया है, जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के विजन को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

पहला निश्चय दो गुना रोजगार और दो गुनी आय । बिहार के युवाओं और गरीब के परिवारों के लिए आशा की एक किरण है ।

दूसरा निश्चय समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार । इसके अंतर्गत हर जिले में औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है ।

तीसरा निश्चय कृषि में प्रगति के प्रदेश के समृद्ध किसानों को आय बढ़ाने की ठोस प्रतिबद्धता है ।

चौथा निश्चय उन्नत शिक्षा, उज्ज्वल भविष्य । इसके तहत हर प्रखंड में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज तथा पटना में एजुकेशन सिटी का निर्माण भविष्य की नींव रखेगा ।

पांचवा निश्चय सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन । इससे स्वास्थ्य सेवाएं गांव तक पहुंचेगी ।

छठा निश्चय मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार । सड़क, एक्सप्रेस–वे और पर्यटन विकास को नई ऊंचाई देगा ।

सातवां निश्चय सबका सम्मान, जीवन आसान, सुशासन । यही इज ऑफ लिविंग संकल्प है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार कथनी नहीं करनी में विश्वास रखती है । मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण नए बिहार के निर्माण में संकल्प पत्र है । हम अपने नेता नीतीश कुमार जी का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत–बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष श्री अजय कुमार । आपके पास एक मिनट का वक्त है, गागर में सागर भरने का ।

श्री अजय कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय जो अपने भाषण को रखते हैं, वो सरकार के द्वारा स्क्रिप्ट जो तैयार होता है उसी को रखते हैं । महोदय, संजय सरावगी जी बता रहे थे बिहार के विकास के लिए बहुत सारे मंदिर का निर्माण किया गया है । मंदिर का मैं कोई विरोध नहीं करता, लेकिन मंदिर के

साथ–साथ लोग जो बेरोजगार हैं उसको रोजगार के लिए अगर कल–कारखाने का निर्माण किया जाता, तब वास्तविक में बिहार का विकास का रास्ता खुलता, यह हम कहना चाहते हैं ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हॉस्पिटल, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम को गिनाए थे राज्यपाल महोदय । मुझे तो लगता है कि जब मैं 2020 में सदन में आया था, हर बार उनकी स्क्रिप्ट को, भाषण को मैं सुनता हूं, उसी को दोहराते जाते हैं । मेरा कहना है कि जो पी0एम0सी0एच0 एक बड़ा हॉस्पिटल, जहां 5000 बेड से ज्यादा की वहां बात की जा रही है और उस पर पूरी तौर पर कहा जा रहा है कि बिहार के अंदर जो स्वास्थ्य का सवाल है वह पूरा हो जाएगा, उससे पूरा नहीं होगा ।

जरा इसको सोचिए, जब इलाके से आते हैं, प्रखंड से आते हैं, जिला से आते हैं और आई0जी0आई0एम0एस0 में एक बेड नहीं मिलता और बेड के लिए जब विधायक को फोन करता है और विधायक को किसको फोन करना पड़ता है ? सुपरिटेंडेंट को या हेल्थ मिनिस्टर को । उसके बाद तब जाकर के एक बेड मिलता है । क्या यही विकास हो रहा है ? स्वास्थ्य के क्षेत्र में यही काम हो रहा है ?

हम आपसे कहना चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री जी, आपको मुखातिब होकर के मैं कहना चाहता हूं...

उपाध्यक्ष : माननीय अजय बाबू आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री अजय कुमार : सर, 30 सेकेंड का समय दिया जाए । मैं एजुकेशन पर मैं बोल रहा हूँ । बिहार में शिक्षा का विकास कैसे होगा ? कॉलेज के अंदर 30 प्रतिशत सीट शिक्षकों के जो पद है वे खाली पड़े हुए हैं । शिक्षक जो हैं कई विषय में शिक्षक नहीं हैं, लेकिन फॉर्म भरे जाते हैं । परीक्षा होती है, वो पास करता है । कैसे वो पास कर रहा है ? यह बहुत बड़ी चिंता का सवाल है ।

उपाध्यक्ष : आपका समय बीत हुआ । आप कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री अजय कुमार : लास्ट सर, कृषि के दो गुना आय की बात जो की जा रही है...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार सिंह यादव जी । आपके पास में एक मिनट का वक्त है ।

श्री अजय कुमार : सर, पांच सेकेंड के बारे में हम कहना चाहते हैं । कृषि के बारे में बस इतना ही कहना है कि जब तक आप कृषि के क्षेत्र में...

(व्यवधान)

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : मैं उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को शुरू करता हूं । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बहुत सी बातों को रखा गया । उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं तमाम मुद्दों को रखा गया । महोदय, हमारे जिले में स्वास्थ्य के मामले में, हम लोगों का जिला कैमूर जिला अंतिम छोर उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है । वहां पर प्रखंड अस्पताल और प्राथमिक

अस्पतालों की तो बात छोड़िए, कैमूर सदर अस्पताल की स्थिति यह है कि वहां पर कोई भी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर, न न्यूरो के डॉक्टर हैं, न हार्ट के डॉक्टर हैं, न नेफ्रो के डॉक्टर हैं, न वहां पर जनरल फिजिशियन के डॉक्टर हैं । महोदय, वहां सदर अस्पताल में सिर्फ डॉक्टर जो है रेफर लिखना जानते हैं महोदय। अगर उत्तर प्रदेश का बनारस बी0एच0यू0 और ट्रामा सेंटर आज हमारे जिले और बिहार के बगल के जिले के लोगों का इलाज बंद कर दे, तो बहुत से गरीब जो है इलाज के अभाव में महोदय मर जाएंगे ।

अभी वर्तमान में बनारस का ट्रामा सेंटर अस्पताल जो है बिहार के, आपके मरीजों का जो आयुष्मान कार्ड है उस पर इलाज करना बंद कर दिया है क्योंकि उनका कहना है कि बिहार के लगभग 8 करोड़ रुपये बकाया है, बाकी है, इसलिए उन्होंने आयुष्मान कार्ड पर इलाज करना बंद कर दिया है।

महोदय, शिक्षा की बात हो रही है । चार जिले शाहाबाद में आरा, बक्सर, रोहतास, कैमूर में एक मात्र विश्वविद्यालय है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय । जिसके तहत महोदय अंगीभूत और संबद्ध मिलाकर 84 कॉलेज हैं । आज भी स्नातक की पढ़ाई में चार साल लगते हैं, तीन वर्षों के बदले चार साल लगते हैं । जिससे एक वर्ष का नुकसान छात्रों को होता है ।

उपाध्यक्ष : अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : महोदय, जब तक हर प्रखंड में महाविद्यालय के साथ–साथ हर जिले में महोदय विश्वविद्यालय की जब तक स्थापना नहीं होगी ।

उपाध्यक्ष : आप कृपया बैठ जाएं ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : धन्यवाद महोदय । समय हमारा कम है, हम अपनी पार्टी से सिंगल हैं । एक मिनट का समय मिलता है हम लोग अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं । महोदय, हम लोगों ने सर्वदलीय बैठक में भी कहा था कि हम लोगों का समय बढ़ाया जाए ताकि हम लोग अपनी सदन में बातों को रख सकें। धन्यवाद महोदय ।

टर्न–20 / हेमन्त / 03.02.2026

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता जी। माननीय सदस्य, आपके पास एक मिनट का वक्त है।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, सांस लेने और सांस छोड़ने भर का वक्त है। महोदय, मैंने माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण को भी सुना और यहां के लोगों के अभिभाषण को भी सुन रहा था और बैठे–बैठे यह सोच रहा था कि काम करते हैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और धन्यवाद दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी को सभी मिलकर, तो यह समझ में नहीं आया मुझे। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय भी खुलना चाहिए बिहार में। महोदय, बहुत सारे काम हुए हैं। मैं एक पॉजिटिव एप्रोच लेकर चलता हूं। आपने 27 मेडिकल

कॉलेज खोलने की बात कही है, यह सरकार ने बढ़िया काम किया है, लेकिन पिछले दो–तीन वर्ष से सहरसा में अभी तक लैंड एक्वीजिशन नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ, अभी तक नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

जी, अगर हो गया तो बहुत–बहुत धन्यवाद सर कि खुलेगा और इंजीनियरिंग कॉलेज आपने खोला हर एक जिला में, यह भी एक बढ़िया कदम है। हम लोग ट्रेन भर–भर के जाते थे इंजीनियर बनने और पैसा देते थे, बहुत अच्छा कदम है। लेकिन सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज में जमीन नहीं होने की वजह से न हॉस्टल बन पा रहा है, न एम.टेक की पढ़ाई हो पा रही है। आप थोड़ा सा देखें, सदन का ध्यान मैं उधर ले जाना चाहता हूँ कि अगर इंजीनियरिंग कॉलेज को जमीन मुहैया करा दी जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत–बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती ज्योति देवी जी। आपके पास में पांच मिनट का वक्त है।

श्रीमती ज्योति देवी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं बाराचट्टी की देवतुल्य जनता को आभार, हम पार्टी के संरक्षक को धन्यवाद, यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदय आरिफ मोहम्मद खान जी द्वारा प्रस्तुत की गई सारगर्भित, दूरदर्शी और तथ्यात्मक अभिभाषण के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण केवल औपचारिक वक्तव्य नहीं बल्कि बिहार के वर्तमान, भविष्य और संभावनाओं का एक स्पष्ट और मजबूत रोडमैप है। इसमें राज्य सरकार की अब तक की उपलब्धियां भी हैं और आने वाले वर्षों के लिए विकास का ठोस खाका भी। यह अभिभाषण सामाजिक न्याय, आर्थिक प्रगति, सुशासन, महिला सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण और समावेशी विकास की स्पष्ट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने यह अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा की है कि आगामी 5 वर्षों में राज्य में 1 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। यह लक्ष्य अपने आप में ऐतिहासिक है। इसके अंतर्गत सरकारी नियुक्तियां, निजी क्षेत्र में रोजगार, स्टार्टअप, कुटीर उद्योग, लघु एवं मध्यम उद्योग तथा स्वरोजगार को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। यह हम सभी जानते हैं कि बिहार युवा राज्य है और जब युवा आत्मनिर्भर होंगे, तभी राज्य आत्मनिर्भर बनेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते विशेष रूप से यह कहना चाहती हूँ कि इस अभिभाषण में महिला सशक्तिकरण को विकास के केंद्र में रखा गया है। राज्य में जीविका योजना के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत हुई हैं। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत महिलाओं को दो लाख तक की

आर्थिक सहायता देकर उन्हें व्यवसाय के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण तथा पंचायती राज एवं शहरी निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें नेतृत्व की मुख्यधारा में लाया गया है। यह केवल योजनाएं नहीं हैं, यह समाज की सोच बदलने की ऐतिहासिक पहल है।

माननीय राज्यपाल महोदय ने शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य की उपलब्धियों का उल्लेख किया है। विद्यालयों के आधारभूत ढांचे में सुधार, डिजिटल शिक्षा का विस्तार, छात्रवृत्ति योजनाएं, साइकिल, पोशाक, पुस्तक सहायता जैसी योजनाओं से लाखों गरीब बच्चों ने शिक्षा की मुख्यधारा में प्रवेश किया है। उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देकर राज्य के युवाओं को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा रहा है। हर जिले में इंजिनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल चुका है। बच्चे प्रतिस्पर्धी पढ़ाई आसानी से पढ़ रहे हैं।

महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के तहत लाखों गरीब परिवारों को 5 लाख रूपये का मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर इलाज संभव हुआ है। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में आई गिरावट राज्य की संवेदनशील स्वास्थ्य नीति का प्रमाण है।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, एक मिनट का समय है आपके पास।

श्रीमती ज्योति देवी : पीएमसीएच को 5400 बेड, आईजीआईएमएस को 3000 बेड एवं अन्य अस्पतालों को 2000 बेड का बनाया जा रहा है, जो ऐतिहासिक कदम है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के क्षेत्र में भी बहुत काम हुआ है और काफी बढ़ोतरी इससे किसानों की हुई है। अंत में मैं यही कहना चाहती हूं कि बढ़ते बिहार के लिए हमारी पार्टी, हमारे लोग पूरी मुस्तैदी के साथ माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं और बेहतर विकास के लिए हम उनकी मदद करेंगे। माननीय महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहती हूं कि पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह खुले हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि गया जिला में एक एम.टेक की बहाली हुई है 3 साल से, गया का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें एम.टेक की पढ़ाई नहीं हो रही है, वहाँ शिक्षकों को स्थापित करने की कृपा की जाए।

उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें माननीय सदस्या।

श्रीमती ज्योति देवी : आपने समय दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती बेबी कुमारी।

श्रीमती बेबी कुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के प्रति आभार

प्रकट करती हूँ कि आज मुझे सदन में बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी की दूरदर्शिता के अटूट संकल्प से बिहार विकसित बिहार की ओर कदम बढ़ा रहा है।

आदरणीय रामविलास पासवान जी की विचारधारा के साथ ''बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट'' के संकल्प को मजबूत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) दृढ़ता के साथ इस सरकार के साथ खड़ी है। महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि विकास की गति के साथ–साथ सामाजिक न्याय की गहराई भी बढ़े। विशेष रूप से दलित, महादलित, अतिपिछड़ा और अत्यंत गरीब परिवारों तक योजनाओं की पहुंच की निगरानी एलजेपी(आर) की प्राथमिकता होगी। महोदय, छात्रावास, छात्रवृत्ति, कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार से वंचित वर्गों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए पार्टी अहम भूमिका निभायेगी। महोदय, आज हमारी एनडीए सरकार की जो योजना चल रही है। हमारी एनडीए सरकार जो कहती है, वह करती है। आपको मैं बता दूं कि एक समय था कि वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, जो 400 थी, आज हमारी सरकार ने उसे 1100 रूपये कर दिया है। सरकारी भर्तियों के साथ–साथ अब निजी निवेश आधारित रोजगार सृजन को और तेज किया जाना चाहिए। एमएसएमई, लघु उद्योग और स्टार्टअप के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करने पर एलजेपी (आर) विशेष बल देगी। शहरी गरीबों, प्रवासी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए लक्षित कल्याण योजनाओं को और सुदृढ़ किया जायेगा।

(क्रमशः)

टर्न–21 / संगीता / 03.02.2026

श्रीमती बेबी कुमारी (क्रमशः) : अध्यक्ष महोदय, झुग्गी–बस्ती क्षेत्रों में आवास, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा । सात निश्चय–3 के केंद्र में केवल विकास नहीं बल्कि गरिमा, सम्मान, अवसर और सामाजिक संतुलन होना चाहिए । प्रत्येक निश्चय में वंचित वर्गों के लिए स्पष्ट प्राथमिकता सुनिश्चित की जाएगी । यह गठबंधन केवल पिछली उपलब्धियों का साझीदार नहीं बल्कि अगले चरण के सुधारों का सह–निर्माता है । आने वाले वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार में गुणवत्ता सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । केंद्र सरकार की नीतियां, राज्य सरकार का क्रियान्वयन और एन0डी0ए0 सहयोगी दलों का सामाजिक आधार तीनों मिलकर बिहार के विकास को नई ऊंचाइयां देंगे । एल0जे0पी0आर0 इस समन्वय को जमीनी स्तर तक मजबूत करेगी । कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है फिर भी कुछ सेक्टरों में और तेजी लाने की आवश्यकता है और सरकार इस दिशा में प्रतिबद्ध है । सुधार

की नियंत्रण प्रक्रिया ही सुशासन की पहचान है । योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे इसके लिए पार्टी कार्यकर्ता सेतु की भूमिका निभाएगी । फिडबैक सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा । आदरणीय रामविलास पासवान जी का सपना था कि शासन का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे । एल0जे0पी0आर0 उसी भावना के साथ इस सरकार में सक्रिय भूमिका निभाएगी । हम इस सरकार के समर्थन में ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय को मजबूत करने वाली साझीदार हैं...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्रीमती बेबी कुमारी : एक मिनट सर । लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक पद्मभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जीवनभर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को अधिकार और सम्मान के लिए संघर्ष किया...

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

आज एन0डी0ए0 सरकार की नीति में उसी विचारधारा की झलक दिखाई देती है, जहां विकास को सामाजिक न्याय से जोड़ा जाए । मैं अपने बोचहां विधान सभा की महान मतदाताओं की तरफ से मैं सदन को धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूं और मैं कहना चाहती हूं कि सभी जगह जो काम चल रही है हमारी सरकार काफी आगे बढ़कर चल रही है । एक समय था कि 2005 से पहले भी आपने देखा होगा और अभी भी देखा है, महिलाओं को सम्मान देने का काम कौन किया तो एन0डी0ए0 सरकार ने किया । मैं आसन के प्रति आभार प्रकट करती हूं और अध्यक्ष महोदय जी को धन्यवाद देती हूं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूं कि आज मुझे सदन में बोलने का मौका दिया । बहुत–बहुत धन्यवाद, जय बोचहां, जय बिहार ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, अपना पक्ष रखें ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आदरणीय सदस्य श्री संजय सरावगी जी द्वारा लाए गए प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । सबसे पहले मैं अपनी कल्याणपुर की महान जनता सहित आसन और अपने नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी, श्री नीतीश कुमार जी, श्री सम्राट चौधरी जी और श्री विजय सिन्हा जी सहित इस सदन के सभी बहनों और भाइयों का धन्यवाद करता हूं आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । महोदय, चूंकि समय कम है और मैं आंकड़ों के खेल में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि यह सरकार जो 2005 के बाद आयी और उसके पहले की जो सरकार थी, कुछ घटनाएं मैं स्मरण दिलाना चाह रहा हूं इस सदन को, तब कानून व्यवस्था की स्थिति यह थी कि बड़े–बड़े नरसंहार– तिस्वारा, तिसखोरा,

लक्ष्मणपुर बाथे, शंकर बिगहा, अफसर जैसे नरसंहार हुआ करते थे और कई लोग सैंकड़ों की संख्या में लोग मारे जाते थे किसी की सुध लेने वाला कोई नहीं था और आज की सरकार जब से यह सरकार बनी ऐसा कोई उदाहरण बिहार में नहीं मिलता है जब इस प्रकार की कोई घटना घटित हो । महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं इस सदन को 2011 का वह समय था जब नक्सली पूरे बिहार में उपद्रव मचा रहे थे । केशरिया थाना क्षेत्र के दरमाहा में पुलिस एनकाउंटर में 9 नक्सली मारे गए थे । बिहार सरकार को भारत सरकार ने भी उपलब्धियों के लिए पीठ थपथपाया था कि बिहार सरकार की शासन व्यवस्था अच्छा काम कर रही है । किसी भी क्षेत्र में आप देख लें, पहले में और आज में कितना अंतर है, पहले हॉस्पिटल में कुत्ते और गाय घूमा करते थे और आज हजारों की संख्या में मरीज जा रहे हैं, दवाई दी जा रही हैं । सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम हमलोग सुनते रह गए हमलोगों के मन में भी जिज्ञासा थी कि कभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारे बाप–दादा भी एडमीशन करायेंगे हमलोग भी ऊंची और अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे लेकिन मौका नहीं मिला । बिहार में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी काम कर रही है, कृषि विश्वविद्यालय काम कर रहा है और इस प्रकार की कई संस्थाएं, सैकड़ों संस्थाएं बिहार में काम कर रही हैं । कानून व्यवस्था की स्थिति यह है आज कि मैं बताना चाहूंगा कि अपने विधान सभा क्षेत्र कल्याणपुर में कानून व्यवस्था के चलते पर्यटकों के चलते और श्रद्धालुओं के चलते दुनिया का सबसे बड़ा हिन्दू मंदिर विराट रामायण मंदिर बन रहा है और मैं बताना चाहूंगा आपको जानकारी देना चाहूंगा इस सदन को कि पिछले 17 जनवरी को जब दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना जो 33 फीट ऊंचा और 33 फीट मोटा शिवलिंग स्थापित हो रहा था तो इस सदन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय विजय सिन्हा सहित इस राज्य के सभी बड़े–बड़े पदाधिकारी वरिष्ठ और कनीय लोग वहां मौजूद थे और आज हजारों की संख्या में प्रतिदिन पर्यटक वहां दर्शन करने आ रहे हैं, श्रद्धालु वहां पूजा–अर्चना करने आ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि बिहार प्रगति के रास्ते पर है और किसी के मन में भी यह भय नहीं है, किसी के मन में भी यह संशय नहीं है कि वहां पर किसी प्रकार का कोई असामाजिक तत्व हमारे साथ कोई घटना घटा सकता है इसलिए मैं सदन के माननीय सदस्यों को भी कहूंगा कि आपको भी कभी मौका मिले तो आप चलिए हमारे तरफ हमारे पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर विधान सभा के कल्याणपुर ब्लॉक के कैथवलिया में, चलकर देखिए इस दुनिया में अब नहीं हैं लेकिन श्रद्धेय किशोर कुणाल जी ने हनुमान मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से जो स्थापना की है वह आने वाले समय में कितना बड़ा चीज बनने वाला है । महोदय, उद्योग की बात हो रही है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि पिछले सदन में मैं सदस्य नहीं था लेकिन उसके पहले मैं था, भारत सरकार के सहयोग से मेरे क्षेत्र में मदर डेयरी

जैसा प्लांट लगा हुआ है । आज उससे 70 हजार परिवारों को किसी न किसी प्रकार का रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, अच्छा उत्पाद की प्राप्ति हो रही है और पुनः उस फैक्ट्री का एक्सटेंशन होने जा रहा है, 15 से 20 दिनों के अंदर एक बड़ी फैक्ट्री उसी के साथ–साथ लगने जा रही है जिसमें सैकड़ों प्रकार के उत्पाद का उत्पादन होगा और हमलोगों को एक अच्छा और बेहतर उत्पाद प्राप्त होगा, यही स्थिति है उद्योग के क्षेत्र का । अन्न भी, हम देखते थे जब उधर से आते हैं हम जब मोतिहारी की तरफ से अपने कल्याणपुर चकिया की तरफ से चलते हैं तो देख रहे हैं मोतिपुर के पास हजारों एकड़ जमीन उद्योग के लिए अधिगृहित करके और कई कंपनियों को दिया जा रहा है, कई लोग उद्योग लगा रहे हैं । बातें बहुत सारी होती हैं हमारे सदन के जो माननीय सदस्य हैं कई बार कई प्रकार की बातें करते हैं कि बिहार में यह नहीं हो रहा है बिहार में वह नहीं हो रहा है लेकिन मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से यह जानना चाहता हूं और उनसे पूछना भी चाहता हूं कि भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं, बिहार सरकार की जितनी योजनाएं हैं चाहे राशन की योजना हो चाहे फ्री में बिजली की योजना हो 5 लाख रूपये का आयुष्मान कार्ड हो या इस प्रकार की कोई भी योजना हो, विपक्ष के कोई माननीय सदस्य कह दें कि मैंने अपने क्षेत्र में एक आदमी को भी कहा है कि यह योजना मत लीजिए...

अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हुआ । कृपया बैठ जाएं ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : यह भारत सरकार की नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की योजना है मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा एक भी सदस्य ऐसा बता दें कोई कि अपने क्षेत्र में किसी भी जनता को...

अध्यक्ष : कृपया बैठ जाएं, आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : किसी भी उपभोक्ता को कहा है कि आप 5 किलो राशन मत लीजिए आप बिजली मत लीजिए आप इस प्रकार की किसी योजना का लाभ मत उठाइए । महोदय, चूंकि समय कम है कम था आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, पुनः मैं आपके प्रति इस सदन के प्रति और पूरे बिहार के प्रति पूरे बिहार के भाइयों और बहनों के प्रति बहुत–बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं । जय हिन्द, जय बिहार ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद–विवाद दिनांक–05 फरवरी, 2026 को भी जारी रहेगा ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–03 फरवरी, 2026 के लिए स्वीकृत निवेदनों की संख्या–3 है । अतः सदन की सहमति हो तो संबंधित विभाग को भेज दिया जाएगा ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की कार्यवाही बृहस्पतिवार, दिनांक–05 फरवरी, 2026 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।